चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

26 जनवरी–01 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

दिल्ली विधानसभा चुनाव

भाजपा की अग्निपरीक्षा

फोटो – प्रभात पाण्डेय

महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने वाली भाजपा का विजय रथ दिल्ली आकर ठिठक-सा गया है. ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की चमक धुंधली पड़ने लगी, बल्कि वजह यह है कि दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी अरविंद केजरीवाल का मुरीद है. इसलिए दिल्ली का चुनाव भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है. वहीं 49 दिनों में अपनी सरकार छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने और उसमें जबरदस्त पराजय का मुंह देखने वाले केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए भी यह चुनाव जीवन-मरण का सवाल बनकर सामने खड़ा है. कैसे? यही बता रही है, इस बार की कवर स्टोरी...

मनीष कुमार

दिल्ली विधानसभा चुनाव का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है. यह चुनाव एक सस्पेंस थ्रिलर सिनेमा की तरह बन गया है. चुनाव कौन जीतेगा, सरकार कौन बनाएगा, इस बारे में वोटों की गिनती के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. वजह यह कि इस चुनाव में हर पार्टी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो और यहां तक कि निर्दलीय उम्मीदवारों का अहम रोल है, सभी का महत्व है. इन सभी का चुनाव नतीजों पर दखल रहेगा, क्योंकि इनमें से कोई जीतेगा, कोई जिताएगा, तो कोई किसी की लुटिया डुबोएगा. मतलब यह कि हर सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है.

मजेदार बात यह है कि दिल्ली पूरी तरह से एक राज्य भी नहीं है. यहां के मुख्यमंत्री के पास किसी बड़े शहर के मेयर जैसी शक्ति है. दिल्ली सरकार की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वह किसी बड़े अधिकारी का तबादला कर सके. एक पुलिस इंस्पेक्टर को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को अनशन करना पड़ता है. लेकिन चुनाव का माहौल ऐसा बन चुका है, जैसे यह पूरे देश का चुनाव हो. टीवी पर न सिर्फ़ प्रचार हो रहा है, बल्कि हर चैनल के प्राइम टाइम में इसे बढ़-चढ़ कर दिखाया जा रहा है. एफएम रेडियो पर हर पांच मिनट में प्रचार सुनाई देता है. अख़बारों और पत्रिकाओं में ख़बरों के साथ-साथ लेखों की भरमार है. इंटरनेट पर तो और भी बुरा हाल है. सोशल मीडिया में तो ऐसा लग रहा है, जैसे दिल्ली चुनाव के अलावा दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है. कहने का मतलब यह कि दिल्ली चुनाव हर तरफ़ छाया हुआ है. इसकी दो मूल वजहें हैं. एक तो यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है और दूसरी तरफ़ यह चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले प्रचार शुरू किया. जब दूसरी पार्टियों में चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं थी, तब आम आदमी पार्टी का प्रचार-प्रसार दिल्ली में शुरू हो चुका था. पार्टी ने दिल्ली डायलॉग और मुहल्ला सभा जैसे कार्यक्रम कर जनता से जुड़ने का काम भी जोर-शोर से किया. चुनाव की घोषणा से पहले ही पार्टी सभी 70 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी थी. दिल्ली की सड़कों पर होर्डिंग्स की भरमार के साथ-साथ रेडियो पर लगातार केजरीवाल प्रचार कर रहे थे. कहने का मतलब यह कि आम आदमी पार्टी शुरुआती लीड ले चुकी थी. इस बार केजरीवाल जन-लोकपाल और स्वराज जैसे मुद्दे दरकिनार कर मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी पार्टी का जोर पिछले चुनाव से कम है. महिला सुरक्षा को लेकर पार्टी महिलाओं को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है. पार्टी का प्रचार, केजरीवाल की भाषा और प्रवक्ताओं का अंदाज़ पिछले चुनाव से ज़्यादा परिपक्व नज़र आ रहा है. इसके अलावा पार्टी यह संदेश देना चाह रही है कि 49 दिनों की सरकार के दौरान केजरीवाल ने अपने वादे पूरे किए. अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए केजरीवाल यह दावा कर रहे हैं कि उस दौरान दिल्ली में भ्रष्टाचार में कमी आई थी. साथ ही आरोप लगाकर विरोधियों को ललकारने की रणनीति आम आदमी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है.

दिल्ली में केजरीवाल का जादू बरकरार है. झुग्गी-झोंपड़ी, निम्न आय वर्ग, खासकर ऑटो वालों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों का समर्थन केजरीवाल के प्रति बरकरार है, क्योंकि वे इस बात को मानते हैं कि केजरीवाल सरकार के दौरान पुलिस ने तंग करना बंद कर दिया था. केजरीवाल का यह दावा भी सही है कि उनकी 49 दिनों की सरकार के दौरान घूसखोरी में कमी आई थी.

पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने बिजली के बिल को बड़ा मुद्दा बनाया था. पार्टी का मानना है कि दिल्ली में जो बिजली के मीटर हैं, वे तेज चलते हैं. इस मुद्दे पर पिछली बार आम आदमी पार्टी को बहुत समर्थन मिला था. इस बार केजरीवाल ने दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और महासचिव आशीष सूद पर दिल्ली में बिजली के मीटर सप्लाई करने और लगाने का आरोप लगाया. केजरीवाल दरअसल यह साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में तेज चलने वाले बिजली के खराब मीटर भाजपा ने लगवाए थे. यह मामला इतना गरमा गया कि सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल के ख़िलाफ़ चुनाव आयोग में शिकायत की और अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया. सच्चाई यह है कि केजरीवाल के आरोपों में आधा सच और आधा झूठ है. केजरीवाल ने जो छह कंपनियां सतीश उपाध्याय और आशीष सूद की बताईं, उनमें से दो कंपनियां मौजूद ही नहीं हैं. ये दोनों कंपनियां वे हैं, जिनके बारे में केजरीवाल ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों में सबसे ज़्यादा कारोबार हुआ. चुनौती देने के बावजूद केजरीवाल कोई सुबूत नहीं पेश कर सके. सच्चाई यह भी है कि उक्त छह कंपनियों में से एक कंपनी दिल्ली में रिलायंस की बिजली कंपनी के साथ कारोबार करती थी. समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय और आशीष सूद की कंपनियों पर बिजली कंपनी के साथ काम करने की बात कही थी, किसी गड़बड़ी या घोटाले का आरोप नहीं लगाया था. उन्होंने बिजली के मीटर का मुद्दा उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की और इसमें वह सफल भी हो गए.

भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों को यह बात भलीभांति समझ में आ गई कि दिल्ली का चुनाव दूसरे राज्यों से अलग है. उन्हें समझ में आ गया कि दिल्ली में केजरीवाल की चुनौती से निपटने के लिए उन्हें एक चेहरा पेश करना होगा. एक ऐसा चेहरा, जो केजरीवाल से हर लिहाज से मजबूत हो.

दिल्ली में केजरीवाल का जादू बरकरार है. झुग्गी-झोंपड़ी, निम्न आय वर्ग, खासकर ऑटो वालों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों का समर्थन केजरीवाल के प्रति बरकरार है, क्योंकि वे इस बात को मानते हैं कि केजरीवाल सरकार के दौरान पुलिस ने तंग करना बंद कर दिया था. केजरीवाल का यह दावा भी सही है कि उनकी 49 दिनों की सरकार के दौरान घूसखोरी में कमी आई थी. इसका फ़ायदा केजरीवाल को ज़रूर मिलेगा. इसके अलावा, दिल्ली में मुसलमानों का झुकाव भी आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ा है. इसकी वजह कांग्रेस का घटता वर्चस्व है. मुसलमानों को लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भाजपा का विजय रथ रोकने में असमर्थ है. उन्हें विश्वास है कि केजरीवाल भाजपा को दिल्ली में चारों खाने चित कर सकते हैं, इसलिए टैक्टिकल वोटिंग के तहत मुसलमान बड़ी संख्या में केजरीवाल को वोट करेंगे. स्थिति इस कदर पक्ष में (फेवरेबल सिचुएशन) होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित नहीं है. इसके कई कारण हैं. 49 दिनों में दिल्ली छोड़कर वाराणसी जाने से लोग नाराज़ हैं. उन्हें लगता है कि केजरीवाल भी दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरह महत्वाकांक्षी हैं. एक वर्ग को लगता है कि केजरीवाल झूठे हैं. उसका मानना है कि केजरीवाल को वादा करके मुकर जाने की आदत है. केजरीवाल को भी लोगों की इस नाराज़गी का साफ़-साफ़ अंदाज़ा है. उन्हें पता है कि उन पर भगोड़ा होने का आरोप है.

यही वजह है कि केजरीवाल ने जबसे चुनाव प्रचार शुरू किया है, वह हर जगह माफी मांग रहे हैं और लोगों से यह वादा कर रहे हैं कि अब किसी भी क़ीमत पर दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे. केजरीवाल की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बार 35 ऐसे नेताओं को टिकट नहीं मिले, जो पिछली

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दिल्ली विधान सभा चुनाव असमंजस में युवा मुस्लिम मतदाता

पेज-03

कांग्रेस और आप के बीच फंसे मुस्लिम मतदाता

पेज-04

किसमें कितना है दम

पेज-15

साई की महिमा

पेज-12

दिल्ली विधानसभा चुनाव : भाजपा की अग्निपरीक्षा

पृष्ठ एक का शेष

बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी ने बिना कार्यकर्ताओं और जनता की राय लिए उम्मीदवार चुने हैं. उन्हें लगता है कि इस बार केजरीवाल ने उन्हीं लोगों को टिकट देना ज़्यादा उचित समझा, जिनके पास पैसा है. केजरीवाल और कार्यकर्ताओं के लिए निराशा का विषय यह भी है कि आम आदमी पार्टी के पुराने नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं. अन्ना आंदोलन के समय से जुड़े कार्यकर्ता पार्टी में अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं. वे या तो घर में शांत बैठे हैं या फिर अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी के ख़िलाफ़ प्रचार कर रहे हैं. पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की सफेद टोपी लगाए दिल्ली की सड़कों में नज़र आते थे, लेकिन इस बार पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं. इसकी वजह पार्टी के अंदर का वातावरण है. दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं का आना भी बिल्कुल बंद हो गया है, जबकि पार्टी लगातार उनसे अपील कर रही है कि वे दिल्ली आएं और चुनाव प्रचार में शामिल हों.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी अरविंद केजरीवाल का चेहरा है. पिछले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की छवि एक आंदोलनकारी, ईमानदार और व्यवस्था परिवर्तन करने वाले नेता के रूप में थी. 49 दिनों के शासनकाल और लोकसभा में पार्टी की शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल की लोकप्रियता में कमी आई है. पिछले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल मध्यम वर्ग की नज़रों में हीरो थे, आज वह लोकप्रियता नहीं है. इन सबके बावजूद पार्टी के समर्थकों एवं मतदाताओं के बीच वह एक ईमानदार और विश्वसनीय चेहरा हैं. आम आदमी पार्टी ने इस बार अपनी खूबियों और कमियों का सही अवलोकन करते हुए रणनीति तैयार की है. केजरीवाल लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए मोदी से सीधे मुकाबला करने के पक्ष में नहीं थे. यही वजह है कि पार्टी ने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही यह दलील दी कि मोदी तो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए केजरीवाल का मुकाबला दिल्ली के किसी नेता से है. मोदी से सीधा मुकाबला न हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में भाजपा के जगदीश मुखी के पोस्टर लगाकर कैंपेन करती रही कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल का मुकाबला जगदीश मुखी से है. आम आदमी पार्टी ने बड़ी सफलता के साथ यह संदेश दिया कि केजरीवाल के मुकाबले में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है. भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों को यह बात भलीभांति समझ में आ गई कि दिल्ली का चुनाव दूसरे राज्यों से अलग है. उन्हें समझ में आ गया कि दिल्ली में केजरीवाल की चुनौती से निपटने के लिए उन्हें एक चेहरा पेश करना होगा. एक ऐसा चेहरा, जो केजरीवाल से हर लिहाज से मजबूत हो. एक और वजह यह भी रही कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नतीजों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी. इसलिए उसने मोदी को सीधे केजरीवाल के मुकाबले उतारने की रणनीति पर पुनर्विचार किया. इसमें एक ख़तरा था कि अगर भाजपा बहुमत नहीं ला पाती है, तो मोदी की साख पर विरोधियों को सवाल उठाने का मौक़ा मिल जाएगा. बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी बेअसर हो जाएंगे. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को मैदान में उतार दिया. किरण बेदी विश्वसनीयता, लोकप्रियता, अनुभव और उपलब्धियों के मामले में केजरीवाल से बहुत आगे हैं. दोनों अन्ना हजारे के आंदोलन में भी शामिल थे. वह आंदोलन, जो आम आदमी पार्टी की आत्मा है. किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस हैं, वहीं केजरीवाल एक आयकर अधिकारी. किरण बेदी ने नौकरी में रहते हुए जो उपलब्धियां हासिल कीं, उनके सामने केजरीवाल की उपलब्धि न के बराबर है. किरण बेदी के आने से भाजपा को सबसे बड़ा फ़ायदा यह होने वाला है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का सारा कैंपेन बेअसर हो जाएगा. किरण बेदी के भाजपा में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के कई नाराज़ नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए.

किरण बेदी को चुनाव का चेहरा बनाना भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि किरण बेदी चुनाव प्रचार और लोकप्रियता में केजरीवाल पर भारी हैं. हालांकि, किरण बेदी को इतना महत्व देने की वजह से भाजपा का एक गुट नाराज़ हो गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह पार्टी संगठन पर मोदी और अमित शाह ने शिकंजा कसा है, उसकी वजह से कोई सामने आकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है. भाजपा के पास दिल्ली में केजरीवाल से दो-दो हाथ करने वाला कोई नेता नहीं था, लेकिन पार्टी में मुख्यमंत्री पद के पांच से ज़्यादा दावेदार ज़रूर थे, इसलिए भितरघात की आशंका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन देर से शुरू हुआ. पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव प्रचार चल रहा था. केंद्र में अपनी सरकार होने की वजह से भाजपा को मदद भी मिली. केंद्र सरकार ने दिल्ली की कई अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का फ़ैसला कर दिल्लीवासियों को खुश करने की कोशिश की. केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा को अनुमति देकर भी केजरीवाल के वोट बैंक में डाका डालने का काम किया. इसके अलावा रामलीला मैदान की रैली में मोदी ने दिल्ली के लोगों को कई सपने दिखाए. मोदी ने दिल्ली में 2022 तक झुग्गियां ख़त्म करने का आश्वासन दिया. साथ ही बिजली और पानी की सुविधाएं बेहतर करने का भरोसा दिलाया. इन सबके बावजूद भाजपा को लगा कि दूसरे राज्यों में जिस तरह वह अपने पक्ष में हवा बनाने में सफल रही, वैसा माहौल दिल्ली में नहीं दिख रहा है. यही वजह है कि भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया.

इस बीच दिल्ली की राजनीति में हाशिये पर गई कांग्रेस ने कुछ अच्छे फ़ैसले लिए. कांग्रेस की तरफ़ से अजय माकन को चुनाव प्रचार का चेहरा बनाया गया. साथ ही पार्टी ने दिल्ली के सभी बड़े नेताओं और दिग्गजों को मैदान में उतार दिया. इसी रणनीति के तहत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. कांग्रेस की साख पिछले विधानसभा चुनाव से लगातार ख़त्म होती जा रही थी. पिछली बार पार्टी महज आठ सीटें जीत सकी थी. कांग्रेस को लोगों ने इनोवा पार्टी कहना शुरू कर दिया था. कांग्रेस के सामने साफ़-साफ़ लक्ष्य है. दिल्ली में अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस को अपने खोए हुए वोट बैंक का विश्वास जीतना होगा, झुग्गी-झोंपड़ी वालों और मुसलमानों का विश्वास जीतना होगा. 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की थी. कहने का मतलब यह कि कांग्रेस जितना मजबूत होगी, केजरीवाल की परेशानी उतनी ही बढ़ती जाएगी. कांग्रेस इस बार भी अगर दस का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, तो आने वाले कई चुनावों तक दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बन जाएगी. इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने का फ़ैसला किया है. 2008 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 14 फ़ीसद वोट मिले थे, जबकि 2013 में यह आंकड़ा घटकर पांच फ़ीसद रह गया. बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट केजरीवाल के खाते में जा पहुंचा था. इस बार अगर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति 2008 वाली हो जाती है, तो केजरीवाल को भारी नुक़सान हो जाएगा. इस सबके अलावा इस चुनाव में विभिन्न पार्टियों के बागी उम्मीदवारों का भी रोल काफी अहम है. चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर सीट पर कांटे की टक्कर है, इसलिए बागी उम्मीदवार किस सीट पर किस पार्टी को कितना नुक़सान पहुंचाएंगे, इसका सीधा असर चुनाव नतीजे के फाइनल टैली पर अवश्य दिखाई देगा.

दिल्ली चुनाव केजरीवाल का भविष्य और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तय करेगा. पार्टी अगर हार जाती है, तो केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठेगा और पार्टी में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है. कई नेता जो अलग-अलग व्यवसाय छोड़कर राजनीति में कूदे, उनके पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा. साथ ही देश में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन पर कुठाराघात होगा. जिन लोगों ने अन्ना के आंदोलन में हिस्सा लिया, उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे. आम आदमी पार्टी के बारे में यही कहा जाएगा कि यह सामाजिक आंदोलन का एक ऐसा प्रयोग था, जो विफल हो गया. यह चुनाव नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है. भाजपा अगर हार जाती है, तो उसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव पर पड़ेगा. दिल्ली चुनाव के नतीजे क्या होंगे, यह तो 10 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन इस चुनाव में साम-दाम-दंड-भेद यानी राजनीति के सारे तिकड़म आजमाए जा रहे हैं. हर पार्टी लोक-लुभावन वादे करके, अगर साफ़-साफ़ कहा जाए, तो झूठे सपने दिखाकर वोट झटकने की फिराक में है.

दिल्ली चुनाव में यह होड़ लगी हुई है कि किसकी सरकार किन-किन चीजों को मुफ्त मुहैया कराएगी. किसी भी पार्टी के पास युवाओं के लिए रोज़गार को लेकर कोई योजना नहीं है. हैरानी की बात यह है कि रोज़गार की कोई बात ही नहीं कर रहा है. दिल्ली में असंगठित मज़दूरों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन किसी भी पार्टी या नेता द्वारा इस वर्ग की समस्याएं दूर करने के झूठे वादे भी नहीं किए जा रहे. कभी-कभी लगता है कि नेताओं को इन ग़रीब मज़दूरों की समस्याओं का अंदाज़ा है भी या नहीं. भूमि अधिग्रहण के नए क़ानून से दिल्ली के गांवों की ज़मीनों का क्या होगा, यह बात चुनाव के मुद्दों में शामिल नहीं है. दिल्ली में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं. इन प्रवासियों में जो ग़रीब वर्ग है, उसका शोषण कई तरीकों से दिल्ली शहर में होता है. इसका रिश्ता अपराध से भी है, लेकिन भविष्य के सभी महान मुख्यमंत्रियों ने इन मुद्दों पर एक वाक्य तक नहीं कहा. बिजली-पानी की समस्या के बारे में हर पार्टी वादे कर रही है, लेकिन यह कोई नहीं कह रहा है कि दिल्ली के नीचे यानी भूगर्भ स्थित पानी ज़हरीला हो चुका है. दिल्ली दुनिया का बेहतरीन शहर बने, इसके लिए ज़रूरी है कि यहां रहने वाले लोग खुशहाल हों, युवाओं के पास रोज़गार हो, सबके लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो, सबके पास घर हो, इलाज के लिए सस्ते अस्पताल हों. अफ़सोस इस बात का है कि दिल्ली चुनाव में सिर्फ़ तू-तू, मैं-मैं हो रही है. जनता के सरोकारों और उससे जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज़ करने के मामले में सारी पार्टियां एक जैसी हैं. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 47
दिल्ली, 26 जनवरी-01 फरवरी 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सेठ और खुल्लर की कामयाबी

पिछले साल केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद मची उथल-पुथल के बाद यूपीए सरकार के दौरान मोर्चा संभाल रहे बहुत कम अधिकारी अपनी जगह बचाने में सफल रहे. कैबिनेट सचिव अजीत सेठ इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण हैं. उनके अलावा योजना आयोग की पूर्व सचिव सिंधुश्री खुल्लर बचने वाली दूसरी अधिकारी हैं. 1975 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी खुल्लर को नवगठित नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है. पूर्व पैनल ख़त्म होने के बाद नवगठित संस्थान में जगह पाने वाली वह एकमात्र अधिकारी हैं. लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि सिविल सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यरत अधिकारियों में श्रीमती खुल्लर से सेठ वरिष्ठ हैं. हालांकि, सरकार द्वारा उन्हें बनाए रखने का निर्णय महत्वपूर्ण कसौटी था. उनकी स्थिति विभिन्न मंत्रालयों-विभागों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समन्वय, सहयोग एवं सामंजस्य बनाने वाली है. ऐसे में उनका वरिष्ठ होना फ़ायदेमंद है. उन्हें इस बात का भी फ़ायदा मिलेगा कि खुल्लर की छवि एक दक्ष, कुशल और निर्विवाद आईएएस अधिकारी की है, जो लो-प्रोफाइल में रहती हैं. इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बदलने के बाद भी खुल्लर एवं सेठ जैसे अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं और बाकी वरिष्ठ अधिकारी ऐसा कर पाने में असफल रहे. ■

कूटनीतिक चिंताएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मसलों पर अच्छा-खासा ध्यान केंद्रित किया है. बावजूद इसके, विदेश मंत्रालय में मुख्य राजदूतों की पदस्थापना को लेकर कई महीनों से अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है. इससे निपटते समय विदेश सचिव सुजाता सिंह के सामने एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है. प्रधानमंत्री ने दिल्ली में राजनयिक सेवा के सभी अधिकारियों, जिनमें सभी राजदूत एवं उच्चायुक्त भी शामिल हैं, की एक बैठक बुलाई. लेकिन, सुजाता सिंह के लिए परेशानी यह थी कि आयोजन स्थल पर खाली सीटों से कैसे निपटा जाए. सूत्रों का कहना है कि विदेश सचिव ने 15 राजदूतों की सूची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के सामने रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनका पत्र इस निर्देश के साथ वापस भेजा गया है कि वह सुनिश्चित करें कि सूची में दर्ज नामों के साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा है. ग़ौरतलब है कि पिछली सरकार के समय इस तरह की नियुक्तियां एक नियमित काम था, लेकिन मोदी राज में केवल प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्णय मायने रखता है. और, जब मोदी स्वयं विदेश नीति का परिचालन कर रहे हैं, तो ऐसे में विदेश मंत्री साफ़ तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि यह सूची उनके मंत्रालय को किसी तरह का नुक़सान न पहुंचाए. ■

एक अनोखी वापसी

यह एक अलग तरह की और ग़ैर-विवादास्पद वापसी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के सचिव स्तर के अधिकारियों से कहा है कि वे अपने एकांत कार्यालय छोड़कर उन ज़मीनी जगहों पर जाएं, जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव संजय कोठारी ने एक आदेश जारी करते हुए सभी 93 केंद्रीय सचिवों को अपनी पहली पदस्थापना की जगह का दौरा करने और वहां के ज़मीनी हालात के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है. हालांकि, मोदी ने नवंबर में ही सभी मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों से मुलाकात के दौरान ऐसा किए जाने के संकेत दिए थे. बाबुओं को भेजे जाने का उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन का आकलन और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वांछित प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें एवं सुझाव हासिल करना है. सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने उदाहरण के साथ पहल की है. वह पहले ही आईएएस अधिकारी के रूप में करियर की शुरुआत के स्थान का दौरा कर चुके हैं. निस्संदेह, दूसरे अधिकारी भी इसी तरह की योजना बना रहे हैं. ■

dilipcherian@gmail.com

आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्र एजेंसियों की मदद से बिजली के बढ़ा हुए बिल की जांच करवाकर बिजली के दामों में 50 फीसदी कमी करने और सभी घरों को प्रतिदिन 700 लीटर मुफ्त पानी पहुंचाने का भी वादा किया था. झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए फ्लैट की व्यवस्था और दिल्ली से वीआईपी कल्चर समाप्त करना उनके अन्य प्रमुख वादे थे. दिल्ली के सभी घरों में 700 लीटर मुफ्त पानी पहुंचाने के वादे के क्रम में सरकार बनने के बाद उन्होंने 666 लीटर पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की, लेकिन अरविन्द केजरीवाल के इस्तीफे के बाद इस घोषणा को वापस ले लिया गया.

दिल्ली विधान सभा चुनाव

असमंजस में युवा मुस्लिम मतदाता

वसीम अहमद

7 फरवरी का दिन देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित किया गया है. तारीख़ की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं. हर पार्टी की ओर से जनता को लुभाने के लिए बड़े–बड़े दावे किए रहे हैं. इस बार शिक्षित युवा और नए मतदाताओं के रुझान में बड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है. बहुत से ऐसे घर हैं जहां पारंपरिक रूप से कांग्रेस को वोट दिया जाता था, अब उन्हीं परिवारों के युवा परंपरा से हटकर कांग्रेस से दूर और आम आदमी पार्टी के क़रीब हो रहे हैं. हालांकि इनमें एक छोटा वर्ग ऐसा भी है, जिसका झुकाव भाजपा की ओर है लेकिन सामूहिक रूप से मुस्लिम विद्यार्थी और नए मतदाताओं में से अधिकतर का वोट कांग्रेस और आम आदमी के बीच विभाजित होने की संभावना है, मगर इसी के साथ–साथ यह भी सच है कि मत विभाजन में कांग्रेस हाशिये पर दिखाई देती है. इस सिलसिले में 'चौथी दुनिया' ने दिल्ली के कॉलेज/विश्वविद्यालय और मोहल्लों में जाकर शिक्षित मुस्लिम युवाओं का सर्वे किया तो अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग राय सामने आई.

'आप' के समर्थन में बोलने वाले युवा केजरीवाल को एक अच्छे मुख्यमंत्री की नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर लगाम लग सकती है. वह अपने हर बयान में बिजली, पानी और रेहड़ी वालों की बात करते हैं और इस पर काम करने की क्षमता भी रखते हैं. इस सिलसिले में बल्लीमारान पुरानी दिल्ली की एक 25 वर्षीय लड़की निदा आरिफ़ से 'चौथी दुनिया' ने बात की तो उसने कहा कि इस क्षेत्र का विधायक 1993 से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आता है. इतना लंबा समय किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए काफ़ी होता है लेकिन इस क्षेत्र की बदतर स्थिति सबके सामने है. टूटी हुई सड़कें और गंदगी का ढेर सबके सामने है. इसलिए अब हालात में बदलाव का दावा करने वाली पार्टी 'आप' को अवसर दिया जाना चाहिए. इसी प्रकार पटेल नगर में रहने वाले 20 वर्षीय आतिफ़ ख़ां ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने पहली बार वोट दिया था और मेरा वोट आम आदमी पार्टी को गया था और अब आगामी विधानसभा चुनावों में भी झाड़ू पर ही मुहर लगाउंगा, क्योंकि इसने पूरी दिल्ली में वाईफ़ाई मुफ्त करने का वादा किया है. इसी प्रकार जामिया मिलिया इस्लामिया में एमए कॉमर्स के विद्यार्थी आलिम कौसर अली ने कहा कि एक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें जनता के लिए कुछ करने का हौसला है. ज़ाफ़राबाद के 24 वर्षीय मोहम्मद अनीस पत्राचार कोर्स कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस विधायक को बहुत देख लिया अब आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए. शास्त्री पार्क, शाहदरा के मोहम्मद शमीम ने कहा कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवार इस क्षेत्र से बड़ी संख्या से जीत प्राप्त करते थे लेकिन इस बार उसे 'आप' का ज़बरदस्त झटका लगा क्योंकि नया वोटर कांग्रेस से नाराज़ है.

कुछ युवाओं ने कांग्रेस को सबसे बेहतर पार्टी बताया. हालांकि ऐसे युवाओं में बहुतों ने इस बात का भी इशारा दिया कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनना कठिन लगता है लेकिन यह पार्टी बहुत पुरानी है और इसके पास दिल्ली में सत्ता का अनुभव है. इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानी जाती है, इसलिए इसकी सरकार बने तो सब चैन से रहेंगे. इस सिलसिले में रंजीत नगर के पत्रकारिता के विद्यार्थी अज़ल जैदी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा चुनावों में पहली बार वोट पोल किया था और अब दिल्ली विधानसभा के चुनावों के लिए भी पहली बार मताधिकार का प्रयोग करूंगा. मैं किसे वोट दूं, इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सका हूं, लेकिन हालत यह है कि जब से दिल्ली से कांग्रेस की शीला सरकार की विदाई हुई है, तब से हमारी कॉलोनी रंजीत नगर में बिजली, पानी की हालत बहुत ख़राब हो गई है. पीने वाला पानी तो अब हमारी कॉलोनी में आता ही नहीं है, जबकि कांग्रेस की सरकार में 24 घंटे बिजली आती थी और पानी भी आता था. पिछले विधानसभा चुनावों में हमारे क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की वीना आनंद जीती थीं, लेकिन उन्होंने हमारी कॉलोनी के लिए कोई काम नहीं किया. ऐसी परिस्थितियों में आप ही बताइये कि मैं किसे वोट दूं?. अतएव रास्ता केवल कांग्रेस का ही बचता है.

जामिया में एमएससी के विद्यार्थी मोहम्मद आमिर का कहना है कि भाजपा के पास योजनाएं तो हैं और उसके पास मज़बूत नेता भी हैं लेकिन इस पार्टी की परेशानी यह है कि इसकी सरकार बनने के बाद ही हिन्दुत्व की विचारधारा रखने वाले संगठनों के हौसले बुलंद हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर यही है कि कांग्रेस को ही दिल्ली में आना चाहिए ताकि आम आदमी कम से कम शांतिपूर्वक अपना काम तो कर सके लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कोशिश होगी कि कांग्रेस उम्मीदवार ही जीते ताकि विधानसभा में धर्मनिरपेक्ष पार्टी का मज़बूत प्रतिनिधित्व हो.

शिक्षित मुस्लिम युवाओं का एक छोटा सा वर्ग आने वाले चुनावों में दिल्ली में भाजपा की सरकार देखना चाहता है. इन युवाओं का कहना है कि दिल्ली की सरकार को केन्द्र से जुड़कर रहना चाहिए क्योंकि यहां की सरकार को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो अन्य राज्यों को हैं. उदाहरणस्वरूप पुलिस विभाग को ही लीजिए. पुलिस दिल्ली सरकार के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिए अगर दिल्ली में उस पार्टी की सरकार हो, जिसकी केन्द्र में है तो ऐसी स्थिति में तालमेल बैठाने और स्कीमों को लागू करने में आसानी होगी. दूसरी बात यह है कि भाजपा के पास शिक्षा और रोज़गार के लिए ठोस योजनाएं हैं. अगर इसकी सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में एक तो हमें उच्च शिक्षा के लिए सुविधा मिलेगी और दूसरा यह कि शिक्षा पूरी होने के बाद नौकरी हासिल करना आसान होगा. उधर बल्लीमारान के एक नौजवान मोहम्मद साज़िद का कहना है कि हमारे पिता पुराने कांग्रेसी हैं लेकिन हमने पिछली बार परंपरा को तोड़ते हुए केजरीवाल को वोट दिया था, यह सोचकर कि यह कुछ परिवर्तन करेंगे लेकिन वह 49 दिन में ही भाग गए. इस बार भाजपा को वोट देंगे ताकि भाजपा का मुसलमानों पर विश्वास बहाल हो और दूसरी बात यह कि मोदी ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जिससे लगता है कि वह काम करने वाले नेता हैं, तो इस बार भाजपा की सरकार बननी चाहिए.

युवाओं में एक वर्ग ऐसा भी नज़र आया जो केजरीवाल से केवल इसलिए नाराज़ है कि उनकी पार्टी ने पिछले 49 दिनों की सरकार में कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे पता चले कि वह मुसलमानों के हमदर्द हैं. इन युवाओं का कहना है कि जब 'आप' भी भाजपा की तरह ही सोचती है तो फिर बेहतर यह है कि भाजपा को ही दिल्ली की सरकार दी जाए ताकि कम से कम केन्द्र से तालमेल तो बना रहे. दूसरी ओर इन्द्रलोक में रहने वाले मोहम्मद इमरान का कहना है कि कांग्रेस में सरकार बनाने का दम नहीं है और केजरीवाल पिछली बार सरकार छोड़कर भाग गए थे और जितने भी दिन रहे, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए इस बार राजधानी में मज़बूत सरकार लाने की आवश्यकता है और मज़बूत सरकार भाजपा ही दे सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली विधानसभा चुनाव

चुनावी वादे केवल वादे

शफ़ीक आलम

साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था. लेकिन उसने साफ तौर पर 15 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ कांग्रेस पार्टी को पूरीतरह नकार दिया था. उन चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद ऐसी स्थितियां निर्मित हुईं कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करने की स्थिति में नहीं थी. अंततः कांग्रेस के समर्थन से पहली बार चुनावी समर में उतरी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई. आप की सरकार केवल 49 दिनों तक चल सकी. एक साल के लम्बे इंतज़ार के बाद आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई. दिल्ली की राजनीति में दखल रखने वाली तीन प्रमुख पार्टियां आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने–सामने हैं. मतदाताओं को लुभाने के लिए इन पार्टियों के चुनावी वादे एक बार फिर जनता के सामने हैं. अब यह सवाल उठाना लाज़मी है कि पिछले चुनावों में इन पार्टियों ने जनता से जो वायदे किये थे उनका क्या हुआ? क्या चुनावी वादे केवल वोट हासिल करने के लिए किए जाते हैं? क्या चुनाव के नतीजे आने के बाद उनका कोई मायने–मतलब नहीं रह जाता है?

सबसे पहले आम आदमी पार्टी के वादों पर नज़र डालते हैं. जो पिछले चुनाव में कई लोक लुभावन घोषणाओं के साथ मैदान में उतरी थी. चूंकि यह पार्टी अन्ना हजारे के जनलोकपाल आंदोलन की वजह से वजूद में आई थी इसलिए उसने प्रमुखता से दिल्ली अन्ना वाला जनलोकपाल क़ानून (जो मसौदा उन्होंने तैयार किया था) बनाने का वादा किया था. पार्टी के घोषणा–पत्र में कहा गया था कि सत्ता में आने के 15 दिन के अंदर विधानसभा के खुले सत्र में इस क़ानून को पारित किया जायेगा. साथ ही पार्टी के नागरिक सुरक्षा फोर्स, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शीघ्र न्याय दिलवाने का वादा किया गया था. यह दोनों वादे ऐसे थे जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर के थे. आप जिस जनलोकपाल क़ानून को पारित करने की बात कर रही थी वह देश की संसद के अधिकार क्षेत्र में था, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होती है. इसमें दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती थी. लिहाज़ा ये दोनों घोषणायें महज़ घोषणायें ही थीं. आम आदमी सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का धरना और उनके क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती का एक रिहायशी इलाके में छापेमारी इन्हीं घोषणाओं से प्रेरित मालूम होते हैं. बाद में जनलोकपाल के मसले पर केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. दिलचस्प बात यह है कि जनलोकपाल इसबार पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है.

आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्र एजेंसियों की मदद से बिजली के बढ़ा हुए बिल की जांच करवाकर बिजली के दामों में 50 फीसदी कमी करने और सभी घरों को प्रतिदिन 700 लीटर मुफ्त पानी पहुंचाने का भी वादा किया था. झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए फ्लैट की व्यवस्था और दिल्ली से वीआईपी कल्चर समाप्त करना उनके अन्य प्रमुख वादे थे. दिल्ली के सभी घरों में 700 लीटर मुफ्त पानी पहुंचाने के वादे के क्रम में सरकार बनने के बाद उन्होंने 666 लीटर पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की, लेकिन अरविन्द केजरीवाल के इस्तीफे के बाद इस घोषणा को वापस ले लिया गया. जहां तक बिजली बिल का सवाल है तो पार्टी के स्थापना के बाद ही बिजली की बिल पर सत्याग्रह के दौरान पार्टी ने लोगों से बिजली बिल नहीं जमा करने की अपील की थी. जिसके नतीजे में बिजली बिल नहीं अदा करने वाले लोगों पर जुर्माना हुआ था. केजरीवाल सरकार ने उस जुर्माने को माफ़ कर दिया और चुनावी घोषणा के मुद्दे नज़र उन्होंने 400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का ऐलान किया था. लेकिन इस घोषणा को भी उनके

इस्तीफे के बाद वापस ले लिया गया. चूंकि सरकार केवल 49 दिन चली थी. उनके इन दो फैसलों को बाद में वापस ले लिया गया, इसलिए ज़मीन पर इन घोषणाओं की सफलता या असफलता का अंदाज़ा नहीं हो पाया.

अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है आम आदमी पार्टी के बाक़ी लोक लुभावन वादों का क्या हुआ? क्योंकि यह वादे तभी पूरे हो सकते थे जब सरकार आगे चलती. अलबत्ता उनकी सरकार जाते–जाते अनुबंध पर रखे गए दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की सेवायें नियमित किया जाने जैसे वादे को पूरा कर देती तो उनकी नीयत पर शक करने की गुंजाईश नहीं रहती. लेकिन उन्हें शायद यह बात समझ में आ गई होगी कि उन्होंने जो वादे किए हैं वे कभी पूरे नहीं हो सकते, इसलिए लोकपाल को बहाना बनाकर त्यागपत्र दे दिया था. केजरीवाल अब यह कह रहे हैं कि उनसे सौ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ़ है. कुल मिलाकर अब तक के उनके चुनाव प्रचार से यह साफ़ तौर पर ज़ाहिर होता है कि वे अपनी 49 दिनों की सरकार की सफलताओं के आधार पर और बिजली–पानी जैसी अपनी पुरानी लोक लुभावन घोषणाओं के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं. बहरहाल, कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं लिया था इसीलिए उसने पार्टी के चुनावी घोषणाओं पर सवाल खड़े नहीं किये थे. भाजपा के भी प्रचार का केंद्र बिंदु कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए उसने भी आम आदमी पार्टी की चुनावी घोषणाओं पर सवाल नहीं उठाये. लेकिन इस बार पार्टी को न केवल अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं करने पर सफाई देनी पड़ रही है बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों से आमने–सामने का मुक़ाबला करना पड़ रहा है.

पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा भी लोक लुभावन घोषणाएं करने में किसी भी पार्टी से पीछे नहीं थी. पार्टी ने बिजली के बिल में 30 प्रतिशत की कटौती करने, सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडर देने, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने, महिला सुरक्षा, अवैध कालोनियों को रेगुलराइज करने, दिल्ली में साइकिल कल्चर स्थपित करने जैसी चुनावी घोषणाएं की थीं. हालांकि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बन सकी थी लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में है और कम से कम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के सिलसिले में कुछ काम कर सकती थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दिल्ली विधान सभा चुनाव के सिलसिले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान के अपने भाषण में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात नहीं की, जिसको आम आदमी पार्टी ने प्रमुखता से मुद्दा बनाया और केंद्र सरकार से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग करते उनके पोस्टर जगह–जगह नज़र आने लगे हैं. केंद्र में आने के बाद भाजपा राष्ट्रपति शासन के दौरान अपनी कुछ घोषणाओं पर अमल करवा सकती थी लेकिन उनकी घोषणाएं भी घोषणाएं ही रहीं. इस चुनाव में भी पार्टी कामोबेश उन्हीं मुद्दों पर चुनाव मैदान में उतरी है.

चूंकि चुनाव से पूर्व दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में थी और पार्टी राष्ट्रमंडल खेल घोटालों जैसे कई तरह के सवालों में घिरी हुई थी, इसलिए वह पहले से ही बैक–फुट पर नज़र आ रही थी. लेकिन कांग्रेस भी लोक लुभावन वादे पेश करने में पीछे नहीं रही. पार्टी ने राष्ट्री राजधानी क्षेत्र के लिए साझा आर्थिक कराधान क्षेत्र स्थापित करने की बात की, खाद्यान सुरक्षा कानून के तहत 73 लाख लोगों को अनाज उपलब्ध कराने, सड़क पर रेहड़ी लगाने वालों के लिए अलग जोन बनाने, 40 लीटर सब्सीडाइज पानी उपलब्ध करवाने जैसी घोषणाओं के साथ–साथ अवैध कोलोनियों को नियमित करने और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 4 लाख फ्लैट बनवाने की बात की थी. ज़ाहिर है कांग्रेस पिछले 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ थी इसलिए उसके इन वादों पर जनता ने ध्यान नहीं दिया और उसे सत्ता से बेदखल कर दिया.

दिल्ली में सत्ता के तीनों मुख्य दावेदार पार्टियों की घोषणाओं को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि चुनाव के दौरान की जाने वाली घोषणाएं केवल चुनाव जीतने के लिए होती हैं और सत्ता में आने के बाद पार्टियां इन्हें गंभीरता से नहीं लेतीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अब एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली को जीतना चाहते हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में इस बार भाजपा को हरा पाना पहले के मुक़ाबले अधिक कठिन है. कांग्रेस न तो तब कहीं लड़ाई में थी और न अब है. इसलिए कुल मिलाकर जनसामान्य में बात केवल दो ही पार्टियों को लेकर हो रही है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी. कुछ लोग यह मान रहे हैं कि पिछली बार तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल हो गई थी, लेकिन इस बार दिल्ली में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

दिल्ली विधानसभा चुनाव

कांग्रेस और आप के बीच फंसे मुस्लिम मतदाता

डॉ. क़मर तबरेज़

सत्तर सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है. आगामी सात फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 फरवरी को वोटों की गिनती होगी. पिछली बार जब दिसंबर 2013 में यहां चुनाव हुआ था, तो किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली थीं, जिसकी बुनियाद पर वह आसानी से सरकार बना पाती. दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें हासिल करना आवश्यक है, लेकिन पिछली बार के चुनाव में भाजपा को 31, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को केवल आठ सीटें ही मिल पाई थीं. चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने में सफल ज़रूर हुई, लेकिन यह सरकार केवल 49 दिनों तक ही चल सकी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. दरअसल, अरविंद केजरीवाल उस समय आम चुनाव में कूदना चाहते थे, हालांकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना कोई प्रभाव नहीं रखती थी. अपने इस ग़लत निर्णय से मलाल केजरीवाल और उनकी पार्टी को आज तक है.

अब एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली को जीतना चाहते हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में इस बार भाजपा को हरा पाना पहले के मुक़ाबले अधिक कठिन है. कांग्रेस न तो तब कहीं लड़ाई में थी और न अब है. इसलिए कुल मिलाकर जनसामान्य में बात केवल दो ही पार्टियों को लेकर हो रही है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी. कुछ लोग यह मान रहे हैं कि पिछली बार तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल हो गई थी, लेकिन इस बार दिल्ली में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. हालांकि, यह भी सच है कि पिछली बार जब पूरी दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल का बुखार चढ़ा हुआ था, तो भी चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था और सरकार बनाने के लिए उसे कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ा था. इसलिए पूरे विश्वास के साथ यह भी नहीं कहा सकता कि ऐसे समय में, जबकि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अगली सरकार बनाने में कामयाब हो ही जाएगी.

मुसलमानों की अगर बात करें, तो दिल्ली के लगभग एक करोड़ 20 लाख मतदाताओं में से 11 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं. मटिया महल, बल्लीमारां, सीलमपुर, मुस्तफाबाद और ओखला जैसे विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. पिछली बार इन पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी और इस बार भी कुछ ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है. आम आदमी पार्टी ने भले ही इनमें से चार सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसका कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल नहीं हो सका था. आम आदमी पार्टी ने पांचवें मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में शाजिया इल्मी को आरकेपुरम से खड़ा किया था, लेकिन वह भी 326 वोटों के साधारण अंतर से वहां चुनाव हार गई थीं. पिछली बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने पांच, जबकि कांग्रेस ने छह मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है.

आइए देखते हैं, इन पांचों विधानसभा सीटों पर पिछली बार मुस्लिम उम्मीदवारों की स्थिति क्या थी और इस बार यहां के मुसलमानों का रुझान क्या है. सबसे पहले बात करते हैं मटिया महल विधानसभा सीट की, जो कि पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के आसपास का क्षेत्र है. यहां पर मुसलमानों की आबादी 67 प्रतिशत है. पिछली बार मटिया महल सीट पर कुल 71,670 वोट पड़े थे, जिनमें से विजयी उम्मीदवार शोएब इकबाल (जो उस समय जदयू में थे और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं) को 22,732 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार मिर्ज़ा जावेद अली को 19,841 वोट मिले थे. आम आदमी पार्टी के शकील अंजुम देहलवी 18,668 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे. इस बार कांग्रेस ने मटिया महल सीट से शोएब इकबाल को अपना उम्मीदवार बनाया है. भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहां से निज़ामुद्दीन को खड़ा किया था, जिन्हें कुल 6,061 वोट मिले थे. मटिया महल सीट पर 1993 से ही शोएब इकबाल का क़ब्ज़ा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर शोएब इकबाल का नाम पार्टी से हर बार बड़ा हो जाता है. यहां के मतदाताओं पर अब तक इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि शोएब इकबाल किस पार्टी में हैं. यही कारण है कि बिहार के जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी में रहकर भी शोएब इकबाल यहां से चुनाव जीत चुके हैं. आजकल वह कांग्रेस में हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी उनके जीतने की संभावनाएं प्रबल हैं. भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 1983 में बेगम खुर्शीद किदवई भी यहां से एक बार चुनाव जीत चुकी हैं.

पुरानी दिल्ली का एक और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है बल्लीमारां. शोएब इकबाल की तरह बल्लीमारां से हारुन यूसुफ़ 1993 से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं. पिछली बार इस सीट पर कुल 88,749 वोट पड़े थे, जिनमें से विजयी कांग्रेस उम्मीदवार हारुन यूसुफ़ को 32,105 वोट मिले थे, दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोती लाल सोढ़ी को 24,012 वोट मिले थे, जबकि बसपा के इमरान हुसैन तीसरे नंबर पर रहे थे. कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट से हारुन यूसुफ़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने पिछली बार यहां से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले इमरान हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है. पिछली बार यहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार फरहाना अंजुम 13,103 वोटों के साथ चौथे नंबर पर थीं. यूं तो इस बार भी यहां से हारुन यूसुफ़ के जीतने की प्रबल संभावना है, लेकिन अगर यहां का मुस्लिम वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अधिक बंटा, तो उस स्थिति में भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है.

मुस्लिम उम्मीदवार

विधानसभा क्षेत्र	आम आदमी पार्टी	कांग्रेस
मटिया महल	आसिम अहमद खां	शोएब इक़बाल
बल्लीमारां	इमरान हुसैन	हारुन यूसुफ़
मुस्तफ़ाबाद	हाजी यूनुस	हसन अहम
सीलमपुर	हाजी इशराक	चौधरी मतीन
ओखला	अमानत उल्लाह खां	आसिफ़ मोहम्मद खां
बाबरपुर	.....	हाजी दिलशाद

मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में यूं तो मतदाताओं की संख्या दो लाख से अधिक है, लेकिन पिछली बार एक लाख 46 हज़ार 314 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिनमें से 56,250 वोट हासिल कर कांग्रेस उम्मीदवार हसन अहमद ने जीत दर्ज कराई थी, जबकि भाजपा उम्मीदवार जगदीश प्रधान 54,354 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे. तीसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कपिल धाम को केवल 19,759 वोट मिले थे. कांग्रेस ने इस बार भी हसन अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस बार यहां से हाजी यूनुस को खड़ा किया है. लिहाज़ा, इस बार यहां पर दो पार्टियों द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करने के कारण मुसलमानों का वोट बंटने का ख़तरा बढ़ गया है, जो भाजपा उम्मीदवार को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

सीलमपुर भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है. यहां पर मुसलमानों की आबादी लगभग 60 प्रतिशत है. पिछली बार यहां के लगभग डेढ़ लाख मतदाताओं में से 99,295 लोगों ने वोट डाले थे, जिनमें से विजयी कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी मतीन अहमद को 46,452 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार कौशल कुमार मिश्रा 24,724 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे. बहुजन समाज पार्टी के अब्दुल रहमान 13,352 वोटों के साथ तीसरे और आम आदमी पार्टी के मसूद अली ख़ां 12,969 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे थे. शोएब इकबाल और हारुन यूसुफ़ की तरह चौधरी मतीन अहमद भी 1993 से सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि 1993 से लेकर 2013 तक के चुनावों में उन्होंने लगातार पांच बार यहां से भाजपा के उम्मीदवार को ही हराया है. दूसरी ओर एक सच्चाई यह भी है कि चौधरी मतीन अहमद को मिलने वाले कुल वोट जहां धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, वहीं भाजपा उम्मीदवार के वोटों में लगातार इज़ाफ़ा होता जा रहा है. चौधरी मतीन अहमद को हराने में भाजपा को अभी कितने साल और लगेंगे, यह कहना ज़रा मुश्किल है.

ओखला विधानसभा क्षेत्र में भी मुसलमान किसी भी उम्मीदवार को हराने या जीत दिलाने का दम रखते हैं. सीलमपुर और बल्लीमारां की तरह ओखला से अधिकतर मतदाताओं की पहली पसंद पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद मुसलमानों का वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बंटा है. पिछली बार यहां के कुल 2,35,966 मतदाताओं में से लगभग एक लाख लोगों ने अपने वोट डाले ही नहीं थे. पिछली बार यहां से कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ़ मोहम्मद खां ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इरफान खान को 25 हज़ार से अधिक वोटों से हराया था. भाजपा यहां पर तीसरे नंबर पर थी. आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों के ही उम्मीदवारों को 23 हज़ार से कुछ अधिक वोट मिले थे, जबकि आसिफ़ मोहम्मद खां को 50 हज़ार वोट मिले थे. इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां से अमानत उल्लाह को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने दोबारा आसिफ़ मोहम्मद खां को अपना उम्मीदवार बनाया है. अमानत उल्लाह पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर खड़े हुए थे और उन्हें केवल 3,747 वोट मिले थे. यहां के लगभग 20 हज़ार लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह के पक्ष में वोट दिए थे. मुसलमानों के मौजूदा रुझान को देखते हुए इस बार यहां से आम आदमी पार्टी के वोटों में कुछ इज़ाफ़ा ज़रूर हो सकता है. यहां से आसिफ़ मोहम्मद खां को हरा पाना किसी भी दूसरी पार्टी के लिए मुश्किल लग रहा है.

इन पांच विधानसभा क्षेत्रों के अलावा दिल्ली में और भी कई ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं, जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है. इन्हीं में से एक बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां पर मुसलमानों की आबादी लगभग 48 प्रतिशत है. यहां पर मुस्लिम वोटों के विभाजन का फ़ायदा उठाते हुए नरेश गौण चार बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं. पिछली बार भी उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार ज़ाकिर खान को साढ़े चार हज़ार वोटों के अंतर से हराया था. तीसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के गोपाल राय को केवल 22.37 प्रतिशत वोट मिले थे. इस बार कांग्रेस ने यहां से हाजी दिलशाद को टिकट दिया है.

इसी प्रकार सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में भी मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं. यहां के अधिकतर मुसलमान पहले कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन पिछली बार उनमें से अधिकतर ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिए. शायद यही कारण था कि पिछली बार यहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वीना आनंद लगभग 38 प्रतिशत वोट हासिल कर जीतने में सफल रहीं, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई, लेकिन इस बार यहां के मुसलमान अपनी विधायक से नाराज़ नज़र आ रहे हैं. उनकी शिकायत है कि वीना आनंद ने अपने क्षेत्र और विशेषकर, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया. सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में भी मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है. पिछली बार यहां से आम आदमी पार्टी के धर्मेंद्र कुमार लगभग 38 प्रतिशत वोटों के साथ जीतने में कामयाब रहे थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के उम्मीदवार रामपाल सिंह को लगभग 21 प्रतिशत वोट मिले थे. यहां के मुस्लिम मतदाताओं के मौजूदा रुझान की बात करें, तो अधिकतर मुस्लिम अब भी आम आदमी पार्टी को अपनी पहली पसंद बताते हैं.

इस तरह देखा जाए, तो दिल्ली में मुसलमानों का रुझान भले ही आम आदमी पार्टी की ओर अधिक दिखाई देता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को अपना समर्थन देना पूरी तरह बंद कर दिया है. लिहाज़ा मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न में इस बार किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है. इस बात की अधिक उम्मीद है कि पिछली बार जिन मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, वे इस बार भी अपनी सीट निकालने में कामयाब हो जाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

रहमान मियां जैसे हज़ारों बुनकर गंगा आरती की भीड़–भाड़ में हर माल दस रुपये वाले खिलौने बेचने को मजबूर होते हैं. बुनकरों को इस बात की जानकारी है कि महाजन ही पूरे बाज़ार को नियंत्रित करता है और फ्लिपकॉर्ट जैसी युक्ति का लाभ भी फिलहाल वही हासिल करने की स्थिति में है, क्योंकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि फ्लिपकॉर्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण कैसे होगा और उसमें बुनकरों की भूमिका क्या होगी. बेहतर होता कि सरकार स्थानीय स्तर पर विपणन केंद्रों को बढ़ावा देने संबंधी क़दम उठाती. खासकर, कृषि फसल की खरीद–बिक्री की तर्ज पर लूम प्रोडक्ट की खरीद–बिक्री को बढ़ावा देने संबंधी उपाय करती.

बुनकरों की बदहाली कब दूर होगी

डॉ. वसीम अख्तर

रहमान मियां से दशाश्वमेध घाट पर मुलाकात हुई थी. वही दशाश्वमेध घाट, जहां की गंगा आरती देखने के लिए देश और परदेस से पर्यटक इकट्ठा होते हैं. रहमान मियां एक बुनकर भी हैं. मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल रखने के लिए हमने रहमान मियां से 10–10 रुपये के दो खिलौने खरीदे थे. रहमान मियां का चेहरा, उनका अंदाज़ और आवाज़ आज भी मेरा पीछा कर रहा है. मेरे लिए बनारसी बुनकरों से मिलना और उनके साथ घंटों बातें करना कम से कम पिछले 12 वर्षों से कोई नई बात नहीं है. आख़िर रहमान मियां में ऐसा क्या था कि जब कभी भी बुनकरों का जिक्र आता है, रहमान मियां के साथ गुजारे चंद लम्हे और उनका चेहरा बरबस ही चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम जाते हैं. चलने से पहले रहमान मियां से मैंने पूछा था कि वह बनारस की खटर–पटर से अलग, ढलती हुई शाम में गंगा आरती के वक्त यहां घाट पर क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने बेचारगी भरी मासूमियत के साथ सिर्फ़ इतना ही कहा था कि क्या करें, लूमवा का धंधवा फेल मार गवा ना...

लूमवा का धंधवा ऐसा उद्योग है, जहां एक परिवार एक साथ एक इकाई की तरह काम करता है. अपनी मेहनत और लाजवाब कर देने वाली कला से पूरी दुनिया में बनारस को एक खास पहचान देने वाले बनारसी बुनकरों के परिवार लूम इंडस्ट्री को हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए अपना खून–पसीना बहाते रहे हैं, लेकिन उनके धंधे के तौर–तरीके ऐसे रहे हैं कि लगभग हर 5 साल के अंदर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है. एक तरफ़ उनके लिए सरकारी कोशिशें होती हैं, जिनमें दस्तकारों की पहचान, उनके स्वास्थ्य एवं सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा के उपाय, जैसे ऋण देने और ऋण माफ़ करने जैसी योजनाएं शामिल होती हैं. वहीं दूसरी तरफ़ बुनकरों की मुंहज़बानियां होती हैं, जिनमें मांग और आपूर्ति के हवाले से यह बताया जाता है कि अभी तो मंदी चल रही है. जब धंधा मंदा नहीं होता, तब यहां के बुनकर कहते हैं कि पहले से ठीक है.

पिछले साल जब लोकसभा चुनाव के बाद बनारस प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र बना, तो यहां के लोगों की आंखों में उम्मीदों की नई किरण देखी गई, लेकिन आज भी हमारे जैसे रिसर्चर जब बनारस के बुनकरों के घरों में पहुंचते हैं, तो मंदी की आह नज़रों में उतरती हुई सुनाई देती है. एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों है कि अपने पूरे परिवार को एक इकाई बनाकर मेहनत करने वाले बुनकरों पर ही लूम इंडस्ट्री की मंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? जवाब में एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि बनारसी साड़ी के कारोबार में बिचौलियों की बड़ी भूमिका है. बाज़ार किसी भी आर्थिक गतिविधि का एक अभिन्न अंग होता है. बुनकरी में अगर बनारस को एक बड़े केंद्र या प्रतीक के तौर पर देखा जाए, तो बुनकर बाज़ार की पहचान कहीं चौक, तो कहीं बैठका के रूप में होती है. बैठका और चौक वे स्थान हैं, जहां से महाजन बुनकरों को कच्चा माल यानी धागा (यार्न) उपलब्ध कराते हैं और उनसे तैयार माल लेते हैं.

पिछले साल जब लोकसभा चुनाव के बाद बनारस प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र बना, तो यहां के लोगों की आंखों में उम्मीदों की नई किरण देखी गई, लेकिन आज भी हमारे जैसे रिसर्चर जब बनारस के बुनकरों के घरों में पहुंचते हैं, तो मंदी की आह नज़रों में उतरती हुई सुनाई देती है. एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों है कि अपने पूरे परिवार को एक इकाई बनाकर मेहनत करने वाले बुनकरों पर ही लूम इंडस्ट्री की मंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है?

इसके अलावा ढेरों बुनकर, जो खुद को इस दायरे से बाहर रखते हैं, उन्हें भी तैयार माल यानी साड़ी वगैरह किसी चौक स्थित किसी महाजन या फिर किसी के बैठका तक ही पहुंचाना पड़ता है. आगे का काम जिसे बिजनेस या व्यापार कहा जाता है, वह महाजन या बैठका वाले करते हैं. बुनकर, जो ताना–बाना का निगहबान होता है, वह व्यापार की प्रक्रिया से बाहर रहता है. जितनी डिजाइन, उतनी मेहनत, वक्त और लागत. हर साड़ी अपने–आप में सुंदर और आकर्षक. समझना ज़रूरी हो जाता है कि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है और उसमें कौन लोग शामिल होते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए लल्लापुरा के इनामुल हक़ अंसारी कहते हैं कि महाजन जो रेट तय करते हैं, उसी रेट में तैयार माल देना होता है. आगे उनकी मर्जी कि वे उस माल को कितनी क़ीमत में बेचते हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही बाज़ार में साड़ियों की क़ीमत वही तय करते हैं.

जाहिर है, बाज़ार से सीधा संपर्क बुनकरों की ज़रूरत रही है. बुनकरों की मानें, तो इससे रेट का फ़र्क़ ठीक हो सकता है. साड़ियों की मांग और आपूर्ति पर महाजनों के रूप में बिचौलियों का जो नियंत्रण है, वह कमज़ोर होगा. निश्चित तौर पर फ्लिपकॉर्ट जैसी युक्ति बुनकरों को इन समस्याओं का ऐसा समाधान दे सकती है. लेकिन, दसवीं पास इनामुल हक़ की बात भी नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती है. वह कहते हैं कि फ्लिपकॉर्ट जैसी ऑनलाइन मार्केटिंग के तौर–तरीकों को समझने के लिए पहले बुनकरों को इस लायक बनना होगा. अगर बनारस में बिचौलियों को छोड़ दिया जाए, तो आम बुनकरों को फ्लिपकॉर्ट पर व्यापार के बारे में न तो कोई जानकारी है और न कोई अनुभव. कुछ नौजवान बुनकरों को टच स्क्रीन मोबाइल पर वाट्सअप और फेसबुक चलाते देखा जा सकता है, उन्हें गूगल पर गाने सर्च करते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि बुनकरों के जवान होते बच्चे अपनी खुद की मेहनत के उस विमर्श से दूर हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं.

रहमान मियां जैसे हज़ारों बुनकर गंगा आरती की भीड़–भाड़ में हर माल दस रुपये वाले खिलौने बेचने को मजबूर होते हैं. बुनकरों को इस बात की जानकारी है कि महाजन ही पूरे बाज़ार को नियंत्रित करता है और फ्लिपकॉर्ट जैसी युक्ति का लाभ भी फिलहाल वही हासिल करने की स्थिति में है, क्योंकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि फ्लिपकॉर्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण कैसे होगा और उसमें बुनकरों की भूमिका क्या होगी. बेहतर होता कि सरकार स्थानीय स्तर पर विपणन केंद्रों को बढ़ावा देने संबंधी क़दम उठाती. खासकर, कृषि फसल की खरीद–बिक्री की तर्ज पर लूम प्रोडक्ट की खरीद–बिक्री को बढ़ावा देने संबंधी उपाय करती. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे केंद्रों के संचालन में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं परंपराओं को स्थापित किया जाए.

अगर नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्कूलों की प्रबंधन समितियों में 75 प्रतिशत अभिभावकों की उपस्थिति मुमकिन है, तो साड़ियों की खरीद–बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर (मुहल्ला या वार्ड स्तर) विपणन केंद्रों की स्थापना और उनके संचालन में 75 प्रतिशत आम बुनकरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना भी संभव है. सोशल ऑडिट की तरह ऐसे केंद्रों की निगरानी करके लोकतांत्रिक तौर–तरीकों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है. ऐसा करने से महाजन या बिचौलिए भी अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील होंगे. तभी सामाजिक ढांचे में भी लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव संभव होंगे. और, तभी यह भी मुमकिन होगा कि रहमान मियां जैसे काबिल शख्स को लुंगी और टोपी संभालते हुए घाट–घाट खिलौने बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली विधानसभा चुनाव

सर्वे रिपोर्ट्स का चुनावी हथियार बेअसर

चौथी दुनिया ब्यूरो

दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. सात फरवरी को विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतदान होगा. पिछली बार की तरह इस बार भी सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर–शोर से जुट गई हैं. मुक़ाबला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है. हर कोई अपने को दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा है. इसके लिए प्रचार के नए–नए तरीके अपनाए जा रहे हैं.

चुनावी सर्वे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की परंपरा आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में शुरू की थी. उस दौरान जो भी स्थापित सर्वे एजेंसियां थीं, उनमें से अधिकांश ने आप को चार से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था. आप ने अपने इंटरनल सर्वे को आधार बनाया और उसके आधार पर चुनाव प्रचार किया. इसका फ़ायदा उसे मिला और अंतत: वह 28 सीटें जीतने में सफल हुई. इस बार भी वह ऐसा ही कुछ कर रही है. इस बार भी उसने प्रचार के लिए अपने पक्ष में आए टोटल टीवी के सर्वे को चुनावी हथियार बनाया है. इस सर्वे के मुताबिक, आप को 48 प्रतिशत लोगों ने वोट देने की बात कही है, जबकि भाजपा 40 प्रतिशत लोगों की पसंद है. इसके अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की. पिछली बार उसने अपना चुनाव प्रचार तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को केंद्र में रखकर किया था, लेकिन इस बार उसने विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की खुद ही घोषणा कर दी और उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से करते हुए चुनाव प्रचार शुरू किया. आप ने भाजपा के जगदीश मुखी को अपनी ओर से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया और उनके मुकाबले मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केजरीवाल को अपनी पहली पसंद बताया. इस आधार पर उसने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की.

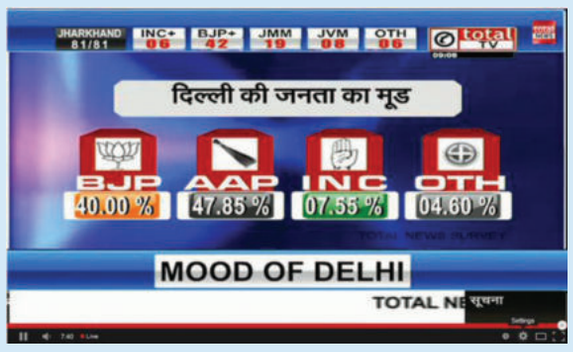

विभिन्न सर्वे एजेंसियां टीवी चैनलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव के लिए सर्वे कर रही हैं. इस कड़ी में बीते दिसंबर में इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो ने दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अलग–अलग आयु वर्ग के 4,273 लोगों की राय जानी कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद कौन है? जवाब में 35 प्रतिशत लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 19 प्रतिशत लोगों ने डॉ. हर्षवर्धन, नौ प्रतिशत लोगों ने शीला दीक्षित और आठ प्रतिशत लोगों ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को अपनी पसंद बताया. सर्वे तीन अलग–अलग आयु वर्ग (18–35, 35–50 और 50–75 वर्ष) के लोगों के बीच किया गया था. लेकिन, जब पार्टी के आधार पर वोट डालने की बात आई, तो लोगों ने भाजपा को पहली पसंद बताया. इस आधार पर भाजपा को 34 से 40 सीटें, आप को 25–31 सीटें और कांग्रेस को 03–05 सीटें मिलने की संभावना जताई गई.

चुनावी सर्वे को अन्य राजनीतिक दल और उम्मीदवार भी अपना हथियार बना रहे हैं. हर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार अपना सर्वे करा रहे हैं और अनजान एजेंसियों के नाम से लोकप्रियता के मामले में खुद को सबसे आगे दिखा रहे हैं तथा भावी विधायक के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. कोंडली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमरीश सिंह गौतम ने भी क्षेत्र में एक पोस्टर लगवाया, जिसमें उन्होंने एक सर्वे का हवाला देते हुए खुद को क्षेत्र के 61 प्रतिशत लोगों की पसंद बताया. पिछली बार इस विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार को केवल 11 प्रतिशत लोगों की पसंद बताया गया. ऐसा ही राजधानी के अन्य इलाकों में भी हो रहा है. सर्वे रिपोर्ट्स की बाढ़–सी आ गई है. मतदाता कन्फ्यूज हो गया है और राजनीतिक दलों के इस हथकंडे को नज़रअंदाज़ कर रहा है. शायद अब उसका यकीन सर्वे रिपोर्ट्स में नहीं रह गया है.

फिलहाल उक्त चुनावी सर्वे के जो परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं, उनमें एक बड़ा विरोधाभास है. वह यह कि जितनी बार सर्वे हो रहे हैं, उनके परिणामों में हर बार भाजपा को मिलने वाली सीटों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है. दूसरी तरफ़ केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे भी परिणाम सामने आ रहे हैं. व्यवहारिक रूप में दोनों ही बातें एक साथ पूरी नहीं हो सकतीं कि भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिलें, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री बनें. एक प्रमुख बात यह भी है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार घोषित ही नहीं किए थे. ऐसे में, केजरीवाल का मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद बनना लाजिमी था.

आप को मात देने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने आख़िरी समय में अपने पत्ते खोले. चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने अजय माकन जैसे साफ़ छवि वाले नेता को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी. दूसरी तरफ़ भाजपा ने एक बड़ा दांव खेलते हुए लोकपाल आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रह चुकीं पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को पार्टी में शामिल करा लिया. यही नहीं, उन्हें दिल्ली के चुनावी समर में उतारने की घोषणा भी कर दी. इन दोनों नामों के सामने आने के बाद स्थिति यह बनी कि अब तक जो भी सर्वे हुए हैं, वे सभी आधारहीन हो जाएंगे. कांग्रेस और भाजपा के क़दमों का भी दिल्ली की जनता पर सीधा फ़र्क़ पड़ेगा. इसलिए आगे जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी, उनमें भारी उतार–चढ़ाव देखने को मिलेगा. ■

आप को मात देने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने आख़िरी समय में अपने पत्ते खोले. चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने अजय माकन जैसे साफ़ छवि वाले नेता को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी. दूसरी तरफ़ भाजपा ने एक बड़ा दांव खेलते हुए लोकपाल आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रह चुकीं पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को पार्टी में शामिल करा लिया. यही नहीं, उन्हें दिल्ली के चुनावी समर में उतारने की घोषणा भी कर दी.

feedback@chauthiduniya.com

> ब्रिगेडियर चाको ने कहा है कि वाराणसी में भी भर्ती रैली की अनुमति पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद मिल सकी. रायबरेली के ज़िलाधिकारी ने तो उनके जनपद के अलावा दूसरे ज़िलों की भर्ती की अनुमति देने से लिखित रूप से इंकार कर दिया. ब्रिगेडियर ने कहा कि भारतीय सेना में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 20 फ़ीसद भागीदारी है. लगभग 15 से 20 हज़ार सैनिक यहां से हर वर्ष भर्ती होते हैं, जिसमें बड़ा भाग उत्तर प्रदेश का होता है.

यूपी में जवानों की भर्ती रोक देगी सेना!

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में अब सेना की भर्ती रुक सकती है. भारतीय थलसेना उत्तर प्रदेश में सैनिकों की भर्ती रोककर उसे किसी अन्य राज्य को देने पर विचार कर रही है. सेना ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में पत्र लिखकर चेतावनी भी दी है और उससे जवाब भी मांगा है. अगर सेना ने उत्तर प्रदेश में सैनिकों की भर्ती रोकी, तो यह राज्य के लिए भारी नुक़सान वाला क़दम साबित होगा. लेकिन, उत्तर प्रदेश सरकार को महोत्सव और मौज-मस्ती से फुर्सत नहीं है. ग़ौरतलब है कि थलसेना के जवानों का 20 फ़ीसद हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भरा जाता है. यहां होने वाली भर्तियों के कारण प्रदेश के युवकों को रोज़गार मिलता है और प्रदेश को राजस्व के साथ-साथ सम्मान मिलता है. लेकिन, उत्तर प्रदेश सरकार के ग़ैर ज़िम्मेदाराना रवैये के चलते सूबे में होने वाले सेना भर्ती कार्यक्रमों पर ग्रहण लगने की आशंका है. सेना ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सेना भर्ती के आयोजनों में उसे सहयोग नहीं कर रही है. इस वजह से उत्तर प्रदेश से सेना में अपेक्षित भर्तियां नहीं हो पा रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की इस उपेक्षा के कारण प्रदेश के युवकों का नुक़सान हो रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार के अलमबरदार सेना के आला अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक तो रखते हैं, लेकिन सेना की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते. सेना के अधिकारी कहते हैं कि सेना में युवकों की भर्ती का फ़ायदा प्रदेश को ही मिलता है. प्रदेश सरकार के इसी रवैये के चलते फैजाबाद स्थित डोगरा रेजिमेंट के उखड़ कर हिमाचल प्रदेश चले जाने का रास्ता तैयार हुआ है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सेना भर्ती के उप-महानिदेशक ब्रिगेडियर एमडी चाको की यह आधिकारिक शिकायत काफी गंभीर है. ब्रिगेडियर चाको ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सेना भर्ती में पूरी तरह असहयोग बरतने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों झांसी ज़िला प्रशासन ने भर्ती की पूर्व घोषित तारीख से एक दिन पहले भर्ती कार्यक्रम रद्द करने का एकतरफ़ा फ़ैसला सुना दिया, जिससे अफरातफरी मच गई. सेना में भर्ती के कार्यक्रम काफी होमवर्क और कवायद के बाद तैयार किए जाते हैं. उनके बारे में संबद्ध ज़िला प्रशासनों को बाकायदा पहले से सूचना दी जाती है. भर्ती की सूचनाएं बाकायदा भर्ती की अनुमति देने से लिखित रूप से इंकार कर दिया. ब्रिगेडियर ने कहा कि भारतीय सेना में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 20 फ़ीसद भागीदारी है. लगभग 15 से 20 हज़ार सैनिक यहां से हर वर्ष भर्ती होते हैं, जिसमें बड़ा भाग उत्तर प्रदेश का होता है. एक जवान को वर्ष में सेना की ओर से जो वेतन एवं सुविधाएं दी जाती हैं, वह धन संबंधित प्रदेश में ही खर्च होता है, क्षेत्र की बेरोज़गारी दूर होती है. इसके बावजूद प्रदेश सरकार के अधिकारियों का रवैया समझ से परे है. सेना भर्ती में स्थानीय स्तर पर असहयोग पर ब्रिगेडियर ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया. फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ छावनी स्थित करियप्पा कॉम्प्लेक्स में पिछले दिनों चल रही भर्ती के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के असहयोगात्मक रवैये को देखकर चाको ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप जड़े. ब्रिगेडियर चाको ने यहां तक कहा कि हालात बेहद खराब हैं और यदि यही स्थिति बनी रही, तो उत्तर प्रदेश का

एक तरफ़ कमी, दूसरी तरफ़ कोताही

जवानों और अफसरों की कमी से जूझ रही भारतीय सेना को प्रदेश सरकारों का असहयोगात्मक रवैया भी झेलना पड़ रहा है. भारत सरकार यह आधिकारिक रूप से स्वीकार करती है कि देश की तीनों सेनाओं को मिलाकर अफसरों और जवानों की भारी कमी है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में सेना में भर्ती होने के लिए बड़ी संख्या में जुटने वाले युवकों को और उत्साहित करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने असहयोग के चलते ऐसे युवकों का मनोबल गिरा रही है. आपको याद ही होगा कि लखनऊ में एक भर्ती रैली के दौरान युवकों को सीवर की छत पर खड़ा करा दिया गया था. सीवर की छत ढह जाने की वजह से तक़रीबन 50 युवकों की मौत हो गई थी. प्रशासनिक अराजकता का यह भीषण उदाहरण है. बरेली में भी भर्ती के लिए आए कई युवकों की सरकारी इंतजामात की कमी के कारण मौतें हो चुकी हैं. खास तौर पर सेना की भर्ती रैली में आने वाले युवकों की भगदड़ या बदइंतजामी के कारण होने वाली मौतों की ख़बरें लगातार आती रहती हैं. सरकार इंतजाम से पल्ला झाड़ती रहती है, लेकिन शासन-प्रशासन की मदद के बगैर सेना भर्ती रैलियां नहीं हो सकतीं. सरकार के इस बेजा रवैये की वजह से सेना में गहरी नाराज़गी है. आज देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा, जहां सेना की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की हिफाजत एवं आतंकियों से लगातार परोक्ष युद्ध लड़ते हुए सेना को प्राकृतिक आपदाओं और क़ानून व्यवस्था के मामलों में भी उतरना पड़ता है. पुलिस पूरी तरह नाकाम है. यहां तक कि बोरवेल में बच्चा गिरने पर भी सेना को ही उसे निकालने के लिए आना पड़ता है. शासन-प्रशासन को इससे शर्म भी नहीं आती. सेना का संकट यह है कि अफसरों के अलावा जवानों की भारी कमी है. अफसरों के कुल स्वीकृत 47,574 पदों में से 9,845 पद रिक्त हैं. इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन एवं लेफ्टिनेंट शामिल हैं. जवानों की कमी लगभग 60-70 हजार आंकी गई है. सेना में भर्ती होने के बाद भी वे सेना छोड़कर भाग रहे हैं. पिछले पांच सालों के दौरान ही क़रीब 50 हज़ार जवान सेना की नौकरी छोड़कर जा चुके हैं. ऐसी स्थिति में सेना में भर्ती के राष्ट्रीय अनिवार्यता वाले कार्यक्रमों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का असहयोगात्मक रवैया बेहद गंभीर है. ■

चला जाएगा डोगरा रेजिमेंटल सेंटर

सैनिकों के सम्मान के साथ भेदभाव बरतने वाले राज्य उत्तर प्रदेश से भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट अपना बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही है. भारतीय सेना की प्रतिष्ठित डोगरा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है. डोगरा रेजिमेंटल सेंटर होने के कारण फैजाबाद की एक बड़ी आबादी का रोज़गार चलता है और पूरी छावनी बसी रहती है. लेकिन, सेंटर उखड़ जाने से फैजाबाद का बड़ा हिस्सा वीरान हो जाएगा और वहां की चहल-पहल ख़त्म हो जाएगी. डोगरा रेजिमेंटल सेंटर को हिमाचल प्रदेश ले जाने की कोशिशें हो रही हैं. इसमें हिमाचल सरकार काफी सक्रिय है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने डोगरा रेजिमेंट की स्थापना के लिए राज्य में मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है. लेकिन, विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की खाल पर इससे कोई फ़र्क़ ही नहीं पड़ रहा. इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित रेजिमेंट को अपने यहां बनाए रखने में उत्तर प्रदेश सरकार की कोई रुचि नहीं है. लिहाजा इसके लिए कोई कोशिश या पहल भी नहीं हो रही है. ■

सैनिकों के साथ भेदभाव

मुआवजे, पुरस्कार और सम्मान देने में भी उत्तर प्रदेश सरकार फौजियों के साथ भेदभाव का रवैया रखती है. उत्तर प्रदेश में मुआवजा मुख्यमंत्री की मर्जी पर टिक गया है. करगिल युद्ध के पहले 1962, 65 और 71 के युद्धों में शहीद हुए सैनिकों की 10 विधवाओं के पुनर्वास के लिए सरकार ने महज पांच लाख रुपये दिए हैं. करगिल युद्ध के शहीदों को अपेक्षाकृत अधिक तरजीह दी जा रही है, जबकि 1962, 65 और 71 का युद्ध ही पूर्ण युद्ध था. वीर सैनिकों के सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 73 लाख रुपये का बजट रखा है. जबकि पुलिस के एक सीओ की हत्या पर 50 लाख रुपये और दो सरकारी नौकरियों के मुआवजे दिए जाते हैं. शांति काल के वीरता पुरस्कार अशोक चक्र और युद्ध काल के वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के विजेताओं के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकार 25 लाख रुपये का पुरस्कार देती है. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार उसी स्तर की वीरता या शहादत के लिए 1.45 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देती है. चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की मौत पर दस लाख रुपये तक का मुआवजा देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार देश सेवा के लिए शहादत देने वाले सैनिकों के लिए संकीर्ण दृष्टिकोण रखती है. बहादुरी का पुरस्कार जीतने वाले सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से जो धनराशि दी जाती है, उसकी तुलना सैन्य अधिकारियों के एक माह के वेतन से भी नहीं की जा सकती. उत्तराखंड सरकार भी इसी तरह सैनिकों का हक़ दबाए बैठी है. उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों के आश्रितों को दोहरी पेंशन देने के केंद्र के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल रखा है. केंद्र सरकार ने इस बारे में 17 जनवरी, 2013 को ही शासनादेश जारी कर दिया था. इसी शासनादेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में दोहरी पेंशन व्यवस्था लागू की है. रक्षा मंत्रालय ने 17 जनवरी, 2013 को जारी किए अपने आदेश में ऐसे सैन्य पेंशनरों के परिवारीजनों के बारे में व्यवस्था की थी, जो सैन्य सेवा से मुक्त होने के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं में दोबारा नियुक्ति पाते हैं. ऐसे पूर्व सैन्य कर्मियों की मृत्यु के बाद सैन्य सेवा के लिए स्वीकृत पेंशन के साथ परिवार को उनकी सिविल सेवा के लिए भी स्वीकृत पारिवारिक पेंशन मिलेगी. पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद दोहरी पेंशन देने का औचित्य यह था कि सिविल में कार्मिक को 60 वर्ष की आयु में सेवा से रिटायर होने का लाभ मिलता है, जबकि सैनिक कम उम्र में रिटायर होने के बाद दोबारा 60 वर्ष की आयु तक सिविल में सेवाएं देता है. केंद्र के इस आदेश पर उत्तराखंड सैनिक कल्याण निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार करके 17 मई, 2013 को प्रदेश के सैनिक कल्याण सचिव के पास भेजा. 12 जून, 2014 को शासन ने सभी ज़िलाधिकारियों को दोहरी पेंशन का लाभ पाने वालों के आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया. इस पर ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारियों ने सूची बनाकर भेज दी, लेकिन उत्तराखंड सरकार उसे दबाकर बैठ गई. ■

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सेना भर्ती के उप-महानिदेशक ब्रिगेडियर एमडी चाको की यह आधिकारिक शिकायत काफी गंभीर है. ब्रिगेडियर चाको ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सेना भर्ती में पूरी तरह असहयोग बरतने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों झांसी ज़िला प्रशासन ने भर्ती की पूर्व घोषित तारीख से एक दिन पहले भर्ती कार्यक्रम रद्द करने का एकतरफ़ा फ़ैसला सुना दिया, जिससे अफरातफरी मच गई.

प्रसारित की जाती हैं, ताकि विभिन्न इलाकों से बच्चे भर्ती के लिए उस स्थान पर आएं. उन प्रसारित सूचनाओं पर अलग-अलग इलाकों से बच्चे आते हैं, लेकिन आने पर पता चलता है कि प्रशासन ने भर्ती का कार्यक्रम रद्द कर दिया है. भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहने वाले सेनाधिकारियों और अन्य सैन्य कर्मियों को भी प्रशासन के फ़ैसले का पता बाद में चलता है. सेना के भर्ती कार्यक्रम सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय की अनुमति और सहमति लेकर तय किए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सेना के इस काम की गंभीरता को समझती ही नहीं. इससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी आम लोगों की निगाह में गिर रही है. हालत यह है कि सेना के इन कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण इसमें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. ब्रिगेडियर चाको ने कहा है कि वाराणसी में भी भर्ती रैली की अनुमति पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद मिल सकी. रायबरेली के ज़िलाधिकारी ने तो उनके जनपद के अलावा दूसरे ज़िलों की भर्ती कोटा किसी अन्य राज्य को दे दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है. सेना के पत्र का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को 10 जनवरी तक दे देना था, लेकिन तब तक सरकार की तरफ़ से कोई जवाब नहीं आया था. इस बारे में सेना का आधिकारिक पक्ष जानने के लिए जब थलसेना के मध्य कमान मुख्यालय की जनसंपर्क अधिकारी गार्गी मलिक सिन्हा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सेना के पत्र के जवाब में राज्य सरकार ने क्या लिखा है और लिखा भी है कि नहीं, इसका उन्हें पता नहीं है. वह शहर के बाहर हैं और आने पर इस बारे में कुछ बता पाएंगी. सेना की पीआरओ ने इतना ज़रूर कहा कि राज्य सरकार के असहयोग के मद्देनज़र सेना भर्ती के कार्यक्रमों पर कोई निर्णायक फ़ैसला सेना मुख्यालय ही ले सकता है. मध्य कमान मुख्यालय राज्य सरकार का जवाब सेना मुख्यालय को भेज देगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

मांझी की कुर्सी पर ख़तरा बरकरार

सुकांत

चुनावी वर्ष की शुरुआत बिहार ने कयासों की उत्तेजक राजनीति से की है. अख़बारी पाठकों को सर्दी के दिन गर्म रखने के लिए खूब खुराक मिल रही है, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के किसी भी घड़ी सलीब पर टंग जाने की आशंका की खुराक. हालांकि, यह राजनीतिक सरगर्मी पिछले कई महीनों से बनी है, लेकिन हाल में इसमें तेजी आई है. राज–नेताओं के साथ–साथ बिहारी मीडिया भी उल्लेखनीय तौर पर काफी सक्रिय रहा. पर, इस राजनीतिक अभियान को सफलता नहीं मिली. कहते हैं, जद (यू) और राजद के प्रमुख क्रमश: नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद ने ऐसे किसी अभियान को चुनावी हित के प्रतिकूल मानते हुए इसके प्रमोटरों को शांत रहने की नसीहत दी है. लेकिन, मांझी के लिए यह तात्कालिक राहत के समान है. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मांझी की विदाई का वक्त तो मुकर्रर कर रखा है, पर इसमें अभी देर है. ऐसा माना जा रहा है कि जनता परिवार के विलय के बाद संगठन और सरकार (दोनों फ्रंट) को लेकर नए सिरे से विचार किया जाना है. उस हालत में नेतृत्व में बदलाव तय माना जा रहा है. यानी मांझी के सिर से तलवार हटी नहीं है, पर उसकी डोर अब नेतृत्व में बदलाव के पैरोकारों के बदले लालू–नीतीश के हाथों में चली गई है. अब राज्य के राजनीतिक समूहों को इस बात की प्रतीक्षा है कि जनता परिवार का विलय कब होता है और तब तक मांझी मुख्यमंत्री रहते हैं या नहीं. यह बात सही है कि मांझी को जीवनदान लालू–नीतीश के कारण मिला है, पर सच्चाई यह भी है कि अपनी प्रशासनिक अक्षमताओं एवं अटपटे बोल के कारण वह राजनीतिक तौर पर किसी को रास नहीं आ रहे हैं, नीतीश–लालू को तो नहीं ही, भाजपा को भी नहीं.

जीतन राम मांझी अपने अंदाज़ में सरकार चला रहे हैं और उनकी शासन शैली में सुशासन सबसे अधिक संकट में फंस गया है. चूंकि नीतीश कुमार के वह सीधे उत्तराधिकारी ही नहीं, उनके द्वारा मनोनीत भी हैं, लिहाजा उनके कामकाज के अच्छे–बुरे के आकलन का पैमाना नीतीश–राज की शासन शैली ही है. इस ख्याल से बिहार के हालात संतोषजनक तो कतई नहीं हैं. नाउम्मीदी के लंबे दौर के बाद कोई नौ साल पहले सत्ता पर नए सिरे से बिहारियों का भरोसा जगा था और राज्य में आम तौर पर क़ानून का भय दिखने लगा था. हालांकि, उस दौर में भी काली दुनिया के अनेक सरगनाओं को सत्ता के खास जैसी सहूलियतें मिली थीं और शासन का यह आचरण कभी–कभी भय (आतंक कहिए) पैदा करता था, पर आम तौर पर जीवन सहज होता दिख रहा था. लेकिन, गत कुछ महीनों से हालात बदलने लगे और अब राज्य में क़ानून व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर जाती दिख रही है. इस मुतल्लिक आंकड़ों की जुबान में बातचीत कठिन है और सरकार एवं सत्तारूढ़ दल के अपने तर्क हैं, अन्य राज्यों के आंकड़े हैं. साथ ही वे सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार कर अपने नेता को सेंसर नहीं करना नहीं चाहते. पर, यह ज़रूर मानते हैं कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. आपराधिक गिरोहों की संगठित–सुनियोजित काली करतूतों के आतंक का दायरा बढ़ता जा रहा है. पटना से लेकर सुदूर ग्रामांचल तक नए–नए अंदाज़ में उक्त गिरोह अपना काम अंजाम दे रहे हैं. पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती दिखना भर चाहती है. कारण, उसकी कार्रवाई का कोई विशिष्ट परिणाम सामने आता नहीं. क़ानून के राज की ज़िम्मेदार एजेंसियां अपना इकबाल खोती जा रही हैं. यही नीतीश की चिंता का कारण है. चुनाव के ठीक पहले राज्य का ऐसा माहौल किसी सत्ताधारी राजनीतिक दल की वापसी की राह का सबसे ख़तरनाक रोड़ा है. फिर, जद (यू) के बागी विधायकों को लेकर संगठन और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद का इस कदर सार्वजनिक होना भी पार्टी नेतृत्व में समन्वय के घोर अभाव का परिचायक है. यह सही है कि बागी विधायकों की सदस्यता ख़त्म कराने को लेकर मांझी से कोई राय–मशविरा नहीं किया गया था और संकेतों में अपनी उपेक्षा वह जाहिर कर चुके हैं. राज्य की चुनावी राजनीति का तकाजा है कि यह नुक्ताचीनी अब ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन हालात विपरीत हैं और आने वाले महीनों में इस या ऐसी प्रवृत्ति के बढ़ते जाने की आशंका है. यह जद (यू) के चुनावी भविष्य को दांव पर चढ़ा रहा है. मांझी के बार–बार के अट–पट बोल प्रशासन में सामाजिक समूहों के बीच नई गोलबंदी का कारण बन रहे हैं. ऐसा प्रशासनिक माहौल दो–ढाई दशक पहले के हालात की याद दिलाता है. नीतीश–राज, विशेषकर एनडीए के जमाने में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने का बड़ा शोर था. उन दिनों सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा दिखता भी था, पर गत कई महीनों में (एनडीए सरकार के विघटन के बाद से) इस फ्रंट पर सरकार की सक्रियता सीमित हो गई है. कुछ महीने पहले तक जब–जब पुलिस का चेहरा दागदार दिखने लगता था, तब–तब ऐसी कार्रवाई होती रही, पर अब तो ऐसी तात्कालिक गतिविधि भी बंद है. प्रशासन के ऊंचे हलकों में लेन–देन की चर्चा पटना की सड़कों पर होने लगी है. नीतीश–राज, जिस पर जद (यू) को नाज़ है, का चेहरा भी आज बिहार को दागदार दिखने लगा है.

जीतन राम मांझी अपने अंदाज़ में सरकार चला रहे हैं और उनकी शासन शैली में सुशासन सबसे अधिक संकट में फंस गया है. चूंकि नीतीश कुमार के वह सीधे उत्तराधिकारी ही नहीं, उनके द्वारा मनोनीत भी हैं, लिहाजा उनके कामकाज के अच्छे-बुरे के आकलन का पैमाना नीतीश-राज की शासन शैली ही है. इस ख्याल से बिहार के हालात संतोषजनक तो कतई नहीं हैं. नाउम्मीदी के लंबे दौर के बाद कोई नौ साल पहले सत्ता पर नए सिरे से बिहारियों का भरोसा जगा था और राज्य में आम तौर पर क़ानून का भय दिखने लगा था.

फिर भी, आज के जीतन राम मांझी विधानसभा चुनाव में नीतीश की राजनीतिक पूंजी बनने की हरचंद ताकत रखते हैं. यह सही है कि गत मई में लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद नीतीश ने बैक बेंचर समझ कर ही मांझी को अपना भरत बनाया था और उन्हें अपनी खड़ाऊं सौंपते हुए 2015 के विधानसभा चुनाव तक उसे संभाले रहने का वचन लिया था, लेकिन कुछ ही महीनों में भरत ने मोम का पुतला बनने से इंकार कर दिया. शुरू के कुछ महीनों के रिमोट संचालित सरकार के प्रभारी मुख्यमंत्री मांझी अपने खास लोगों तक को सरकारी समितियों में शामिल कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे. पर, चार–पांच महीने में ही उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की और अब वह नीतीश भक्त अफसरों को न केवल शंटिंग पदों पर भेज रहे हैं, बल्कि मंत्रि परिषद के नीतीश भक्तों को भी जता रहे हैं कि मंत्रियों को बर्खास्त करने की ताकत तो उनके पास है ही. वह अपनी रौ में सब कुछ कर रहे हैं और कई मसलों पर जद (यू) की राजनीतिक धारा के विपरीत लाइन लेते हैं. उनकी स्वाभाविक दलितोन्मुखी राजनीति जद (यू) को ही नहीं, लालू प्रसाद के सामाजिक आधार को भी बार–बार उत्तेजित कर रही है. जद (यू) जिस सामाजिक समूह को अपना वोट बैंक के तौर पर पेश कर रहा है, वह वस्तुत: मांझी के साथ है और इसके अलावा उसकी वोट की पूंजी बड़ी सीमित है. लालू प्रसाद के पास गत कई चुनावों से यादव–मुसलमान की पूंजी है, लेकिन उसमें भी संसदीय चुनाव में भारी क्षरण हुआ है और ग़ैर यादव उम्मीदवारों को यादव वोट दिलवाने में वह कई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विफल रहे. अब मांझी के साथ कोई बैर–भाव लेकर अपनी चुनावी विफलता पर एक बार फिर वह मुहर नहीं लगवाना चाहते. ऐसे में मंडल राजनीति के इन दोनों बिहारी नायकों की राजनीतिक विवशता बन गए हैं मांझी. यह सच्चाई है कि मांझी के चलते बिहार के महादलित समाज में नई चेतना विकसित हो रही है और वह नई चुनौतियों का सामना करने की मानसिक तैयारी कर रहा है. लेकिन, यह भी सही है कि यह सारा कुछ मांझी के साथ ही है, जद (यू) के साथ नहीं. नीतीश कुमार और उनके समर्थक राजनीतिक–सामाजिक समूहों को यह वास्तविकता पच नहीं रही है. यही कारण है कि मांझी निरंतर मजबूत होते जा रहे हैं, दृढ़ता से अपनी बात कह रहे हैं, जिससे सरकार से जुड़े बिचौलियों की, जिनमें मंत्रियों की संख्या कम नहीं है, परेशानी बढ़ गई है. मांझी हटाओ अभियान में इन बिचौलियों की भूमिका किसी अन्य राजनीतिक समूह से अधिक है. लेकिन, कुछ तो ऐसी मजबूरी है कि जद (यू) में सुप्रीमो की हैसियत पा चुके नीतीश कुमार खामोश हैं. उनकी यह खामोशी कुछ तो क़ीमत वसूल करेगी. पर क्या? इस क्या का उत्तर भविष्य देगा.

इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक राजनीतिक बेचैनी भाजपा में है. बिहार का मतदाता समूह गहरी वोटबंदी का नमूना बन गया है. अगड़ा मतदाता भाजपा की ओर प्रतिबद्ध दिखता है, मगर पिछड़े मतदाताओं में विभाजन है और दलित–महादलित एवं अति पिछड़ा मतदाता समूह प्राय: अति–प्रतिबद्ध ही है. राजद–जद (यू) की एकता या जनता परिवार के विलय के बाद निर्विवाद रूप से यह तीसरा अप्रतिबद्ध मतदाता समूह काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा. सत्ता के दरवाजे तक किसी भी राजनीतिक समूह को पहुंचाने के लिए इस समूह का वोट ज़रूरी हो जाएगा. भाजपा के साथ मजबूरी है कि उसके पास बड़े दलित–महादलित और अति पिछड़े नेता का अभाव है. इसके साथ यह यथार्थ है कि हाल के महीनों में मांझी दलित–महादलित के साथ–साथ अति पिछड़ों में एक नए राजनीतिक ध्रुव बनकर उभरे हैं. इन सामाजिक समूहों की मतदान–शैली को प्रभावित करने की उनकी ताकत दिखने लगी है. अभी तक उनके इस उत्थान का राजनीतिक लाभ जनता परिवार या ऐसे भाजपा विरोधी किसी गठबंधन को मिलता दिख रहा है. बिहार की मौजूदा सरकार के सत्ता के बिचौलिए जब तक अपने अभियान को अंजाम तक नहीं पहुंचाते, मांझी के मुख्यमंत्री होने का लाभ नीतीश–लालू को मिलना तय है. भाजपा इस समीकरण को बदला हुआ देखने को बेचैन है. देखना है, भाजपा को कब चैन मिलता है, मिलता भी है या नहीं.■

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस के चिंतन शिविर में छाए रहे मोदी और शाह

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड

कांग्रेस के सामने दूसरा संकट यह भी है कि 2017 में पीडीएफ के कब्जे वाले सात विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं और पिछले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को वह किस आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करे. जानकारों का कहना है कि इसी वजह से पार्टी नेतृत्व पीडीएफ विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में था. लेकिन, कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के कांग्रेस में शामिल होने से उनकी विधायकी जाने की आशंका के चलते पार्टी की इस कोशिश को भी पलीता लग चुका है.

प्रदेश की राजधानी देहरादून में दो दिनों तक चले कांग्रेस के चिंतन शिविर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आक्रामता का भय पूरी तरह छाया रहा. कांग्रेस के दिग्गज नेता पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री हरीश रावत को कमजोर करने की कोशिश करते दिखे. उन्होंने अंतिम दिन कड़ा रुख अपनाते हुए साफ़ कहा कि कांग्रेस छोटे दलों के साथ रहने की अपनी नीति पर कायम रहेगी. हरीश के उक्त बयान ने पीडीएफ के सरकार में बने रहने की बात साफ़ करने के साथ ही विरोधियों की हवा निकाल दी. पीडीएफ को सरकार से बाहर करने और दायित्व बांटने की आवाज़ों से घिरे मुख्यमंत्री रावत आख़िरी दिन बैकफुट से फ्रंटफुट पर आ गए और अपने स्वभाव के अनुसार मोर्चा संभालते हुए नीतिगत बात कहकर सबकी बोलती बंद कर दी.

मंथन शिविर की शुरुआत में एजेंडा सामने रखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि देश में इस वक्त राजनीतिक शक्ति की सरकार है, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है. कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है, गांधी की विचारधारा से मुक्त भारत, जो किसी क़ीमत पर स्वीकार नहीं हो सकता. काबीना मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश ने सोशल मीडिया में प्रचार में भाजपा से पिछड़ जाने पर अफ़सोस जताया. उन्होंने मध्य वर्ग को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए सोशल मीडिया पर पार्टी की विचारधारा और नीतियों के प्रचार की ज़रूरत बताई. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ के नेताओं का कहना था कि पार्टी इस वर्ग पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि यह कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है. उपेक्षा की वजह से ही यह वर्ग लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में चला गया. देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित उक्त मंथन शिविर में गढ़वाल मंडल के विभिन्न ज़िलों के छह समूहों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी, हरीश रावत, किशोर उपाध्याय और सह प्रभारी संजय कपूर के सामने अपने विचार रखे.

चर्चित कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि पीडीएफ को लेकर फ़ैसला लेने का यह सही वक्त है. मंथन शिविर के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह टिहरी ज़िले के प्रभारी मंत्री भी हैं. टिहरी से पीडीएफ कोटे के दो मंत्री हैं. उन्हें पता है कि उनके साथ समन्वय स्थापित करने में कितनी दिक्कत आती है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे कितने संतुष्ट हैं. विधायक गणेश गोदियाल ने भी पीडीएफ विरोधियों के सुर में सुर मिलाया. वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य द्वारा देहरादून में मौजूद होने के बावजूद चिंतन शिविर में हिस्सा न लेना चर्चा का विषय बना रहा. मुख्यमंत्री रावत पीडीएफ के साथ मजबूती से खड़े नज़र आए. उन्होंने पीडीएफ के मंत्रियों के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं. पीडीएफ का साथ छोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता. मंथन शिविर से पहले मीडिया से बातचीत में अंबिका सोनी ने कहा कि पीडीएफ को लेकर फ़ैसला सरकार और प्रदेश संगठन यानी हरीश रावत और किशोर उपाध्याय को करना है. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री रावत का कहना है कि पीडीएफ ने ज़रूरत के वक्त कांग्रेस की मदद की थी. हालांकि, वह यह भी कह चुके हैं कि पीडीएफ को लेकर कांग्रेस आलाकमान ही फ़ैसला लेगा. दरअसल, कांग्रेस के सामने इस समय भरोसे का संकट है. यदि कांग्रेस पीडीएफ से अपना पल्ला छुड़ाती है, तो उस पर यह आरोप लगाना आसान होगा कि वह विश्वास के काबिल नहीं है. राजनीति में वैसे भी विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी होती है. यदि उसने पीडीएफ को छोड़ा, तो भविष्य में होने वाले चुनावों में फिर से समर्थन लेने के हालात पैदा होने पर छोटे दल अथवा निर्दलीय शायद ही उस पर भरोसा कर सकेंगे. कांग्रेस के सामने दूसरा संकट यह भी है कि 2017 में पीडीएफ के कब्जे वाले सात विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं और पिछले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को वह किस आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करे. जानकारों का कहना है कि इसी वजह से पार्टी नेतृत्व पीडीएफ विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में था. लेकिन, कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के कांग्रेस में शामिल होने से उनकी विधायकी जाने की आशंका के चलते पार्टी की इस कोशिश को भी पलीता लग चुका है. लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बह जाने के बाद कांग्रेस ने खुद के ऊपर मंडरा रहे संकट को पहचान तो लिया है, लेकिन उससे निजात पाने के उपाय वह फिलहाल ढूंढ नहीं पा रही है.

उधर, कांग्रेस के 15 विधायकों ने एक बार फिर सरकार के ख़िलाफ़ अपनी ताकत दिखाई है. पीडीएफ विधायक सरवर करीम अंसारी से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र की प्रति प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी को सौंपी गई. पत्र में बहुगुणा समर्थकों के अलावा कुछ अन्य विधायकों के भी हस्ताक्षर हैं. उक्त पत्र में विधायक अंसारी के ख़िलाफ़ मीडिया में आए स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा की गई है, जिसमें उन्हें रिश्वत लेते हुए दिखाया गया. पत्र में इसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि इससे कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है. यह पत्र वरिष्ठ विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने अंबिका सोनी तक पहुंचाया.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भाजपा का दीवालियापन

आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाज़िया इल्मी भी भाजपा में शामिल हो गई हैं. समाजवादी पार्टी से जुड़ी रहीं जयाप्रदा भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं. जैसा कि कहा जाता है कि मधुमक्खियां वहीं जमा होती हैं, जहां शहद होता है. इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं हूं क्योंकि इन लोगों ने कभी अपनी विचारधारा ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि केजरीवाल के साथ जाने का सीधा अर्थ है कि आप साफ़-सुथरी राजनीति चाहते हैं, आप पानी और बिजली के दाम कम करना चाहते हैं. आप वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी हैं, आप सांप्रदायिक हैं या सेकुलर, कोई अपनी विचारधारा नहीं बताता.

अचानक से भाजपा में शामिल होने वालों की भीड़ उमड़ गई है. ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि फिलहाल वो सत्ता में है और अगले पांच साल सत्ता मे बनी रहेगी. लोग विचारधारा के बारे में विचार किये बगैर राजनीति में अपने पैर जमाना चाहते हैं. ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहां जायेंगे, जहां उन्हें कोई पद या सत्ता का लाभ मिलेगा. किरण बेदी हमेशा से दिल्ली की पुलिस कमिश्नर बनना चाहती थीं, लेकिन उन्हें यह पद नहीं दिया गया. सिस्टम के प्रति इस निराशा की वजह से वह अन्ना हज़ारे के आंदोलन में शामिल हो गईं. इसके बाद आम आदमी पार्टी को फलने-फूलने में उन्होंने सहयोग किया. उन्होंने पिछला चुनाव नहीं लड़ा, इसकी वजह उनका स्वयं का निर्णय या उनके केजरीवाल के साथ मतभेद हो सकते हैं.

अचानक वह भाजपा में शामिल हो गईं, हालांकि इस संबंध में पिछले कुछ महीनों से अफवाहों का बाजार गर्म था कि वह इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसी अटकलें लगाई जा रहीं थी कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी. लेकिन भाजपा ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन मेरे जैसे सभी लोगों के लिए यह एक रहस्योद्घाटन होगा. किरण बेदी के लोकप्रिय होने की एक ही कहानी है. वह जब दिल्ली में डीसीपी (ट्रैफिक) के पद पर तैनात थीं, तब वह नो-पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठवा लेती थीं. उन्होंने यहां अच्छा काम किया इस वजह से उन्हें क्रेन बेदी नाम से जाना जाने लगा. इसके बाद उन्होंने ऐसा कोई शानदार काम नहीं किया. इसके विपरीत उनके द्वारा तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों पर कराये लाठी चार्ज की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति डी पी वाधवा कमेटी की जांच रिपोर्ट में उन पर गंभीर आरोप लगे. आम तौर पर जांच कमेटियां निरर्थक रिपोर्ट देती हैं, जिसमें आरोप ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं. लेकिन डी पी वाधवा कमेटी ने बेहतरीन काम किया और 65 पृष्ठ की अपनी जांच रिपोर्ट में तीन बातें साफ तौर पर कहीं, कि साल 1988 में एक वकील को चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया, यह ठीक था. लेकिन उसे हथकड़ी बांधकर ले जाना गैरक़ानूनी था, इसी वजह से दिल्ली बार एसोसिएशन हड़ताल पर चला गया. किरण बेदी ने आरोपी वकील के हाथों में हथकड़ी लगाई. रिपोर्ट में कहा गया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों के ऊपर तत्कालीन पुलिस उपायुक्त(उत्तर) किरण बेदी द्वारा घटना के एक सप्ताह बाद लाठी चार्ज कराना अनुचित और विवेकहीन था. उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया, उसके बाद सीढ़ियों पर फैले खून को पानी से साफ करवा दिया. यह बेहद निर्मम और क्रूर था. एक और बात जो जांच रिपोर्ट में कही गई कि बेदी निगम काउंसलर की मिलीभगत से उन लोगों की भीड़ तीस हजारी कोर्ट लाईं, जिनका वकीलों के साथ झगड़ा हुआ था. अब भी एक छोटा सा पुलिस अधिकारी जो रिश्वत लेता है, अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, इस हद तक नहीं जा सकता है.

यह एक अजीब तरह की पुलिस कार्रवाई है, जहां मदद करने अथवा कड़ी कार्रवाई करने की जगह उपद्रवियों को प्रोत्साहित किया गया. यह न ही लोकतंत्र है और न ही पुलिस प्रशासन है, यह भीड़तंत्र है. यहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भीड़तंत्र को प्रोत्साहित करने का काम किया और वह किरण बेदी हैं. उनके पुलिस में होने की वजह से सीबीआई रिपोर्ट वकीलों के विरोध में दायर की गई, पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई. यदि कभी कोई कार्रवाई की भी गई तो वह छोटे अधिकारियों के ख़िलाफ की गई, न कि किरण बेदी के ख़िलाफ. यदि उनके ख़िलाफ कोई कार्रवाई की गई होती तो उन्हें पुलिस सेवा से बर्ख़ास्त कर दिया गया होता और अपमान का सामना करना पड़ता. उन्होंने अपनी राजनीतिक पहुंच का लाभ उठाते हुये अपने रिटायरमेंट या वॉलेंटरी रिटायरमेंट तक स्वयं को बचाये रखा. यह हास्यास्पद है कि सभी ने इस वाकये को बहुत जल्द भुला दिया. जब वह टीवी परिचर्चा में शामिल होती थीं, तब वह उन्हीं नेताओं को, प्रशासन को भला-बुरा कहती थीं जिनका लाभ वह अपने पूरे करियर के दौरान उठाती रहीं. उनकी जो छवि बनी है, वह वास्तविक नहीं है. यह उनकी गढ़ी गई छवि है, जो टीवी पर दिखाई जाती है. उनका पुलिस अधिकारी के रूप में करियर रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें एक बेहतरीन पुलिस अफसर का खिताब दिया जा सके.

> साल 1988 में एक वकील को चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया, यह ठीक था. लेकिन उसे हथकड़ी बांधकर ले जाना गैरक़ानूनी था, इसी वजह से दिल्ली बार एसोसिएशन हड़ताल पर चला गया. किरण बेदी ने आरोपी वकील के हाथों में हथकड़ी लगाई. रिपोर्ट में कहा गया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों के ऊपर तत्कालीन पुलिस उपायुक्त(उत्तर) किरण बेदी द्वारा घटना के एक सप्ताह बाद लाठी चार्ज कराना अनुचित और विवेकहीन था.

अब भाजपा अपने विवेक के आधार पर उनका चुनाव कर रही है. यदि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करती है तो इससे उसका दीवालियापन ही ज़ाहिर होगा. इस सीधा सा मतलब यह है कि इतने सालों तक दिल्ली में काम करने के बावजूद, वह एक ऐसा नेता नहीं बना सकी जो उसके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सके. वह पार्टी में हाल ही में शामिल हुए एक व्यक्ति को यह पद देना चाहते हैं. यह भाजपा की वास्तविक सोच को दर्शाता है कि वह पार्टी के फासीवादी रवैये को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल सही शख्सियत हैं. यदि वकीलों पर लाठीचार्ज हो सकता है तो आम जनता के साथ ऐसा कभी भी हो सकता है, उसकी क्या हैसियत है? यदि भाजपा ताकत से सत्ता चलाना चाहती है तो किरण बेदी इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त साबित होंगी. यह वाकई एक रहस्योद्घाटन है कि अन्ना हजारे और केजरीवाल के राजनीति में प्रवेश के बाद वह भी राजनीतिक मैदान में कदम रख चुकी हैं. लेकिन उनका एजेंडा क्या है?

पहला काम जो एक सरकार को करना चाहिए वह यह है कि डी पी वाधवा कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग करे, क्योंकि तीस हजारी दिल्ली सरकार के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आता है. एक बड़ी घटना 1988 में घटी थी लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. अब किरण बेदी से इस घटना पर कार्रवाई करेंगी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं. मैं नहीं जानता कि दूसरे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं. सबको एकजुट होकर वाधवा कमेटी की रिपोर्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए. यदि ऐसा होता है तो किरण बेदी किसी भी पद पर बने रहने की अर्हता खो देंगी.

आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाज़िया इल्मी भी भाजपा में शामिल हो गई हैं. समाजवादी पार्टी से जुड़ी रहीं जयाप्रदा भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं. जैसा कि कहा जाता है कि मधुमक्खियां वहीं जमा होती हैं, जहां शहद होता है. इसलिए मैं इससे बहुत ज्यादा अचंभित नहीं हूं क्योंकि इन लोगों ने कभी अपनी विचारधारा ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि केजरीवाल के साथ जाने का सीधा अर्थ है कि आप साफ-सुथरी राजनीति चाहते हैं, आप पानी और बिजली के दाम कम करना चाहते हैं. आप वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी हैं, आप सांप्रदायिक हैं या सेकुलर, कोई अपनी विचारधारा नहीं बताता. इसलिए सुविधाजनक तरीके से वे किसी भी विचारधारा को अपना लेते हैं. जयाप्रदा वास्तव में एक सेकुलर पार्टी के साथ थीं, अब उन्हें अपने अचानक हुए हृदय परिवर्तन को स्पष्ट करना होगा. राजनेता दल बदलने के लिए अच्छे बहाने ढूंढ लेते हैं. अंततः वह भी कोई न कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेंगी.

अब किरण बेदी के मसले पर वापस आते हैं, भाजपा को गंभीरता से विचार करके पार्टी के अंदर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किसी उपयुक्त नेता का चुनाव करना चाहिए. भाजपा में सुषमा स्वराज से लेकर हर्षवर्धन तक कई ऐसे लोग हैं जो समय-समय पर दिल्ली की राजनीति से जुड़े रहे हैं. वे भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं. ऐसे लोगों के बजाये किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना यह साबित करता है कि आठ महीने बाद ही भाजपा भी आसान विकल्प चुनने के लिए बाध्य हो गई है. मुझे आशा है कि उन्हें इस निर्णय के लिए सद्बुद्धि मिले. ■

feedback@chauthiduniya.com

जेपी की मौत ने देश को झकझोर दिया था

जेपी पुन: जीप में बैठे. पीछे विशाल जुलूस डाक बंगला चौराहे से रेवेन्यू बिल्डिंग की ओर मुड़ा. पुलिस का तीसरा मोर्चा थाने के सामने था. आगे के लोगों को पुलिस ने रोक दिया. तब तक जेपी की जीप आई, जेपी ने इशारा किया और लोग लकड़ी की बल्लियों के अवरोध को तोड़ते हुए आगे बढ़ आए. रेवेन्यू बिल्डिंग से पहले पुलिया पर पुलिस ने अपना सबसे मजबूत मोर्चा लगाया. वहां संक्षिप्त चेतावनी के बाद लाठीचार्ज कर दिया गया. आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे. एक गोला जेपी की जीप के नीचे गिरा. रेणु जेपी के साथ थे. जेपी जीप से उतरे और आगे बढ़े. पुलिस वालों ने उन पर लाठी से प्रहार किया, वह गिर पड़े. इधर लाठीचार्ज तथा आंसू गैस से जुलूस तितर-बितर हो रहा था. जेपी उठे, कुछ क़दम चले, फिर बैठकर सुस्ताने लगे. शिवानंद, हैदर अली आदि लोगों को चोटें आई थीं. रामचंद्र राही की पीठ पर तो बेतों के दर्जनों प्रहार किए गए थे. एक साधारण औरत ने पुलिस के लाठी के प्रहारों को झेलते नौजवानों को देखकर कहा, काश! मैं इन सबको अपनी कोख में छिपा लेती.

जेपी आगे बढ़े और फिर उनके साथ बढ़ा जुलूस का एक हिस्सा. दारोगा राय के घर के सामने धरना देकर सभी लोग बैठ गए. शाम को पुलिस ने सबको पकड़ना शुरू किया, तो जेपी ने कहा, मुझे भी पकड़ें. जब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वह खुद पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए. पुलिस की गाड़ी जेपी को लेकर क़दमकुआं छोड़ गई. जेपी नौ बजे तक उसमें ही बैठे रहे तथा बाद में यह घोषणा कर उतरे कि अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा. उन दिनों आंदोलन से जुड़े हर आदमी का ध्यान जेपी खुद रखते थे. उनके पास कोई भी आसानी से जा सकता था. खुद भी काफी घूमते थे. इसी बीच आपातकाल लग गया. जब यह समाचार आया कि जेपी को सरकार ने छोड़ दिया है, तो जो कुछ लोग सबसे पहले पहुंचे थे, उनमें से मैं भी एक था. हम लोगों के ग्रुप में सबको देखकर जेपी बेहद खुश हुए थे. बंबई की त्रासदी भरे वे दिन थे. देश का हर आदमी प्रार्थना कर रहा था कि जेपी स्वस्थ हो जाएं. लेकिन जेपी बस बीमार ही रहे और सबसे बाहर के समाचार ही लेते थे.

आपातकाल में जेपी अधिकांश समय बंबई में ही थे. वहां उनसे मिलने सर्वोदय कार्यकर्ताओं के अलावा पेरोल पर छूटे लोग आते थे. जेपी की जिस दिन डायलिसिस नहीं होती, आराम करते थे तथा बाद में कहीं घूमने चले जाते थे. लोग उन्हें देखकर, पहचानते हुए भी पास आने से हिचकते थे. प्रसिद्ध अभिनेता अमोल पालेकर ने एक दिन कहा कि वह जेपी को बादल सरकार का नाटक जुलूस सुनाना चाहते हैं. जुलूस को अमोल ने बंबई में अपने निर्देशन में सौ से ज़्यादा जगहों पर दर्शाया था. अमोल अंबेडकर जयंती के बाद जेपी के पास अपनी पत्नी अनूया पालेकर के साथ गए. जेपी काफी देर से व्यस्त थे. उनकी बहू ने जेपी से काफी तारीफ़ कर डाली थी अमोल की. अमोल को देखते ही जेपी ने पूछा कि लगते तो आप युवक हैं, लेकिन आप प्रसिद्ध भी काफी हो गए हैं. अमोल कुछ सकुचा गए. बाद में उन्होंने जेपी को नाटक की विषय-वस्तु समझाई. जेपी काफी प्रभावित हुए तथा उन्होंने अमोल से वादा किया कि वह ज़रूर कभी चुपचाप उनका यह नाटक देख आएंगे.

> आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह कर ना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

जो सर्वोदयी इंदिरा की वकालत करते थे, उन्होंने जार्ज फर्नांडिस के विरुद्ध एक अभियान चला रखा था, जिसमें नाना गणेश गोरे भी प्रमुख थे. इन सबका कहना था कि जेपी यदि जार्ज को डिसओन कर दें, तो इंदिरा जी का मूड कुछ ठीक हो सकता है. जेपी सूनी आंखों से सब सुन रहे थे. केवल सच्चिदा बाबू ही जार्ज की वकालत कर रहे थे. एक बार मैं गया, तो जेपी बोल उठे, पता नहीं क्या हो रहा है? ब्रह्मानंद ने जेपी से कहा कि जार्ज वही कर रहे हैं, जो आप 42 में कर चुके हैं. जेपी ने अपनी पहली सभा में, 30 जनवरी, 77 को गांधी मैदान में विशाल जनसमूह के सामने कहा था, मित्रो, अगर जनता पार्टी के लोग भी ऐसा ही करेंगे (जैसा इंदिरा कांग्रेस ने किया), तो जयप्रकाश जीवित नहीं रहेगा. सचमुच जेपी चले गए. उनकी मौत की ज़िम्मेदारी तो कोई किसी पर नहीं डालेगा, लेकिन उनकी मानसिक अशांति की ज़िम्मेदारी तो लोगों को लेनी ही होगी.

जनता सरकार बनने के एक साल के अंदर ही जेपी को लगने लगा था कि चाल कहीं ग़लत पड़ गई है. प्रधानमंत्री से उनका विरोध समय-समय पर प्रकट हो जाता था. जेपी को भरोसा था कि मोरारजी भाई जेल में रहे हैं, इसलिए अवश्य बदल गए होंगे. पर उनकी आशा बेकार चली गई. जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के एक वर्ष बाद मैं पटना गया था. जेपी से खुलकर झगड़ने की इच्छा थी. रविवार के संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था कि कलकत्ता से वह भी आएंगे. हम दोनों जेपी के पास गए. जेपी ने इससे पहले किसी को इंटरव्यू टेप करने नहीं दिया था. उनके सचिव साक्षात्कार लेने ही नहीं दे रहे थे. मैंने जेपी से कहा कि टेप करूंगा, तो वह बोले, करो. सच्चिदा बाबू को जेपी ने रोक दिया था तथा जब बोलना शुरू किया, तो अपनी सारी व्यथा उड़ेल दी. उनके कमरे की छत पर काम चल रहा था, ठक-ठक की आवाज़ आ रही थी. जेपी ने उसे बंद कराया कि इससे टेप होने में बाधा पड़ेगी. जेपी ने अपने इंटरव्यू में जो कठोर भाषा इस्तेमाल की है, अब वह इतिहास की प्रामाणिक निधि बन गई है. यद्यपि बाद में कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने आग्रह किया कि शब्द कुछ हल्के कर दिए जाएं. और इंटरव्यू छापते समय वैसा ही किया गया, लेकिन मोरारजी भाई उतना भी नहीं सह सके.

> आपातकाल में जेपी अधिकांश समय बंबई में ही थे. वहां उनसे मिलने सर्वोदय कार्यकर्ताओं के अलावा पेरोल पर छूटे लोग आते थे. जेपी की जिस दिन डायलिसिस नहीं होती, आराम करते थे तथा बाद में कहीं घूमने चले जाते थे. लोग उन्हें देखकर, पहचानते हुए भी पास आने से हिचकते थे. प्रसिद्ध अभिनेता अमोल पालेकर ने एक दिन कहा कि वह जेपी को बादल सरकार का नाटक जुलूस सुनाना चाहते हैं. जुलूस को अमोल ने बंबई में अपने निर्देशन में सौ से ज़्यादा जगहों पर दर्शाया था.

अभी जब मैं जेपी से मिलने आया था, तो काफी बातें की थीं उन्होंने. मैंने टेप नहीं किया था. जब उनके सचिव सच्चिदा बाबू से कहा कि जेपी से सामान्य, लेकिन आम जनता से संबंधित बातें करूंगा, तो सच्चिदा बाबू ने रोक दिया. कहा, आप कर लेंगे, तो हम लोग दूसरों को नहीं रोक पाएंगे. मैंने फिर कहा कि राजनीतिक दलों के बारे में बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन्हें समझा नहीं सका. यदि वह बातचीत औपचारिक ढंग से हो जाती, तो संभव था कि जेपी का चिंतन सार्वजनिक रूप से प्रकट होता. सर्वोदय के राधाकृष्ण, नारायण देसाई आदि ने जेपी के पास आना बहुत कम कर दिया था, जबकि इन लोगों ने सारी ताकत जेपी से ही ली थी. जेपी को इसका बहुत दु:ख था. जेपी चले गए. उनका बहुत से लोगों से रिश्ता था, लेकिन अनाम लोगों से जो रिश्ता था, वही सही रिश्ता था. और, यही वजह है कि जेपी की मौत देश के एक साधारण आदमी के लिए कम गहरी नहीं है. हो सकता है कि उसने जेपी को क़रीब से देखा न हो, उनसे मिला न हो. **(14 अक्टूबर, 1979)** ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

संपादकीय

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आशा करें, आगामी बजट जनता का हो

बजट आने वाला है, बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पूर्व बैठकें भी शुरू कर चुके हैं. मानना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के रोडमैप का पहला बजट होगा. पिछले बजट में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या वित्त मंत्री अरुण जेटली को कुछ करने का मौक़ा नहीं मिला, क्योंकि उस समय वक्त ही नहीं था. इसलिए बजट की जो रूपरेखा पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने बनाई थी, उसी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में रखा था. वह बजट पूर्णतय: बाज़ार आधारित और दूसरे शब्दों में, विकास विरोधी बजट था.

जब हम विकास विरोधी कहते हैं, तो हमारा सीधा मतलब है कि वह बजट इस देश के 80 प्रतिशत लोगों के लिए नहीं था, बल्कि देश के 20 प्रतिशत संभ्रांत, सुसंस्कृत, उच्च शिक्षित, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लिए था. जब हम नरेंद्र मोदी के चुनाव के दौरान के भाषणों, फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया भर में उनके दिए भाषणों और पिछले चार महीने में देश में दिए भाषणों को पढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि शब्द विकास की अवधारणा सिर्फ़ 20 प्रतिशत के लिए नहीं है, बल्कि 100 प्रतिशत के लिए है और 100 प्रतिशत में सबसे पहले उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए, जिन्हें आज तक कभी हिस्सा मिला नहीं है. यह भाषा न साम्यवादियों की है और न समाजवादियों की, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यही भाषा चुनावों के दौरान बोली, प्रधानमंत्री बनने के बाद बोली है और अभी भी बोल रहे हैं.

नरेंद्र मोदी जब सबका साथ-सबका विकास की बात कहते हैं, तो इसका मतलब उनकी विकास की अवधारणा में वे सब हैं, जो वंचित हैं, जिन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है. इसलिए आशा करनी चाहिए कि यह बजट उनके लिए लाभदायक होगा, जिन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है. और, जिन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है, ऐसे लोग कम से कम 70 प्रतिशत तो हैं ही. ऐसे लोग देश के उन प्रांतों में ज़्यादा हैं, जहां पर नक्सलवाद अपना असर बढ़ाता जा रहा है. देखना यही है कि यह बजट नरेंद्र मोदी के सपनों का बजट होता है या फिर उनके अवचेतन मन के सपनों का. भारतीय अर्थतंत्र पर बाज़ार की ताकतों का भरपूर कब्जा हो सकता है और वे चाहेंगी कि बजट उनके मुताबिक बने, ताकि वे इस देश में किए गए पूंजी निवेश का पूरा फ़ायदा उठा सकें. लेकिन, जब नरेंद्र मोदी के भाषणों के आधार पर बजट में प्रावधान किए जाएंगे, तो बाज़ार की शक्तियों का सपना कैसे पूरा होगा और यहीं पर अंतर्विरोध खड़ा होता है. एक तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से उपजी हुई आशाएं हैं और दूसरी तरफ़ पूंजी द्वारा और क्रूरतापूर्वक लूटे जाने की आशंकाएं हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का शाब्दिक विवेचन करें, तो आशा पैदा होती है कि इस देश के किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, छात्रों के लिए और नौज़वानों के लिए यह बजट कारगर उपाय लेकर आएगा. जब हम किसानों की बात करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ़ यह नहीं होता कि किसानों को फसल की लागत से पचास प्रतिशत ज़्यादा मिले, बल्कि जो सीधे किसानी पर ज़िंदा रहने वाले लोग हैं, चाहे उनके पास ज़मीन हो या न हो, उन्हें रोज़गार मिले, यह आवश्यक है. और, यह रोज़गार तभी संभव हो सकता है, जबकि वहां स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले कच्चे माल के आधार पर उद्योगों की श्रृंखला लगाई जाए. जो उद्योग कृषि के आधार पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगें, उनके मुकाबले पूंजीपतियों को उद्योग लगाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए. अगर कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उद्योग नहीं लगाए जाते, तो यह मानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के भाषण लोगों को सपना दिखाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के काम लोगों के हाथों से रोज़गार छीनेंगे. यही चुनौती खुद नरेंद्र मोदी के सामने है और यही चुनौती उनके वित्त मंत्री के सामने है.

> हम न किसी की नीयत पर संदेह जता रहे हैं और न किसी के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं. हम तो सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने द्वारा किए गए वादों के आधार पर देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो उसे अपने क़दमों से यह बताना होगा कि उसके विकास का मतलब सिर्फ़ 20 प्रतिशत का विकास नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की अवधारणा में इस देश में रहने वाले 70 से 80 प्रतिशत लोग आते हैं, जो अब तक विकास की अवधारणा, विकास के मानचित्र और विकास की परिधि से बाहर रहे हैं.

> पानी ठंडा होता है, तो उसे गुनगुना होने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब वह गुनगुना हो जाता है, तो उसे गर्म होने और उबलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता. इस देश में 70 प्रतिशत लोगों के मन में अविश्वास के बादल किसी भी राजनीतिक दल को लेकर गहराने लगे हैं और उन्हें यह लगता है कि उनके हितों के प्रति कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, कोई संवेदना नहीं रखता. उनकी तकलीफ़ों से किसी का कोई सरोकार नहीं है.

हम न किसी की नीयत पर संदेह जता रहे हैं और न किसी के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं. हम तो सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने द्वारा किए गए वादों के आधार पर देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो उसे अपने क़दमों से यह बताना होगा कि उसके विकास का मतलब सिर्फ़ 20 प्रतिशत का विकास नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की अवधारणा में इस देश में रहने वाले 70 से 80 प्रतिशत लोग आते हैं, जो अब तक विकास की अवधारणा, विकास के मानचित्र और विकास की परिधि से बाहर रहे हैं.

मैं एक उदाहरण प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं कि जब पानी ठंडा होता है, तो उसे गुनगुना होने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब वह गुनगुना हो जाता है, तो उसे गर्म होने और उबलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता. इस देश में 70 प्रतिशत लोगों के मन में अविश्वास के बादल किसी भी राजनीतिक दल को लेकर गहराने लगे हैं और उन्हें यह लगता है कि उनके हितों के प्रति कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, कोई संवेदना नहीं रखता. उनकी तकलीफों से किसी का कोई सरोकार नहीं है. और, इस ख़तरनाक अवधारणा को बदलने की चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने है. इसलिए आने वाले बजट में आम लोगों के लिए क्या है और श्रीमंत वर्ग के लिए क्या है, यह देखना दिलचस्प होगा. मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह दूसरा बजट नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की पुख्ता राय बनाएगा और यह धारणा साख बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी.

मैं सिर्फ़ एक घटना की याद दिलाऊं. इतिहास में सर्वाधिक मतों से जीते हुए राजीव गांधी दो साल के अंदर ही अपनी साख खो बैठे थे. वह प्रधानमंत्री तो पांच साल तक रहे, लेकिन उनकी साख दो साल में ही समाप्त हो गई. यह ख़तरा कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने न पैदा हो जाए, यह सोचना और समझना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज़रूरी है और उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए भी ज़रूरी है. हम बजट की प्रतीक्षा बहुत आशाभरी निगाहों से कर रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

आधुनिकता से डरते हैं आतंकी

कट्टर इस्लाम स्वतंत्रता के लिए हर जगह ख़तरा बन गया है. यह इस्लामिक समाज को बर्बाद कर रहा है, जिसे हम पाकिस्तान में देख सकते हैं कि आख़िर कैसे अलकायदा वहां के लोगों को सता रहा है. यह संगठन आधुनिकता से डरता है, क्योंकि आधुनिकता आपको अपने हिसाब से सोचने और अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है. अलकायदा चाहता है कि सभी इस्लामिक देश मध्य युग में वापस लौट जाएं.

क्या पेरिस हमला शिक्षा, साक्षरता, अख़बार, कार्टून और दूसरी सृजनात्मक चीजों के बारे में था, जो कि धार्मिक उन्मादियों को बहुत ही ज़्यादा क्रोधित कर देती हैं. आख़िर इसमें बेइज्जती किसकी हुई थी? यह बेइज्जती निश्चित रूप से ईश्वर की नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की मानवीय भावनाओं को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है. क्या ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ़ धार्मिक उन्मादी इससे बेइज्जती महसूस करते हैं? क्या वे इस बात से दु:खी हैं कि बच्चियां स्कूल जा रही हैं और इसी वजह से मलाला को गोली मार दी गई? या फिर शायद उनके दिमाग में एक ऐसा घृणित विचार है, जो उन्हें को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि पेशावर के स्कूल में 132 बच्चों की हत्या कर दी जाए.

हमने पेरिस में क्रोध देखा. उसी तरह के कार्टूनों पर, जिन पर कुछ साल पहले डेनमार्क में बवाल हो चुका है. डेनमार्क में भी ऐसे कार्टून पर तुरंत विवाद नहीं हुआ था. उसमें थोड़ा समय लगा, जब तक कि उसे किसी ने राजनीतिक रंग नहीं दे दिया. और, आख़िर यह मामला क्या था? मामला यह था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता है. यह धारणा हाल में स्थापित की गई है, जबकि ऐसा कोई प्रतिबंध कुरान में नहीं है. कुरान में पैगंबर वही कहते हैं, जो उन्हें अल्लाह की तरफ़ से आदेश दिया जाता है. वहीं यहूदी धर्म में भी ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं बनाई जाती, लेकिन यह निषेधाज्ञा पैगंबर के लिए नहीं है. पैगंबर की मौत के कई शताब्दी बाद उनकी छवि के आधार पर सिक्के निकाले गए. लेकिन, यह बात जानता कौन है और कौन इस बात की चिंता करता है?

अगर लोग हर उस बात का बुरा मानने पर उतारू हो जाएं, जो उन्हें बुरी लगती है, तो वे तर्क नहीं करते. वे सिर्फ़ विध्वंस का रास्ता जानते हैं. कई बार यह विध्वंसक रूप सिर्फ़ उलझन पैदा करने के लिए होता है, जैसे कि बजरंग दल एमएफ हुसैन की चित्रकलाओं की प्रदर्शनी पर रोक लगाने की कोशिश करता रहा है. लेकिन, अलकायदा कोई भी काम आधे-अधूरे रूप में नहीं करता, वह लोगों की सीधे हत्याएं करता है. दरअसल, ये लोग ज्ञान, कला, खूबसूरती, संगीत और शब्दों से डरे हुए हैं. पश्चिम भी पहले ऐसे धार्मिक उन्माद से जूझ चुका है, जब स्पेन में जियोरडानो बर्नो को उनकी धारणा के लिए ज़िंदा जलाया गया था. उस समय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में कई धार्मिक युद्ध हुए थे, जिन्होंने सदियों तक यूरोप में उथल-पुथल बनाए रखी. उसके बाद एकाएक चिंतकों ने धर्म पर सवाल करने शुरू कर दिए.

बरुच स्पिनोजा ने इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में की. वास्तविक ज्ञान का समय आ चुका था. उस समय तर्क ही प्रमुख सिद्धांत बन गया था. इसी वजह से मानवाधिकार और मानव स्वतंत्रता जैसे विचार आने शुरू हुए, लेकिन दो विश्व युद्धों और कई देशों की सत्ताएं हिलने के बाद ही वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा हुई. यही घोषणाएं भारतीय संविधान में भी मानवाधिकारों को परिभाषित करती हैं और बोलने एवं अभिव्यक्ति का अधिकार देती हैं. यह स्वतंत्रता सभी अख़बारों, टीवी चैनलों, रेडियो, किताबों, भाषणों, कार्टूनों, पेंटिंग्स, संगीत और नृत्य में मिलती है. यह स्वतंत्रता पूरे विश्व में रक्त के समान प्रवाहित होती है. रामराज्य चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें यह स्वतंत्रता नहीं थी. शायद इसी वजह से शंभूक ने अपने आपको राजा की तलवार के ग़लत सिरे पर पाया था. उसके पास वैदिक किताबें पढ़ने का अधिकार नहीं था. शंभूक पिछड़ी जाति का था.

कट्टर इस्लाम स्वतंत्रता के लिए हर जगह ख़तरा बन गया है. यह इस्लामिक समाज को बर्बाद कर रहा है, जिसे हम पाकिस्तान में देख सकते हैं कि आख़िर कैसे अलकायदा वहां के लोगों को सता रहा है. यह संगठन आधुनिकता से डरता है, क्योंकि आधुनिकता आपको अपने हिसाब से सोचने और अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है. अलकायदा चाहता है कि सभी इस्लामिक देश मध्य युग में वापस लौट जाएं. अभी तक उसके हमले ज़्यादातर मुस्लिम देशों तक ही सीमित हैं, पाकिस्तान से लेकर पूर्व में मोरक्को तक और उत्तर में चेचेन्या तक. यही आईएसआईएस इराक और सीरिया में कर रहा है. वह उन सभी लोगों को मार रहा है, जो मध्ययुगीन नियमों में विश्वास नहीं रखते. अलकायदा लोगों की हत्याएं करने में यह नहीं देखता कि वह कौन है या क्या है? इसका असर उन देशों पर भी पड़ रहा है, जो मुस्लिम देश नहीं हैं.

9/11 के हमले या इसके पहले ईरान की इस्लामिक क्रांति के समय से ही इस्लाम के धार्मिक उन्माद और आधुनिकता के बीच जंग जारी है. इसकी एक खराब प्रतिक्रिया हो रही है, जिसमें इस्लामोफोबिया का डर यूरोप में पैदा हो रहा है. ऐसा लग रहा है, जैसे कट्टर इस्लाम के मानने वाले अपनी ही छवि बर्बाद करने पर तुले हुए हैं. मुसलमानों को चाहिए कि वे इनका साथ न दें और अपना सिर ऊंचा रखें. स्वतंत्रता के साथ बोलें और व्यवहार करें. भारत ने अपने इतिहास से यह हासिल किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वाइन फ्लू

भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें

किसी भी इंफ्लुएंजा के वायरस का मानवों में संक्रमण श्वास प्रणाली के माध्यम से होता है. आम फ्लू के वायरस की तरह स्वाइन फ्लू भी फैलता है. एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसका वायरस खांसने, छींकने से पहुंचता है. स्वाइन फ्लू का वायरस बेहद संक्रामक है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत तेज़ी से फैलता है.

मोनीशा भटनागर

स्वाइन इंफ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू सूअरों में होने वाला श्वसन रोग (सांस की बीमारी) है. यह टाइप ए इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होता है और सूअरों में नियमित रूप से इंफ्लुएंजा के फैलने का कारण बनता है. वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह वायरस अब केवल सूअरों तक सीमित नहीं है, इसने इंसानों के बीच फैलने की कूवत हासिल कर ली है. साल 2009 इस बात का उदहारण है. इंसानों में स्वाइन फ्लू यानि एच1एन1 इंफ्लुएंजा एक बेहद संक्रामक श्वसन तंत्र की बीमारी है जो इंफ्लुएंजा वायरस की नई किस्म की वजह से होता है. फ्लू के प्रमुख लक्षण है – बुखार, बदन दर्द, नाक बहना, गले का दर्द, बेचैनी, उल्टियां, दस्त. स्वाइन फ्लू होने पर यह लक्षण ज़्यादा विशिष्ट हो जाते हैं. इस फ्लू से उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता किसी बीमारी अथवा अन्य कारणों की वजह से कम है.

किसी भी इंफ्लुएंजा के वायरस का मानवों में संक्रमण श्वास प्रणाली के माध्यम से होता है. आम फ्लू के वायरस की तरह स्वाइन फ्लू भी फैलता है. एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसका वायरस खांसने, छींकने से पहुंचता है. स्वाइन फ्लू का वायरस बेहद संक्रामक है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत तेज़ी से फैलता है. जब कोई खांसता या छींकता है, तो छोटी बूंदों में से निकले वायरस कठोर सतह पर आ जाते हैं. जिस पर ये वायरस 24 घंटो तक जीवित रह सकते हैं. आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, यदि आप इन संक्रमित बूंदों के बीच सांस लेते हैं. जब कोई खांसता या छींकता है, तो छोटी बूंदें थोड़े समय के लिए हवा में फैल जाती हैं और बाद में किसी सतह पर बैठ जाती है. हवा में फैली हुई बूंदें किसी भी इंसान को संक्रमित कर सकती हैं, यदि वह संक्रमित बूंदो को अपनी सांस के भीतर लेता है. संक्रमित व्यक्ति के वायरस से संपर्क में आई किसी चीज़ को छूने से भी यह फैलता है. इस वायरस के संक्रमण के साथ लोगों को लक्षणों की शुरुआत के एक दिन पहले से संभावित संक्रामक माना जाना चाहिए. छोटे बच्चे और ज्यादा लंबी अवधि के लिए संक्रामक हो सकते हैं.

इंफ्लुएंजा वायरस लगातार अपने जीन बदल रहे हैं, यह प्रक्रिया म्युटेशन कहलाती है. स्वाइन फ्लू का वायरस जब मनुष्यों में पाया जाता है, यह प्रजाति बाधा को ओवरकम करने के बाद होता है. इसका मतलब यह वायरस इस तरह म्यूटेटेड है कि यह आदमी में वह स्थिति पैदा करने की अनुमति देता है क्योंकि मनुष्य में सूअरों की तरह इस वायरस के लिए कोई प्राकृतिक संरक्षण या प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती और इस लिये उनके बीमार हो जाने की आशंका बढ़ जाती है.स्वाइनफ्लू वायरस में हुए म्यूटेशन के कारण सबसे अधिक परेशानी इसके संदिग्धों को चिन्हित करने में हो रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक इन दिनों वायरल, डेंगू और स्वाइन फ्लू से मिलते–जुलते लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में इज़ाफा हुआ है. पहले स्वाइन फ्लू के मरीजों में एच1एन1 वायरस के लक्षण की पहचान आसानी से हो जाने के कारण उन्हें तत्काल ही टेमीफ्लू दी जाने लगती थी और बाद में रिपोर्ट आने पर जरूरत अनुसार आगे का इलाज जारी रखा जाता था. वहीं वर्तमान में जो मरीज अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं उनमें स्वाइन फ्लू, डेंगू और वायरल तीनों के लक्षण मिले–जुले नजर रहे हैं. यही कारण है कि वायरस के नए स्वरूप के कारण डॉक्टरों को इसका इलाज करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वर्तमान में स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए सबसे अधिक टेमीफ्लू का इस्तेमाल हो रहा है. एच1एन1 में हुए म्यूटेशन के कारण अब टेमीफ्लू भी इतना असर नहीं कर पा रही है और मरीज को रिकवर होने में अधिक समय लग रहा है.

क्या है स्वाइन फ्लू के लक्षण ?

- नाक का लगातार बहना, छींक आना
- कफ, कोल्ड और लगातार खांसी
- मांसपेशियां में दर्द या अकड़न
- सिर में दर्द
- नींद न आना, ज्यादा थकान
- दवा खाने पर भी बुख़ार का लगातार बढ़ना
- गले में ख़राश का लगातार बढ़ते जाना

स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए क्या करें ?

- खांसते या छींकते समय अपनी नाक तथा मुंह को ढंकें
- बार-बार अपने हाथों को साबुन से धोएं
- नाक और मुंह को मास्क से ढकें
- भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें
- फ्लू के जैसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें
- लगातार पानी पीते रहे
- बुखार के ठीक होने के 24 घंटे बाद तक घर पर रहे

इस समय स्वाइन फ्लू से बचने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है. ऐसी कुछ रोज़मर्रा की चीज़े हैं, जो स्वाइन फ्लू जैसी श्वास संबन्धी बीमारियां उत्पन्न करने वाले वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर सकती हैं, जैसे खांसते या छींकते समय अपनी नाक तथा मुंह को ढंकें,अपने हाथों को बार–बार साबुन तथा पानी से धोएं, विशेष रूप से खांसने या छींकने के बाद और कुछ भी खाने से पहले, अपनी आंखें, नाक तथा मुंह को छूने से बचें, श्वास संबंधी बीमारी है तो भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, बीमार लोगों से नज़दीकी संपर्क रखने से बचें, और यदि आप इंफ्लुएन्ज़ा से पीड़ित हों तो अन्य लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उनसे दूर रहें. हाथ धोने से वायरस और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं. किसी भी व्यक्ति में यदि फ्लू के जैसे कोई लक्षण हैं जैसे –अचानक बुखार, खांसी या मांसपेशियों का दर्द, तो उन्हें काम से दूर रहना चाहिए या सार्वजनिक परिवहन से दूर रहना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. सामान्य इंफ्लुएंजा के दौरान रखी जाने वाली सभी सावधानियां इस वायरस के संक्रमण के दौरान भी रखी जानी चाहिए. स्वाइन फ्लू खाने से नहीं फैलता, पशु के मांस को यदि अच्छी तरह पकाया गया हो तो उससे संक्रमण का कोई ख़तरा नहीं होता है. अगर आप स्वाइन फ्लू से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे है, और आप में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिख रहे है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.■

feedback@chauthiduniya.com

साहस की मिसाल थीं क्रिस्टिना स्कारबेक

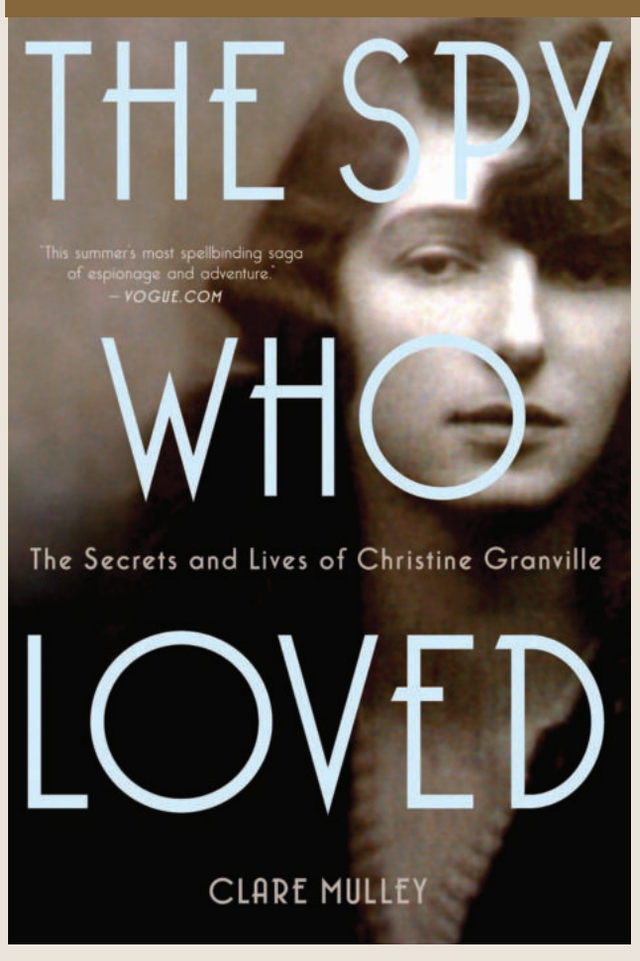

अरुण तिवारी

मारिया क्रिस्टिना जैनिना स्कारबेक, जिन्हें क्रिस्टीन ग्रैनविले के नाम से भी जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का हिस्सा थीं. उन्हें नाजी अधिकृत पोलैंड और फ्रांस के खिलाफ जासूसी करने के लिए याद किया जाता है. उनका जन्म 1 मई 1908 को हुआ था. ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन्स एक्जिक्यूटिव की स्थापना होने से पहले ही वह ब्रिटिश एजेंट बन गई थीं. वे सबसे लंबे समय तक खुद को बचाकर जर्मनी के खिलाफ काम करने वाली ब्रिटिश जासूस थीं. ऐसा माना जाता है कि उनके व्यक्तित्व की वजह से कई महिलाओं ने जासूसी का पेशा अपनाने की तरफ कदम बढ़ाया था. सन 1941 में उन्होंने अपना जासूसी नाम क्रिस्टीन ग्रैनविले प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था. इस नाम को उन्होंने कानूनी रूप से 1946 में एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पर अपनाया.

स्कारबेक का जन्म 1908 में पोलैंड की वर्तमान राजधानी वॉरसा में हुआ था. उनकी मां एक अमीर यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनके पिता ने मां से शादी ही इस वजह से कि थी जिससे वे अपने कर्जे चुका सकें और खर्चीली जिंदगी जी सकें. उनके पिता ने अपने दहेज में मिले पैसों को कर्जा चुकाने में समाप्त कर दिया था. अपनी किशोरावस्था में स्कारबेक का अपने पिता से साथ काफी झगड़ा हुआ करता था, इसका कारण यह था कि भले ही स्कारबेक एक लड़की थीं लेकिन वे लड़कों की तरह स्वच्छंद जीवन जीना चाहती थीं, जिससे उनके पिता को आपत्ति थी.

जब वे 22 वर्ष की थीं तभी उनके पिता की मौत हो गई. वे नहीं चाहती थीं कि अपनी मां पर वे आर्थिक रूप से बोझ बनें. इस वजह से उन्होंने कार कंपनी फियट में नौकरी शुरू कर दी. लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी तबियत ख़राब रहने लगी तो एक्सरे से पता चला कि उन्हें टीबी है जिसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी. कार कंपनी की तरफ से इंश्योरेंश कंपनी ने बीमारी के लिए उन्हें मुआवजा भी दिया. डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि ज्यादा से ज्यादा समय खुली हवा में गुजारने की जरूरत है. इसके बाद वे दक्षिणी पोलैंड चली गई. वहां वादियों के बीच उन्होंने अपने दिन गुजारने शुरू कर दिए. 1930 में उनकी शादी बिजनेसमैन गुस्ताव से हुई. लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली. स्कारबेक ने उसे छोड़ दिया लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें जर्ज़ी नाम के एक आदमी से प्यार हो गया जिससे उन्होंने 1938 में दोबारा शादी की. जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया तो ये युगल लंदन भाग गया. वहां पर स्कारबेक ने खुफिया एजेंसी से जुड़ने की कोशिश की. उनकी मदद ब्रिटिश अधिकारियों ने की. इसका कारण यह था कि ब्रिटिश अधिकारी यह बात जानते थे कि स्कारबेक एक पोलिश महिला हैं और उन्हें अपने मिशन के लिए पोलैंड भी भेजना पड़ेगा तो वे अपने देश के बारे में भली भांति परिचित हैं. स्कारबेक ने अपनी मेहनत से पोलैंड में ऐसा कूरियर सिस्टम बनाया जिसके जरिये जर्मन सेनाओं की सूचना आसानी से ब्रिटेन तक पहुंचाई जा सके. यह पूरा सिस्टम बनाने के बाद स्कारबेक पोलैंड से बुडापेस्ट के रास्ते तुर्की की राजधानी कायरो भाग गईं. जब वे काहिरा पहुंची तो स्पेशल ऑपरेशन एक्जीक्यूटिव के अधिकारियों ने उन पर शक किया क्योंकि स्कारबेक के संबंध पोलिश खुफिया एजेंसियों के भीतर भी थे. इसके अलावा शक की एक और वजह उन्हें मिला तुर्की का वीजा भी था क्योंकि उस तुर्की का वीजा ज्यादातर या तो जर्मनी की जासूसों को मिलता था या पोलिश जासूसों को, लेकिन स्कारबेक इन दोनों में कुछ भी नहीं थीं. जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो स्कारबेक ने पोलैंड में अपने संबंधों के जरिए कई खुफिया सूचनाएं ब्रिटेन तक पहुंचाई थीं. कुछ सालों बाद वे फ्रांस चली गई और एसओई की टीम के लिए काम करना शुरू कर दिया. वे फ्रेंच बोलने में निपुण थीं इस वजह से उन्होंने मैडम पाउलिन के छद्म नाम से ब्रिटेन की ओर से जर्मनी के विरुद्ध जासूसी करना शुरू कर दिया. स्कारबेक के काम की वजह से ब्रिटेन में उनकी काफी तारीफ हो रही थी. 1945 में उन्हें एक बार फिर पोलैंड भेजा गया. जब रेड आर्मी पोलैंड को नाजी सेनाओं के कब्जे से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ने लगीं तो उस समय गोपनीय सूचनाएं रूस और ब्रिटेन को बताकर स्कारबेक ने मित्र राष्ट्रों की काफी मदद की.

विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वे 1946 में वे ब्रिटेन वापस लौट गईं. वहां की सरकार ने उनकी काबिलियत के लिए काफी सराहा. सरकार का मानना था कि स्कारबेक एकमात्र जासूस थीं जो युद्ध के दौरान लगभग छह वर्षों तक लगातार जासूसी करती रहीं. इस दौरान उनके बहुत सारे साथी मार दिए गए लेकिन उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाने में सफलता पाई. इसके बाद उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता दे दी गई.

स्कारबेक की मौत 1952 में लंदन के एक होटल में चाकू घोंपकर हत्या करने की वजह से हुई. उनको मारने वाले पर मुकदमा चलाकर मौत की सजा दे दी गई. स्कारबेक ने अपनी वीरता से नाजी सैनिकों को धूल चटाने की पूरी कोशिश की. वे लगभग हर जगह इस बात में कामयाब भी हुईं. दुनिया के इतिहास में उन्हें बेहतरीन महिला जासूसों में गिना जाता है.■

feedback@chauthiduniya.com

टीटीपी ने रावलपिंडी विस्फोट की ज़िम्मेदारी ली

रावलपिंडी स्थित इमाम बारगाह में हुए विस्फोट की ज़िम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के एक धड़े ने ले ली है. इमाम बारगाह में हुए उक्त भीषण आत्मघाती विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल हो गए थे. विस्फोट से इमारत को भी नुक़सान पहुंचा था. उस वक्त इमाम बारगाह में ईद-मिलन-नबी समारोह चल रहा था. चश्मदीदों के मुताबिक, विस्फोट उस वक्त हुआ, जब एक आत्मघाती हमलावर बारगाह में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहां रोक लिया गया, जिसके बाद उसने अपने आपको उड़ा लिया. टीटीपी के एक धड़े जमात-उल-अहरार के प्रवक्ता एहसानउल्ला एहसान ने कहा, हम इमाम बारगाह में हुए धमाके की ज़िम्मेदारी लेते हैं और इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ इसी तरह हमले जारी रखने का संकल्प लेते हैं. ■

आईएस ने ट्वीटर पर पूछा सवाल

आईएस ने फिर से अपने खूनी अभियान के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया. उसने ट्वीटर पर सवाल पूछा कि बंधक बनाए गए जॉर्डन के पायलट को कैसे मारा जाए? ट्वीटर पर अरबी में लिखे एक हैशटैग को, जिसका मतलब था, जॉर्डनियन पायलट को मारने का तरीका बताएं, हज़ारों बार रि-ट्वीट किया गया. अंग्रेजी अख़बार-द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, आईएस समर्थकों ने ट्वीटर पर बहुत वीभत्स तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनके द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि पायलट को कैसे मारा जाए. जॉर्डनियन पायलट मुआत अल-कसासबे, जिन्हें मोआज कहकर भी पुकारा जाता है, को आईएस लड़ाकों ने बंधक बना लिया था. आईएस ने अपनी अंग्रेजी मासिक पत्रिका द्वारा पायलट का लिया गया इंटरव्यू भी छापा है. ■

ओबामा से पहले जॉन कैरी भारत आए

अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी राष्ट्रपति बराक ओबामा के गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने से पहले भारत पहुंचे. उन्होंने भारतीय अधिकारियों से आर्थिक संबंधों पर चर्चा की और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मिट में शामिल हुए. उनके साथ अमेरिकी व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल भी था. कैरी ने भारत एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र के स्थायी आर्थिक विकास में अमेरिकी प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका और दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश की मजबूती पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिनिधि बराक ओबामा के भारतीय गणतंत्र दिवस में शामिल होने से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे. केरी ने अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अलग-अलग मुलाकात की. ■

पाकिस्तान में नई सैन्य अदालत

अच्छे बुरे आतंकियों की व्याख्या में फंसा पाकिस्तान

वसीम अहमद

पाकिस्तानी कौमी असेंबली ने सैन्य अदालतों की स्थापना के लिए संविधान में 21वें संशोधन के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है और आर्मी एक्ट 1952 में संशोधन का बिल भी सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है. इसमें राजनीतिक एवं धार्मिक दलों में तहरीक-ए-इंसाफ़, जमाते इस्लामी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम ने शिरकत नहीं की. बिल सदन में मौजूद सभी 247 सदस्यों की सहमति से पारित हुआ और किसी भी सदस्य ने उसका विरोध नहीं किया. हालांकि, तहरीक-ए-इंसाफ़, जेयूआई (एफ) और जमाते इस्लामी के सदस्य सदन से अनुपस्थित थे. बिल सीनेटर परवेज रशीद ने पेश किया और सदन से संशोधन की मंजूरी ली गई. 21वें संशोधन के बाद आर्मी एक्ट में संशोधन का बिल प्रस्तुत किया गया. उसे भी सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित कर लिया गया. बिल की मंजूरी के लिए 228 वोटों की आवश्यकता थी, जबकि 240 से अधिक सदस्यों ने उसके पक्ष में सहमति दी. यह बिल सैन्य अदालतों की स्थापना, उनकी सीमा और कार्यावधि से संबंधित है. पाकिस्तान की ज़मीन पर जिस प्रकार से आतंकवाद जन्म ले रहा था, उसे देखते हुए ऐसे बिल की सख्त आवश्यकता थी. विशेषकर, पेशावर स्कूल घटना के बाद इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता अधिक महसूस की जाने लगी, लेकिन इस संशोधन को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान ने तालिबान की तरह अब आतंकवादियों को भी दो वर्गों में बांट दिया है, अच्छा आतंकवादी और बुरा आतंकवादी. बुरा आतंकवादी वह है, जो इस संशोधन की व्याख्या के अंतर्गत आता है. ऐसे आतंकवादी का फ़ैसला सैन्य अदालत करेगी और उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. जो आतंकवादी इस व्याख्या के अंतर्गत नहीं आएंगे, वे अच्छे आतंकवादी कहे जाएंगे. संशोधन 2015 में कहा गया है कि देश में असाधारण परिस्थितियां हैं, जो इस बात का तक़ाज़ा करती हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध का वातावरण पैदा करने वालों के मुक़दमों की फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं.

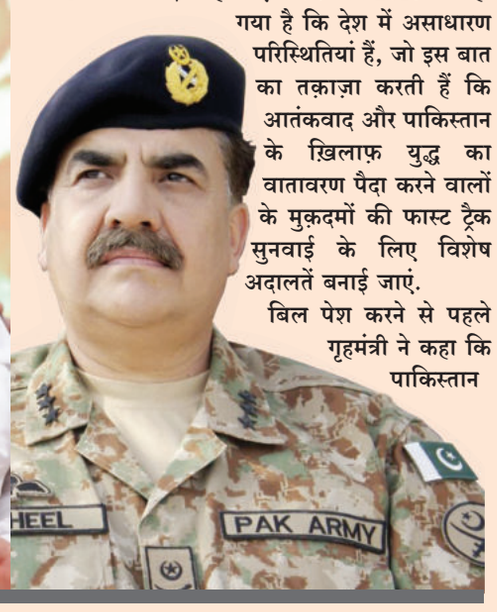

बिल पेश करने से पहले गृहमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में इस समय स्थिति सामान्य नहीं है. देश की जनता, संस्थाएं, नेतृत्व, विपक्ष, बच्चा-बच्चा युद्ध-परिस्थितियों से प्रभावित है. सैन्य अदालतें जब भी दुनिया में बनीं, या तो जंग की स्थिति बनी तब या फिर जंग के बाद. और, इस समय पाकिस्तान युद्ध-परिस्थितियों का सामना कर रहा है. लिहाज़ा इस बिल को लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी संगठनों की ओर से धर्म या संप्रदाय का नाम लेकर हथियार उठाने वालों को सजा देना और स्थानीय एवं विदेशी मदद हासिल करके ऐसे तत्वों को रोका जाना है. इसी तरह आतंकवादी संगठनों की ओर से सेना पर हमला करने वाले समूह के ट्रायल के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी. इस संशोधित बिल के बाद कोई भी आतंकवादी समूह या उससे संबंध रखने वाले शख़्स, जो धर्म या संप्रदाय की बुनियाद पर पाकिस्तान के विरुद्ध हथियार उठाएगा, सशस्त्र सेना और क़ानून लागू करने वाली एजेंसियों पर हमला करेगा, किसी नागरिक या सैन्य ठिकानों पर हमले में संलिप्त होगा, अपहरण करके किसी व्यक्ति की हत्या या उसे घायल करेगा, बारूदी वस्तुएं एकत्र करने में संलिप्त होगा, आत्मघाती जैकेट्स या गाड़ियों की तैयारी में संलिप्त होगा, किसी भी प्रकार के स्थायी या विदेशी सूत्रों से फंडिंग उपलब्ध करेगा या कराएगा, अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ किसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होगा, उसके विरुद्ध इस क़ानून के तहत कार्यवाही होगी. यह संशोधन दो वर्षों तक के लिए प्रभावी होगा और उसके बाद इसे स्वयं निष्क्रिय मान लिया जाएगा.

इस संशोधित बिल में जो व्याख्या पेश की गई है, उसे देखने के बाद अनुमान होता है कि अब कोई आतंकी घटना अंजाम दिए जाने के बाद पहले यह देखा जाएगा कि आतंकवादी किस स्वभाव का है. अगर घटना धर्म का नाम लेकर अंजाम दी गई है, तो वह आतंकवाद की श्रेणी में आएगा और आरोप साबित हो जाने के बाद ऐसे अपराधी को सजा-ए-मौत दी जाएगी. अगर घटना धर्म के नाम पर नहीं है, तो उसका निर्णय साधारण अदालतों में होगा. यह व्याख्या बताती है कि अगर कोई व्यक्ति क्षेत्रीय, नस्ली या किसी दूसरे कारण से किसी को मार देता है, पुलिस पर हमला करता है, कॉलेज की बस पर हमला करता है, बस यात्रियों को बाहर निकाल कर गोलियों से भून देता है, किसी मुहल्ले में जाकर घरों को आग लगा देता है, तो उसका मुक़दमा विशेष अदालत में नहीं भेजा जा सकेगा, क्योंकि उसने यह ख़ूनख़राबा धर्म के नाम पर नहीं किया है. ऐसे अपराधियों के मामले साधारण अदालतों में भेजे जाएंगे और उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकेगी. इस संशोधन में आतंकवादियों को स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय सूत्रों से मिलने वाली सहायता पर रोक लगाने का इशारा दिया गया है. निश्चित ही आतंकवाद तो आतंकवाद होता है और उसे स्थानीय या विदेशी सहायता मिलना देश की शांति के लिए ख़तरा होता है, लेकिन इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया. वह यह कि अगर देश का कोई समूह या संस्था विदेश जाकर आतंकी घटना को अंजाम देता है और फिर देश में आकर शरण लेता है, तो उसका मुक़दमा विशेष अदालत में पेश करने की बात नहीं कही गई है. मतलब यह है कि ऐसा करने वालों का फ़ैसला आम अदालतों में होगा और उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा. लिहाज़ा यह कहना उचित होगा कि इस बिल ने आतंकवादियों को दो धड़ों में बांट दिया है. यानी बुरे आतंकवादियों का फ़ैसला विशेष अदालत में होगा और अपराध सिद्ध होने पर उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, जबकि दूसरे धड़े के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वे अच्छे आतंकवादी हैं.

आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, वह चाहे किसी भी रूप में और किसी भी जगह पर अंजाम दिया गया हो, उसमें मानवता की हत्या होती है. लिहाज़ा अपराध सिद्ध होने पर उसकी सजा मौत होनी चाहिए. पेशावर स्कूल, जिय़ारत रेजिडेंसी, क्वेटा कॉलेज बस हमले जैसी घटनाओं के अपराधियों को सरेराह फांसी की सजा दी जानी चाहिए. लेकिन, जब आतंकवादियों के बीच अच्छे और बुरे का अंतर पैदा कर दिया जाएगा तथा दोनों की सजाएं तय करने के लिए अलग-अलग अदालतें बनेंगी, तो मौलाना फज़लउर्रहमान जैसे धार्मिक लोगों को संशोधित बिल का विरोध करने का मौक़ा मिलेगा और यह कहने का अधिकार मिल जाएगा कि धर्म को जबरन आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है. इसलिए आतंकवाद में धर्म को शामिल करने की बजाय इस व्याख्या को आम रखना चाहिए. हालांकि, इस संशोधन में एक अच्छी बात यह है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है. अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उससे संबंधित मुक़दमा विशेष अदालत में ले जाने की बात कही गई है.

चूंकि इस संशोधन का संबंध पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों से है, लिहाज़ा उसे अधिकार है कि वह अपने क़ानूनों में जैसा चाहे, वैसा फेरबदल करे. लेकिन, जब पाकिस्तान सरकार पूरी दुनिया में ढोल पीटकर यह कहती है कि उसने अपने देश से आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए कमर कस ली है और अब वह अपनी ज़मीन से आतंकवाद का ख़ात्मा करके ही दम लेगी, तो स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिक जाती हैं और यह आशा की जाती है कि वह देश के अंदर आतंकवाद रोकने के साथ-साथ अपनी धरती से दूसरे देशों में अंजाम दी जाने वाली आतंकवादी घटनाएं रोकने के लिए कोई कारगर क़दम उठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा. ■

मंगल ग्रह पर बसने के ख़िलाफ़ फतवा

यूएई के मुस्लिम विद्वानों ने मंगल ग्रह पर रहने के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया है. मंगल ग्रह पर रहने को ग़ैर इस्लामिक बताते हुए जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड एंडॉमेंट ने कहा है कि मार्स वन नामक संगठन ने मंगल पर बस्तियां बसाने का जो ऐलान किया है, वह ग़ैर इस्लामिक है. विद्वानों का कहना है कि मंगल एक ख़तरनाक ग्रह है, वहां का वातावरण इंसान के लिए ख़तरनाक है, इसलिए वहां रहना खुदकुशी करने जैसा होगा, जो इस्लाम में हराम है. ख़लीज टाइम्स डॉट कॉम के अनुसार, इस कमेटी ने कहा कि मंगल पर जाना ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है. इसे इस्लाम में कभी सही नहीं ठहराया जा सकता. आशंका है कि मंगल पर जाने वाला इंसान ज़िंदा नहीं बच पाएगा. कमेटी ने कहा कि ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों की जान बिना किसी उचित वजह के जाएगी और उन्हें मौत के बाद वही सजा मिलेगी, जो खुदकुशी करने वालों को मिलती है. कमेटी के अध्यक्ष डॉ. फारूक हमादा ने कहा, हर धर्म में कहा गया है कि जीवन को किसी भी सूरत में हर तरह के ख़तरे से बचाना चाहिए. कुरान-ए-पाक में भी लिखा है कि न खुद को मारो, न दूसरों को. ■

मिल गया ब्लैक बॉक्स

क्रैश हुए एयर एशिया के विमान का ब्लैक बॉक्स जावा सागर में ढूंढ निकाला गया. हादसे की गुत्थी सुलझाने में अहम यह ब्लैक बॉक्स विमान की मुख्य बॉडी में फंसा हुआ था. इंडोनेशिया के मरीन ट्रांसपोर्ट विभाग के डायरेक्टर जनरल ने ब्लैक बॉक्स खोज निकालने की पुष्टि की. इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज केएन जदायत में तैनात गोताखोरों ने 30-32 मीटर की गहराई पर इसे खोज निकाला. इससे पहले जावा सागर में विमान की तलाशी वाले इलाके में खोजकर्ताओं को ब्लैक बॉक्स के पहले से ज़्यादा मजबूत और तेज संकेत मिले थे. उसी इलाके में विमान की मुख्य बॉडी होने का भी पता चला. भारतवंशी एवं एयर एशिया के प्रमुख टोनी फर्नांडिस ने उम्मीद जताई कि ब्लैक बॉक्स के ज़रिये हादसे की गुत्थी सुलझ सकती है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

> अच्छा, तुम उससे पूछ आओ कि क्या वह बारवी कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है. शामा ने हांजी से जाकर बाबा का संदेश बताया और हांजी तैयार हो गया. शामा बाबा के पास उत्तर लेकर पहुंचे. फिर बाबा ने पुनः शामा से कहा कि उससे फिर पुछो कि क्या वह मुझे चार किश्तों में चालीस हजार रुपये देने को तैयार है. फिर शामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं चालीस लाख रुपये देने को तैयार हूं.

साई हर मनोकामना पूरी करते हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा निराकार थे, लेकिन भक्तों के प्रेमवश वे साकार रुप में प्रगट हुए. साई बाबा का हम सभी को ध्यान व स्मरण करना चाहिए. जब हम इस धरती पर पैदा होते हैं तो मानव की न कोई जाति होती है और न ही उसका कोई धर्म. मानव को बांटने का काम हम लोग ही करते हैं. हमारे साधु–संतो और समाज सुधारकों ने हमेशा समाज में एकता कायम करने के लिए लोगों को जागरूक किया. समाज में इसी वर्गीकरण की दीवार को और एकता भाव को मजबूत करने के लिए शिरडी के साई बाबा को हम याद करते हैं.

शिरडी के साई बाबा को कुछ लोग दैवीय अवतार तो कुछ लोग चमत्कारी मानते हैं, लेकिन समाज में उन पर कोई सवाल नहीं उठाता कि वह हिंदू थे या मुसलमान. साई बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है. साई बाबा धर्म और जात–पात की बेड़ियों को तोड़कर एक विशुद्ध संत की तस्वीर समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं. साई सभी जीवात्माओं की पुकार सुनने व उनके कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए.

यह कोई नहीं जानता कि कब साई बाबा अपने भक्त को अपना कृपापात्र बना लेंगे. यह उनकी सदिच्छा पर निर्भर था. हाजी सिद्दीक फालके की कथा इसी का उदाहरण है. कल्याण निवासी एक यवन, जिनका नाम सिद्दीक फालके था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आये. वे चावड़ी

में उत्तर की ओर रहने लगे. वे मस्जिद (जहां साई बाबा रहते थे) के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे. बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा न दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी. फालके बहुत निराश थे और कुछ निर्णय न कर सके कि कौनसा उपाय काम में लाएं. लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो. शामा साई बाबा के भक्त हैं. तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो. जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिये नन्दी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी शामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिये. फालके को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होने शामा से सहायता की प्रार्थना की. शामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि, बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते. अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया–जाया करते हैं. कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो. बाबा बोले, शामा, तुम अभी नादान हो. यदि फकीर को अल्लाह नहीं आने देता है तो मै क्या करुं. उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता. अच्छा, तुम उससे पूछ आओ कि क्या वह बारवी कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है. शामा ने हांजी से जाकर बाबा का संदेश बताया और हांजी तैयार हो गया. शामा बाबा के पास उत्तर लेकर पहुंचे. फिर बाबा ने पुनः शामा से कहा कि उससे फिर पुछो कि क्या वह मुझे चार किश्तों में चालीस हजार रुपये देने को तैयार है. फिर शामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं चालीस लाख रुपये देने को तैयार हूं. मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूं, उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा–बकरे का मांस, नाध या अंडकोष. शामा यह उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन–पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाय तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा. यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गये और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन (पानी की गागर) उठाकर फेंक दी और अपनी कफनी उठाये हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे. वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो. अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो. यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है. क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो. तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, लेकिन तुम मुझसे अनभिज्ञ हो. इस प्रकार डां सुनकर हाजी घबरा गया. बाबा मस्जिद को लौट आये और कुछ आमों की टोकरियां खरीद कर हाजी के पास भेज दी. वे स्वयं भी हाजी के पास गये और अपने पास से 55 रुपये निकाल कर हाजी को दिये. इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे. अब हाजी भी अपनी इच्छानुसार मस्जिद में आने–जाने लगे. कभी–कभी बाबा उन्हें कुछ रुपये भी भेंट में दे दिया करते थे. इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गये. इसी प्रकार बाबा कब किसे अपना कृपापात्र बना ले किसी को नहीं पता.■

शिरडी के साई बाबा को कुछ लोग दैवीय अवतार तो कुछ लोग चमत्कारी मानते हैं, लेकिन समाज में उन पर कोई सवाल नहीं उठाता कि वह हिंदू थे या मुसलमान. साई बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है. साई बाबा धर्म और जात–पात की बेड़ियों को तोड़कर एक विशुद्ध संत की तस्वीर समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं. साई सभी जीवात्माओं की पुकार सुनने व उनके कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए.

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

पीके का अनुचित विरोध

विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित, राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित एवं आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म पीके का हिन्दु संगठन जिस तरह विरोध कर रहे हैं. उससे तो वे अपना ही अहित कर रहे हैं. अच्छा होता कि वे उस संदेश को समझने की कोशिश करते जो फिल्म के माध्यम से समाज को दिया गया है कि ईश्वर की खोज आत्मिक शक्ति के माध्यम से बिना किसी आडम्बर से होनी चाहिए तथा पाखंडी छद्म गुरूओं से बचना चाहिए. सेंसर बोर्ड से पारित फिल्म का आक्रामक विरोध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठार घात है, क्योंकि लोकतंत्र में विविधता तथा आत्मलोचना का विशिष्ट स्थान है.

–सत्य प्रकाश(शिक्षक), *लखीमपुर–खीरी, उत्तर प्रदेश*

आतंकवादियों की फांसी में विलम्ब क्यों!

भारत में एक नहीं दर्जनों ऐसे मामले गिनाए जा सकते हैं, जब आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें वर्षों तक जेल में रखकर उनकी शाही खातिर की गई. लालकिले पर विस्फोट करने वाले आरिफ उर्फ अशफाक, मुंबई बम विस्फोट का साजिशकर्ता याकूब मेमन समेत कई ऐसे आंतकी कैदी हैं, जिन्हें अदालत मौत की सजा सुना चुकी है. इनमें 27 कैदी ऐसे हैं जिनकी दया याचिका भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा खारिज की जा चुकी है, फिर सरकार उन्हें फांसी क्यों नहीं दे रही है?

–राजकिशोर पांडेय, *लखीमपुर–खीरी, उत्तर प्रदेश.*

बैंक का काला कारनामा

कवर स्टोरी– ऋण की रेवड़ियां बांट रहा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अरबों रुपये डूबे घोटालेबाजों का बैंक..!(05 जनवरी–11 जनवरी 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक आलेख है. प्रभात रंजन दीन का आलेख एक सच्चाई बयां कर रहा है जो बैंकों का असली रूप है. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने जिस तरह दिवालिया हो चुकी कम्पनियों पर ऋण बांटे हैं, वह उसके अधिकारियों के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है. किसी जरूरतमंद गरीब, किसान को कभी आसानी से ऋण नहीं मिलता है. अगर किसी किसान को ऋण मिल भी गया और वह किसी कारण समय से चुका नहीं पाया तो उसे प्रताड़ित करने के साथ ही जेल में डाल दिया जाता है. इसलिए घोटलोबाज कर्मियों की पूरी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिले.

–रवि कुमार, *रीवा, मध्यप्रदेश.*

मोदी लहर ने दिलाई जीत

आलेख–झारखंड, मोदी लहर का जादू और जम्मू–कश्मीर, जनता के फैसले से सब हैरान (05 जनवरी–11 जनवरी 2015) पढ़ा. दोनों आलेख तथ्यपरक हैं. मंगालनंद ने सही कहा है कि झारखंड में मोदी लहर का जादू चला. भाजपा मोदी लहर पर सवार होकर झारखंड विधानसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गई और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी. आजसू ने झारखंड विधानसभा चुनाव में पांच सीटों पर जीत हासिल की और झारखंड में पहली बार चुनाव पूर्व गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया. कमर तबरेज का कहना बिल्कुल सही है कि जम्मू–कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया. जम्मू–कश्मीर में वहां की जनता ने किसी पार्टी को बहुमत नहीं दी. भाजपा अपना मिशन 44 पूरा करने में तो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन वह 25 सीटें जीतकर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई. पीडीपी जम्मू–कश्मीर में 28 सीटें जीतकर नंबर एक पर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर है. सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को हुआ जो केवल 12 सीटें ही जीत पाई और जम्मू कश्मीर में चौथे नंबर पर पहुंच गई. मोदी लहर का ही नतीजा है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी और जम्मू–कश्मीर में भाजपा 25 सीटें जीतने में कामयाब हो गई.

–अभिमन्यु यादव, *आरा, बिहार.*

सराहनीय समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र (05 जनवरी–11 जनवरी 2015) पढ़ा. इस अंक में प्रकाशित सभी आलेख जानकारीपरक हैं. कवर स्टोरी पर प्रकाशित आलेख ऋण की रेवड़ियां बांट रहा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अरबों रुपये डूबे घोटालेबाजों का बैंक..! काफी विचारोत्तेजक है. प्रभात रंजन दीन के आलेख से पता चलता है कि एक बैंक किस प्रकार घोटालेबाजों का बैंक बन गया है. झारखंड मोदी लहर का जादू, जम्मू–कश्मीर जनता के फैसले से सब हैरान, धर्मांतरण विवाद: क्या कहता है भारतीय कानून, असम नरसंहार: आंतरिक सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत, हिटलर की जासूस थी स्टेफनी, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे दो और संपादकीय पेज पर प्रकाशित सभी आलेख तथ्य परक हैं. जब तोप मुकाबिल हो आत्मावलोकन का वक्त है इतना अच्छा और जानकारी परक संपादकीय है जिसे पढ़कर काफी खुशी हुई. चौथी दुनिया समाचार पत्र की सराहना जितनी की जाय उतनी कम है.

–उर्मिला तिवारी, *पटना, बिहार.*

कब वादा पूरा होगा!

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बने 6 महीने से अधिक हो गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे वह एक भी पूरा होता दिख नहीं रहा है. सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की है, लेकिन अमल कब तक होगा यह नहीं मालूम है. महंगाई की बात करें, कालेधन की बात करें और रोजगार की बात करें किसी पर भी अमल होता दिख नहीं रहा है. चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई थी, लेकिन सरकार उस पर अब तक कामयाबी नहीं पाई सकी है. अगर सरकार कहे कि उसने पेट्रोल पटार्थों के दाम कम किए हैं, तो वह गलत है. पेट्रोलियम पटार्थों के दाम इसलिए कम हुए, क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोस की कीमत हुई है. इसलिए सरकार को चाहिए कि वह बाते कम करें और काम ज्यादा करें.

–सौरभ मौर्या, *पालम, नई दिल्ली.*

कहानी

एक परिश्रमी बालक

एक बालक नित्य विद्यालय पढ़ने जाता था. घर में उसकी माता थी. मां अपने बेटे पर प्राण न्योछावर किए रहती थी, उसकी हर मांग पूरी करने में आनंद का अनुभव करती. पुत्र भी पढ़ने–लिखने में बड़ा तेज और परिश्रमी था. खेल के समय खेलता, लेकिन पढ़ने के समय का ध्यान रखता. एक दिन दरवाजे पर किसी ने–माई! ओ माई! पुकारते हुए आवाज लगाई तो बालक हाथ में पुस्तक पकड़े हुए द्वार पर गया, देखा कि एक फटेहाल बुढ़िया कांपते हाथ फैलाए खड़ी थी.

उसने कहा, 'बेटा! कुछ भीख दे दे.

बुढ़िया के मुंह से बेटा सुनकर वह भावुक हो गया और मां से आकर कहने लगा, मां! एक बेचारी गरीब मां मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है.

उस समय घर में कुछ खाने की चीज नहीं थी, इसलिए मां ने कहा, बेटा! रोटी–भात तो कुछ बचा नहीं है, चाहे तो चावल दे दो.

पर बालक ने हठ करते हुए कहा–मां! चावल से क्या होगा? तुम जो अपने हाथ में सोने का कंगन पहने हो, वही दे दो न उस बेचारी को. मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो तुम्हें दो कंगन बनवा दूंगा'

मां ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का अपना वह कंगन कलाई से उतारा और कहा, लो, दे दो.

बालक खुशी–खुशी वह कंगन उस भिखारिन को दे आया. भिखारिन को तो मानो एक खजाना ही मिल गया. कंगन बेचकर उसने परिवार के बच्चों के लिए अनाज, कपड़े आदि जुटा लिए. उसका पति अंधा था. उधर वह बालक पढ़–लिखकर बड़ा विद्वान हुआ, काफी नाम कमाया.

एक दिन वह मां से बोला, मां! तुम अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूं. उसे बचपन का अपना वचन याद था.

पर माता ने कहा, उसकी चिंता छोड़. मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देंगे. हां, कलकत्ते के तमाम गरीब बालक विद्यालय और चिकित्सा के लिए मारे–मारे फिरते हैं, उनके लिए तू एक विद्यालय और एक चिकित्सालय खुलवा दे जहां निशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो. मां के उस पुत्र का नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर था.■

शिक्षा: हम समाज और गरीबों के लिए कार्य करना चाहिए.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

गांव पहुंचे, तो लगा जेल से छूट आए. अब तो हंसी आती है. वही जेल अब हमको सबसे ज़्यादा मुक्ति देती है. नहीं आने के लिए मां से लड़ाई किए, रूठे, रोए, कांपे, परारथना (प्रार्थना) तक कर डाले थे कि इक्का का घोड़ा मर जाए. बहुत बुरी लगी थी तब मां. बाउ जी भी. सभी लोग. बस वही देखे हुए हैं मां–बाउ जी को. फिर सबके मरने की ख़बर ही सुनते रहे. एक बार और मौक़ा मिला था जाने का. दो साल बाद. भइया की सादी (शादी) में. लेकिन, जाने की खुसी (खुशी) से ज़्यादा डर वापस आने का लगा. फिर से उनको छोड़के आना पड़ेगा. फिर मां नहीं मानेगी. फिर हमको सब बुरे लगेंगे. फिर गुस्सा आएगा, रोना आएगा, दुःख होगा, घबराहट होगी, आने का पछतावा होगा. हमने सास को बोल दिया, हम नहीं जाएंगे.

कालजयी फिल्म पर किताब

अनंत विजय

विश्व राजनीति में रुचि रखने वालों को इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व, उनकी राजनीति एवं क्रियाकलापों में दिलचस्पी रहती है और उसे केंद्र में रखकर किताबें एवं पर्चे लिखे जाते हैं. इंदिरा गांधी की राजनीतिक चालों से लेकर उनके व्यक्तिगत जीवन पर दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, हज़ारों शोधपत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं. राजनीतिक पंडित अलग–अलग तरीके से उनके जटिल व्यक्तित्व की व्याख्या करते रहे हैं. सबका अपना–अपना कोण और अपनी–अपनी दृष्टि, लेकिन केंद्र में इंदिरा गांधी और उनकी राजनीति. इसी तरह फिल्मी दुनिया एवं वहां काम करने वाली शख्सियतों पर लिखने वालों को मशहूर अदाकारा मीना कुमारी का फिल्मी करियर और व्यक्तित्व बार–बार अपनी ओर खींचता है. मीना कुमारी के व्यक्तित्व के अनेक छोर हैं और लेखक उन छोरों को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं. जब मीना कुमारी जीवित थीं, तो उनके प्रेम और अलगाव के किस्से, जब उन्होंने कमाल अमरोही से निकाह किया तो पारिवारिक जीवन में मुहब्बत और झगड़ों के किस्से, जब वह बीमार पड़ीं तो उनकी मुफलिसी के किस्से आम होते रहे. एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय फिल्म जगत में मीना कुमारी ऐसी अदाकारा हैं, जिन पर या जिनकी फिल्मों को केंद्र में रखकर अब तक सबसे ज़्यादा किताबें आईं और लेख छपे. अब ताजा किताब है मशहूर अर्थशास्त्री एवं लेखक मेघनाथ देसाई की. इस छोटी–सी किताब का नाम है, पाकीजा, एन ओड टू अ बाइगॉन वर्ल्ड. यह किताब हॉर्पर कॉलिंस ने अपनी फिल्म सीरीज के तहत छापी है. मेघनाद देसाई का मानना है कि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस की सफलता को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं. देसाई के मुताबिक, 1954 में फिल्मिस्तान के बैनर की फिल्म नागिन और उसके दस वर्षों बाद आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म संगम इसी श्रेणी में आती है. मेघनाथ देसाई के मुताबिक, एक निश्चित समय के बाद इन फिल्मों को भुला दिया जाता है. पता नहीं, मेघनाथ देसाई के यह कहने का आधार क्या है, लेकिन अब भी राजकपूर की फिल्म संगम और फिल्मिस्तान की फिल्म नागिन की चर्चा होती रहती है. मेघनाथ देसाई का यह कथन सही है, लेकिन उन्होंने उदाहरण ग़लत चुन लिए हैं.

इन दो फिल्मों के अलावा मेघनाथ देसाई उदाहरण देते हैं, 1943 में बनी बांबे टाकीज की फिल्म किस्मत और 1949 में बनी महबूब खान की फिल्म अंदाज़ का. देसाई का मानना है कि भारत छोड़ो आंदोलन और विश्व में युद्ध के माहौल के बीच बनी फिल्म किस्मत का अब कोई नामलेवा भी नहीं है. इसी तरह वह दावा करते हैं कि महबूब खान की फिल्म अंदाज़ में दिलीप कुमार, नरगिस एवं राजकपूर के होने और नई पीढ़ी को परिभाषित करने के बावजूद इस फिल्म को दर्शक अब याद नहीं करते. बहुत हद तक मेघनाथ देसाई सही हो सकते हैं, लेकिन वह इतने बड़े कालखंड के बाद दर्शकों से उन फिल्मों को याद रखने की अपेक्षा कर रहे हैं, यह थोड़ी ज़्यादती है. उनका एक और तर्क बेमानी लगता है कि उन फिल्मों का रीमेक नहीं बन रहा है.

फिल्मों में विषय का चयन पीढ़ियों की रुचि को ध्यान में रखकर किया जाता है. व्यवसायिक फिल्मों से धन कमाने की इच्छा और इरादा, दोनों ही बातें साथ काम करती हैं. अब अगर फिल्म किस्मत को इस आधार पर दरकिनार कर दिया जाए कि उसका रीमेक नहीं बना, तो यह तर्क गले नहीं उतरता है. देसाई का मानना है कि इस तरह की फिल्मों के अलावा कई फिल्में ऐसी होती हैं, जो काल से होड़ लेती हुई कालजयी हो जाती हैं. ऐसी फिल्मों का जिक्र करते हुए वह याद करते हैं, 1935 में रिलीज हुई फिल्म देवदास को. इस फिल्म को पीसी बरुआ ने निर्देशित किया था और कुंदन लाल सहगल केंद्रीय भूमिका में थे. देसाई इस बात को लेकर उत्साहित दिखते हैं कि देवदास की कहानी पर कई बार फिल्में बनीं और अलग–अलग अभिनेताओं ने केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया. फिल्म जब भी बनी, हिट रही. इसी सूची में उन्हें दो नाम और याद आते हैं, मदर इंडिया और मुगल–ए–आजम, लेकिन देसाई शोले को इस आधार पर खारिज कर देते हैं कि उसका रीमेक जब राम गोपाल वर्मा ने राम गोपाल वर्मा की आग के नाम से बनाया, तो वह फिल्म फ्लॉप रही. मैं सिर्फ़ इतना जोड़ना चाहूंगा कि इस बारे में

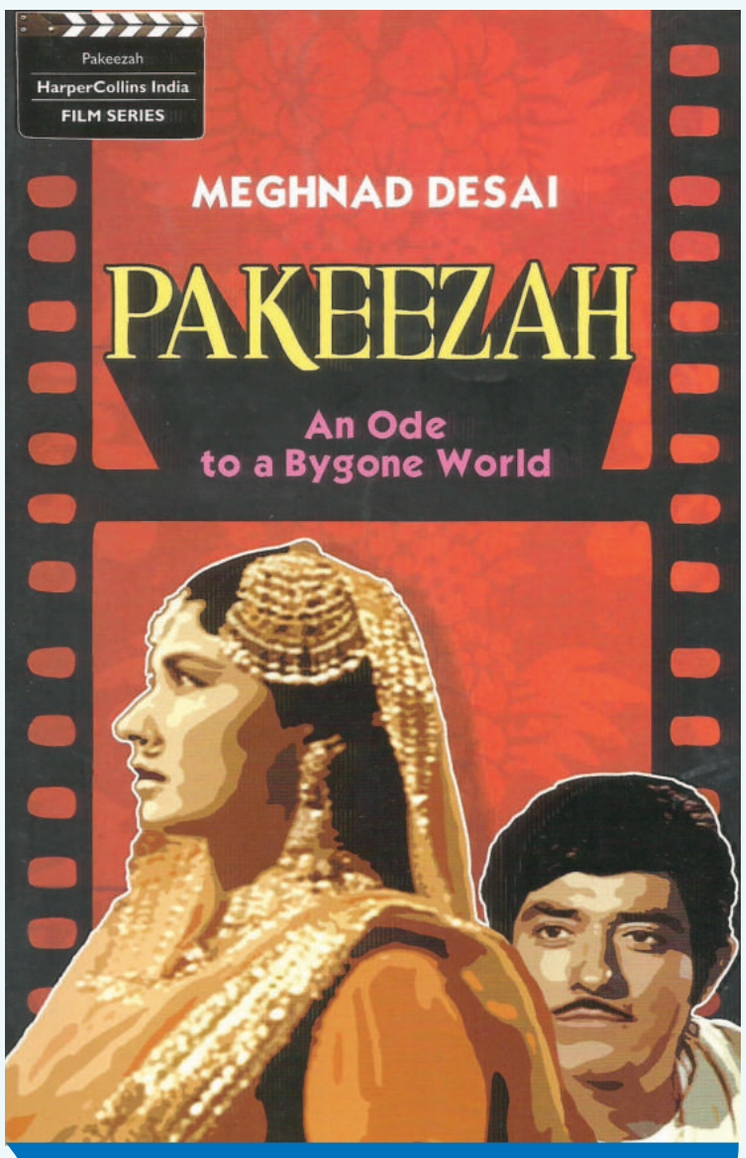

समीक्ष्य कृति: पाकीजा, एन ओड टू अ बाइगॉन वर्ल्ड
लेखक: मेघनाद देसाई
प्रकाशक: हॉर्पर कॉलिंस, नोएडा
मूल्य: 250 रुपये

मेघनाद देसाई संभवत: अर्थशास्त्र के नियमों के आधार पर फिल्मों और उनकी शेल्फ लाइफ की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ग़लत है. वह हाल की फिल्म डॉन को भूल जाते हैं, जिसका रीमेक भी उतना ही सफल रहा, जितनी मूल फिल्म थी. अपने इसी विश्लेषण में मेघनाथ देसाई कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा को एक विशेष कालखंड में मुस्लिम संस्कृति को पकड़ने और उसे चित्रित करने वाली फिल्म करार देते हैं. देसाई अपने उपरोक्त तर्कों में तो कई फिल्मों के नाम गिना देते हैं, लेकिन जब मुस्लिम संस्कृति को चित्रित करने वाली फिल्म के तौर पर पाकीजा को याद करते हैं, तब न तो उन्हें राजेंद्र कुमार की फिल्म पालकी याद आती है और न 1960 में मोहम्मद सादिक के निर्देशन में बनी मशहूर फिल्म चौदहवीं का चांद. भुला तो वह राजेश खन्ना एवं लीना चंदरावरकर की फिल्म महबूब की मेहंदी को भी देते हैं. खैर, यह लेखक का अधिकार है कि वह किस विषय पर अपने किस तर्क को सामने रखे और किसे अपनी नज़रों से ओझल कर दे.

मेघनाथ देसाई ने अपनी इस छोटी–सी किताब में इस फिल्म की कहानी, उससे जुड़े किस्सों, किरदारों एवं घटनाओं के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियां की हैं. फिल्म पाकीजा के कई किस्से बेहद मशहूर हुए हैं. यह बात तो सर्वविदित है कि इस फिल्म का मुहूर्त शाट 17 जनवरी, 1957 को दिया गया और फिल्म रिलीज हुई चार फरवरी, 1972 को, तक़रीबन पंद्रह साल बाद. इस बीच इस फिल्म में काम करने वाले कई लोग प्रोजेक्ट से अलग हो गए, तो कइयों की मौत हो गई. यह फिल्म पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट में शूट होनी शुरू हुई, तकनीक बदली, तो फिर से कलर में शूट होने लगी. उसके बाद सिनेमास्कोप का जमाना आया, तो उसमें शूटिंग हुई. पहले के सारे शूट रद्दी में डाल दिए गए. सिनेमास्कोप को लेकर भी एक दिलचस्प प्रसंग इस फिल्म से जुड़ा हुआ है. कमाल अमरोही को परफैक्शनिस्ट के तौर पर जाना जाता है. वह फिल्म की लोकेशन से लेकर हर शॉट का बेहद बारीकी से ध्यान रखते थे. जुनूनी इतने थे कि फिल्म के कास्ट्यूम डिजायन का काम खुद मीना कुमारी ने संभाला था. जब उन्होंने पाकीजा के कलर शूट को रद्दी में डालकर सिनेमास्कोप में करना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि सिनेमास्कोप के जिस लेंस से वह शूटिंग कर रहे थे, उसका फोकस ठीक नहीं था. उस जमाने में एमजीएम नामक विदेशी कंपनी से लेंस आता था. कभी किराए पर, तो कभी अन्य शर्तों पर. कमाल अमरोही उस जमाने में उस लेंस के लिए पचास हज़ार रुपये महीने चुका रहे थे. कमाल अमरोही ने लेंस के फोकस की त्रुटि के बारे में एमजीएम कंपनी को खत लिखा. कंपनी के नुमाइंदों ने लेंस की जांच की, तो अमरोही की शिकायत सही पाई गई. बाद में उस लेंस को कंपनी ने कमाल अमरोही को उपहार के तौर पर भेंट कर दिया. इस किताब के एक अध्याय–द मेकिंग में लोकेशन को लेकर कमाल अमरोही की बेचैनी का भी जिक्र है. मेघनाद देसाई ने उस जमाने के फिल्मी अख़बारों के हवाले से कई तथ्य लिखे हैं, जैसे लोकेशन के चुनाव को लेकर उन्होंने जनवरी, 1958 के स्क्रीन को कोट किया है.

पाकीजा को तकनीक से आधुनिक बनाने के जुनून के दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई थी. फिल्म शुरू होने के सात वर्षों के बाद मार्च, 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग हो गए. उस दौर में मीना कुमारी अपने करियर के शिखर पर थीं और उनकी एक के बाद एक फिल्म सुपरहिट हो रही थी. फिल्म पाकीजा के हीरो के चुनाव की भी दिलचस्प दास्तां है, जो सालों से ज्ञात है. उसे भी मेघनाद देसाई ने बचते–बचाते बयान किया है. धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्तों पर भी लिखा गया है. इतना अवश्य है कि देसाई ने पठनीय तरीके से इस फिल्म के बहाने सारे किस्से कह डाले हैं. इस किताब की एक और विशेषता है कि इसमें उनके किरदारों के बारे में भी जानकारीपरक टिप्पणियां हैं. मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेघनाथ देसाई ने वीणा सप्रू और विजयलक्ष्मी के बारे में भी परिचयात्मक टिप्पणी की है. कमाल अमरोही पर तो एक पूरा अध्याय ही है.

इस पूरी किताब को पढ़ते वक्त अचानक मेरे दिमाग में बचपन की कुछ यादें कौंध गईं. उस वक्त हमें फिल्में देखने की मनाही थी या कह सकते हैं कि अकेले जाकर फिल्म देखने की इजाजत नहीं थी. फिल्मों की चर्चा सुनकर जानने की जिज्ञासा होती थी. उस दौर में हम बुक स्टॉल पर पहुंचते थे, जहां हिट फिल्म की कहानी की एक पतली–सी किताब मिला करती थी. हम उसे खरीदते और दोस्तों के साथ सामूहिक रूप से बांचते थे. अमिताभ बच्चन की फिल्मों के संवाद की किताब तो अलग से मिला करती थी. क़ीमत एक से दो रुपये तक हुआ करती थी. अब उसी कांसेप्ट पर अंग्रेजी में इस तरह की किताबें निकलनी शुरू हुई हैं. अंग्रेजी के प्रकाशकों ने पुराने जमाने के सूत्र पकड़े और उन्हें अपनी मार्केटिंग का औजार बना लिया, लेकिन अफ़सोस कि यहां भी हिंदी के प्रकाशक पिछड़ गए. हिंदी के प्रकाशक तो अब भी सिनेमा के सौ साल का जश्न मना रहे हैं और अलग–अलग लोगों के पुराने लेखों को एक साथ छापकर किताब बना रहे हैं.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

घिरनी दादी

प्रज्ञा तिवारी

हम नौ साल में बिहा (ब्याह) गए थे बेटा. तुम्हारे दादा जी का तब सतरहवां साल शुरू हुआ था. हमारी छटपटाहट, हमारा डर, हमारा हदस और हमारा बचपन किसी को नहीं दिखता था. सबको जल्दी थी. जल्दी से हमको घरनी बना देने की. शुरू में बहुत घबराए, बहुत भागे. पर कहां तक? आंगन से छत तक, कमरा से बाथरूम तक. बस. तीन–साढ़े तीन महीना में पक्का घरनी बन ही गए.

लेकिन अपने कमरा में जाने को जो डर था, उसमें घरनी न बन पाए. बबलू के बाबू जी का भी दोस (दोष) नहीं था. नए–नए जवान हो रहे थे. इतनी गोरी मेहरारू मिल गई. अब नहीं रख पाए काबू. याद है हमको. ठीक छह महीने बाद सास ने हमको घर भेजा था. साथ में बबलू के बाबू जी और नौकर भी था. इक्का बाउनी नदी पार करता और हमारा घर आता, इससे पहले ही रोने लगे हम. खुसी (खुशी) का आंसू था, लेकिन लोग–बाग थोड़े ही समझते. बबलू के बाबू जी तो वापस जाने को तैयार. ऐसी कलपती हुई बहू को ले जाएंगे, तो सब कहेंगे कि बहू खुस (खुश) नहीं अपने ससुराल में. फिर नौकर के बहुत समझाने–बुझाने और मेरे एकदम दम साधकर चुप हो जाने पर इक्का आगे बढ़ा.

गांव पहुंचे, तो लगा जेल से छूट आए. अब तो हंसी आती है. वही जेल अब हमको सबसे ज़्यादा मुक्ति देती है. नहीं आने के लिए मां से लड़ाई किए, रूठे, रोए, कांपे, परारथना (प्रार्थना) तक कर डाले थे कि इक्का का घोड़ा मर जाए. बहुत बुरी लगी थी तब मां. बाउ जी भी. सभी लोग. बस वही देखे हुए हैं मां–बाउ जी को. फिर सबके मरने की ख़बर ही सुनते रहे. एक बार और मौक़ा मिला था जाने का. दो साल बाद. भइया की सादी (शादी) में. लेकिन, जाने की खुसी (खुशी) से ज़्यादा डर

वापस आने का लगा. फिर से उनको छोड़के आना पड़ेगा. फिर मां नहीं मानेगी. फिर हमको सब बुरे लगेंगे. फिर गुस्सा आएगा, रोना आएगा, दुःख होगा, घबराहट होगी, आने का पछतावा होगा. हमने सास को बोल दिया, हम नहीं जाएंगे.

घिरनी नाम था हमारा. गांव भर में चकरघिन्नी की तरह घूमा करते थे, इसलिए मां हमें घिरनी कहकर बुलाती थी. बाद में तो चलके इसका बहुत मतलब हो गया. हम अपने कमरा में नहीं जाते थे बेटा. सच कहते हैं. रात में सास सोने के लिए भेज देती थी. दूध का गिलास स्टूल पर रखके हम कमरा के पिछले दरवाजे से भाग जाते थे. फिर हमारे पीछे छपरन माई को लगाया गया. दरवाजे के बाहर पहरे पर बैठने लगी वह. तब हम फिर पलंग के नीचे छिपने लगे. पलंग के नीचे छिप जाते थे और वहीं सो जाते थे. बबलू के बाबू जी गुस्सा भी होते थे. फिर छपरन माई हमको बगल में बिठाके (बैठाकर) कहानी सुनाने लगी और हमारे सो जाने पर हमें कमरा में पलंग पर रख आती थी. हमसे झूठ बोलती रही कि रात में किसन जी (भगवान कृष्ण) हमको उठाके पलंग पर सुला आते हैं.

कहना नहीं चाहिए, पर जब बबलू के बाबू जी पढ़ाई पूरी करने बनारस गए, हम छपरन माई के गले लगकर रात में खूब रोए और छपरन माई को बोले कि अब हमको कहानी नहीं सुनना है. हम खुद सो जाया करेंगे. ऐसा लग रहा था कि कमरा में कोई ख़तरनाक राकस (राक्षस) रहा करता था, जो चला गया है. कमरा तब पहली बार ठीक से देखे हम. बबलू के बाबू जी छुट्टी में आते रहे. छपरन माई भी एक दिन बूढ़ी होके मर गई. कौन कहानी सुनाता. फिर पता ही नहीं चला कि किस उमर में हम बबलू की मां बने, किस उमर में मोनू की, कब अवधेस की और कब सबीता की. सब कहते थे कि बबलू के बाबू जी हमको बहुत प्यार करते थे, इसलिए चार बच्चे दिए हमको. फिर यह भी कहते हैं कि हम उनको अपने नाम जइसा घिरनी की तरह नचाए, इसलिए हमको छोड़ के चले गए. पता नहीं, क्या सच है बेटा. हम खुद ही नहीं जानते.

उस दूसरी औरत के बारे में सुनके कलेजा फटता था मेरा. बहुत गुस्सा आता था, बहुत दुःख, एकदम वैसे ही, जब मां इक्के पे हमको वापस यहां भिजवा दी थी. लेकिन, जब बाबू जी वापस घर आएं, तो फिर वही हदस. मुंह सूख जाए. छपरन माई की याद आने लगती थी. लगता था कि बस किसी तरह वापस चले जाएं और कमरा फिर से पूरा हमारा हो जाए. यह कैसा घिरनी था, समझ नहीं आता था हमको. आज भी नहीं आता. सास खटिया पर बैठी–बैठी कहती थी कि चार बच्चे हैं इसके, पति है. सुख से इसी खटिया पर बैठकर ठाठ वाला बुढ़ापा काटेगी. खूब हंसकर कहती थी कि घिरनी को आख़िर घरनी बना ही दिए हम. घिरनी नहीं रही अब यह. और, अपनी पीठ खुद ही थपथपाती थी. मानती बहुत थी वह हमको. समय से पहले ही चली गई. अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो देखती कि उसकी घरनी सुधरी नहीं. घिरनी की घिरनी ही बनी रह गई. कभी एक बेटा के घर, कभी दूसरे के घर, तो कभी तिसरे (तीसरे) के. बेटी के यहां दामाद को मां–बाबू जी हैं, नहीं तो साल में एक बार वहां भी रह आना पड़ता है, तीन–चार दिनों के लिए. सबके यहां हम घिरनी जैसे चक्कर काटते रहते हैं, बस उसकी घिरनी ही नहीं बन पाए, जिसकी घरनी थे. बनारस नहीं गए. कभी जाएंगे भी नहीं. पता नहीं गुस्सा से, दुःख से, डर से या घबराहट से, कलेजा फटता भी है, कलेजा हदसता भी है.

सच, घिरनी दादी आज भी बनारस नहीं गई. न ही अब उसके बबलू के बाबू जी आते हैं उसके आंगन. उसके कमरे का राक्षस चला गया. सास की खटिया को संभाल कर एक कोने में रख दिया है उसने. पांव में घिरनी डाले, सिर पर घरनी का आंचल लिए, पता नहीं वह कभी उस खटिया को देख भी पाती है या नहीं, जिस पर सुख से बैठकर ठाठ चलाते हुए बुढ़ापा काटने का सपना उसकी सास ने उसके लिए देखा था. हां, पिछले साल श्रावणी पूजा में जब वह अपने घर पर थी, तो शाम के समय गोधूलि बेला में उस खटिया के पायदान पर बैठे सुस्ताते देखा था मैंने उसे.■

feedback@chauthiduniya.com

> कंपनी ने एक प्रजेंटेशन के दौरान यह भी दिखाया कि तेल अवीव में प्रयोगशाला में विकसित की जा रही बायो कार्बनिक चार्जर प्रणाली किसी स्मार्टफोन की बैटरी को मात्र 30 सेकेंड में ही चार्ज कर सकती है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि यह चार्जर, बैटरी प्रौद्योगिकी को नए सिरे से विकसित करके तैयार किया गया है.

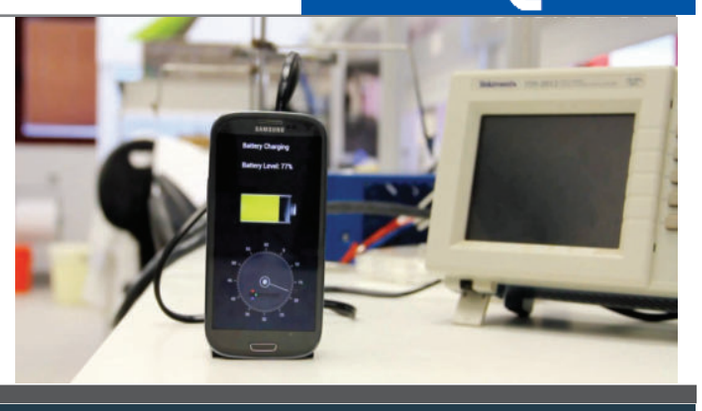

वॉट्सएप्प इस्तेमाल करने के आसान तरीक़े

प्रिंस भारद्वाज

आज कल अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं और स्मार्टफोन में कोई न कोई एप्पस जरूर मिल जाएगा. वाट्सएप्प की बात करें तो यह तो लगभग सभी के स्मार्टफोन में मिल जाएगा और आपस में बातचीत का सबसे प्रमुख जरिया बन गया है. आइए जानते हैं वॉट्सएप्प से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो सामान्यतः वॉट्सएप्प का प्रयोग करने वाले उपभोक्ता इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप इसका प्रयोगकर वॉट्सएप्प मैसेजिंग का और बेहतर तरीके से आनंद ले सकते हैं.

वॉट्सएप्प के मैसेज लॉक करना

आप अपने वॉट्सएप्प मैसेज को किसी के पहुंच से दूर और प्राइवेट रखना चाहते हैं तो अपने वॉट्सएप्प मैसेज को लॉक भी कर सकते हैं. वॉट्सएप्प के मैसेज को लॉक करने के लिए एक थर्ड पार्टी एप्प का इस्तेमाल करना होगा वॉट्सएप्प लॉक नाम के इस ऐप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने फोन में इनस्टॉल कर सकते हैं. इसके बाद वाट्सएप्प खोलने के लिए यूजर को पासवर्ड डालना होगा. ये ऐप्पस गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में उपलब्ध हैं. इस एप्प का एक वर्जन ब्लैकबेरी यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है जिसको ब्लैकबेरी स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

वॉट्सएप्प में पुराने मैसेज का बैकअप कैसे बनाए

आप अपने फोन को बदलना चाहते हैं और आपको वॉट्सएप्प मैसेज के डिलीट हो जाने का डर सताता है तो अब डरने की जरूरत नहीं है. जी हां अगर आप फोन को फॉर्मेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वॉट्सएप्प का बैकअप बना कर रख सकते है. आईओएस (ios) यूजर मैसेज बैकअप करने के लिए वॉट्सएप्प के सेटिंग्स में जाकर चैट सेटिंग में जाए और फिर वहां पर आप चैट बैकअप ऑप्शन पर जाकर बैकअप नाउ पर क्लिक करें. जबकि एंड्रायड यूजर वॉट्सएप्प के सेटिंग्स में जाकर चैट सेटिंग में जाए वहां बैकअप कन्वर्सेशन्स का ऑप्शन मिलेगा उसको सेलेक्ट करें और आपके वाट्सएप्प मैसेज चैट का बैकअप बन जायेगा पर इससे वॉट्सएप्प की मीडिया फाइल्स जैसे पिक्चर, वॉइस नोट्स या वीडियो क्लिप्स कॉपी नहीं होंगी. उसके लिए फाइल मैनेजर में जाकर वॉट्सएप्प में जाते हैं उसके बाद मीडिया पर जाकर मीडिया फाइल्स को अलग से कॉपी करना होगा.

आखिरी बार देखे गए मैसेज को हाइड करना

वॉट्सएप में लास्ट सीन (आखिरी बार कब वॉट्सएप्प देखा गया उसका समय) हाइड किया जा सकता है. उसके बाद किसी भी यूजर को यह नहीं दिखेगा की आप कब ऑनलाइन आए थे. अगर आप ऑनलाइन रहते हैं, तो सामने वाले को उस समय आप ऑनलाइन दिखाई देंगे एंड्रॉयड फोन में आपने वॉट्सएप्प के वर्जन को अपडेट कर लिया है तो इसमें कई लेटेस्ट विकल्प मिलेंगे. इसमें फोटो से लेकर लास्ट सीन तक कई प्राइवेसी सेटिंग्स मिल जाएंगी इसके लिए सेटिंग्स में जाकर अकाउंट में जाना होगा. उसके बाद प्राइवेसी में जाएं और लास्ट सीन में कई विकल्प मिलेंगे जैसे एवरीवन, माय कॉन्टेक्ट्स और नो बॉडी, इनमें से नो बॉडी पर क्लिक करते ही आपका लास्ट सीन टाइमस्टैम्प पूरी तरह से हाइड हो जाएगा.

आईओएस (IOS) यूजर्स केलिए

एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए लास्ट सीन हाइड करने का फीचर काफी पहले से ही उपलब्ध है. आईफोन में लास्ट सीन टाइमस्टैम्प सभी यूजर्स को एक साथ हाइड किया जा सकता है. हाइड करने के लिए–सेटिंग्स में जाकर चैट में जाएं और ऑप्शन सेलेक्ट करें वहां आपको लास्ट सीन टाइम स्टम्प ऑप्शन मिलेगा, यहां लास्ट सीन टाइमस्टैम्प को हाइड किया जा सकता है.

वॉट्सएप्प पर शॉर्टकट बनाना

आप किसी कॉन्टैक्ट का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो वॉट्सएप्प के लिए ऐसा भी किया जा सकता है. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी खास से वॉट्सएप्प पर बार-बार बात करते हैं. ऐसे में अपने वॉट्सएप्प कॉन्टैक्ट को होम स्क्रीन पर ला सकते हैं. इसके लिए किसी भी ग्रुप या कॉन्टैक्ट पर ज्यादा देर तक प्रेस कीजिए. इसके बाद ऑप्शन में ऐड कनवर्जेशन टू शॉर्टकट (Add conversation to shortcut) पर क्लिक कीजिए. ऐसा करने से आपका कॉन्टैक्ट होम स्क्रीन पर आ जाएगा.

ब्लूटिक्स हाइड करना

अभी तक वॉट्सएप्प ने हाइड ब्लू टिक्स फीचर नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही वॉट्सएप्प की तरफ से नए वर्जन के लिए हाइड रीड रिसिप्ट का फीचर आने वाला है. एक बार यह फीचर इंट्रोड्यूस हो गया तो यूजर्स अपने ब्लू टिक मार्क्स को हाइड कर सकेंगे. इसके लिए यूजर्स को प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर रीड रिसिप्ट्स फीचर को डिसएबल करना होगा.

कैसे करेंगे ब्लू टिक्स डिसएबल

इसके लिए सबसे पहले आपको अपडेटेड वॉट्सएप्प डाउनलोड करना होगा. अब आप फोन की सेटिंग्स में जाएं. उसके बाद सिक्योरिटी में जाकर चेक अननोन सोर्सेज पर जाएंगे जहां आपको गूगल प्ले के अलावा थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने की परमीशन भी देनी होगी, अब डाउनलोड की गई एपीके (apk) फाइल अपने फोन में इंस्टॉल कर लें, उसके बाद वॉट्सऐप्प की सेटिंग्स में जाएंगे उसके बाद अकाउंट्स में जाएं वहां प्राइवेसी पर जाकर रीड रिसिप्ट्स (Read receipts) फीचर को अनचेक कर दें.

वॉट्सएप्प में नंबर बदलना

आपने वॉट्सएप अकाउंट में पुराना नंबर डाला है और नए नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिना किसी झंझट के उसे बदला जा सकता है. ऐसा करने के लिए आप सेटिंग में जाएं उसके बाद अकाउंट्स में जाएं और आखिरी में चेंज नंबर के ऑप्शन पर जाएं. यहां पुराना नंबर और नया नंबर दोनों एंटर करें फिर ऊपर दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और कुछ समय में आपका नंबर बिना किसी झंझट के चेंज हो जाएगा साथ ही अगर आप अपना पुराना नंबर नई सिम के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी वॉट्सएप्प अकाउंट को कुछ नहीं होगा.

मैसेज का काउंटर देखना

आप यह है देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक कितने मैसेज वॉट्सएप्प पर भेजे हैं या रिसीव किया है तो यह जानने के लिए आप सेटिंग्स में जाकर अकाउंट में जाएं नेटवर्क यूसेज पर क्लिक करें इसमें भेजे गए या रिसीव मैसेज के साथ कितने डाटा का प्रयोग मीडिया को भेजने और पाने में खर्च किया है उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सुपर पॉवर सेवर स्मार्टफोन कैनवस ह्यू

माइक्रोमैक्स ने एक नया स्मार्टफोन कैनवस ह्यू लॉन्च किया है जो सुपर पॉवर सेविंग मोड से लैस है. इस फोन की बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद एक महीने का स्टैंडबाय टाइम उपलब्ध कराती है. इस डुअल सिम फोन की स्क्रीन 5 इंच की है जो 1280 गुणा 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. साथ ही इसमें एमोलेड डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी है और यह एंड्रॉयड किट कैट पर आधारित है. इसका रियर कैमरा 8 एमपी का ऑटो फोकस है और इसमें कई तरह के सेंसर हैं और इसका फ्रंट कैमरा 2 एमपी का है. यह फोन 1.3 गीगाहर्ट्ज मीडियाटेक एमटी 6582 क्वॉड कोर प्रोसेसर से लैस है. इसमें 1 जीबी रैम है और यह फोन ओएस 4.4 किटकैट पर आधारित है. अगर ऑडियो की बात करें तो इसमें 3.5 मिमी ऑडियो जैक, एफएम रेडियो है. अन्य फीचर्स- 3जी, एचएसपीए, वाई-फाई, ब्लूटुथ 4.0, जीपीएस उपलब्ध है. इस फोन की बैटरी 3,000 एमएएच की है जो 9 घंटे का टॉकटाइम देती है. इसकी कीमत 10,999 रुपये है. ■

डोंगल टीवी को बदल देगा कम्प्यूटर में

इंटेल कंपनी ने एक ऐसा डोंगल लॉन्च किया है जो स्मार्ट टीवी को फुल फीचर्स वाले कम्प्यूटर में बदल देगा. इंटेल का नया कम्प्यूट स्टिक नामक डोंगल टीवी को कम्प्यूटर में बदल देगा. इसमें विंडोज 8.1 या लाइनक्स प्री-इन्स्टॉल्ड रहेगा. इस स्टिक के विंडोज वर्जन की कीमत लगभग 9284.93 रुपये है और लाइनेक्स वर्जन की कीमत लगभग 5546.03 रुपये है. इस कम्प्यूट स्टिक में इतनी पावर है कि ये किसी भी एचडीएमआई मॉनिटर (मल्टीमीडिया मॉनिटर) में लगाई जाए तो उसे किसी कम्प्यूटर में बदल सकती है. ये कम्प्यूट स्टिक फुल साइज की है और इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट्स दिए गए हैं. 4 इंच के साइज वाली ये स्टिक कई तरह के कनेक्टिवटी फीचर्स जैसे ब्लूटुथ 4.0, वाईफाई और यूएसबी देती है. विंडोज 8.1 वर्जन वाली स्टिक में 32जीबी की इंटरनल मेमोरी और 2जीबी रैम दी गई है. इसके अलावा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वर्जन में 8जीबी इंटरनल मेमोरी और 1जीबी रैम दी गई है. इस डोंगल में माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिसकी मदद से डिवाइस की मेमोरी बढ़ाई जा सकती है. इंटेल की ये स्टिक इस साल के अंत तक बाजार में आ जाएगी. ■

2 मिनट में स्मार्टफोन होगा चार्ज

इजरायल की कंपनी स्टोरडॉट ने बेहद तेज स्पीड वाला मोबाइल फोन चार्जर बनाया है जो स्मार्टफोन की बैटरी को महज दो मिनट में चार्ज कर सकता है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि बैटरी चूंकि दो मिनट में चार्ज हो जाती है, लिहाजा दिन में दो बार चार्ज कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी. कंपनी ने एक प्रजेंटेशन के दौरान यह भी दिखाया कि तेल अवीव में प्रयोगशाला में विकसित की जा रही बायो कार्बनिक चार्जर प्रणाली किसी स्मार्टफोन की बैटरी को मात्र 30 सेकेंड में ही चार्ज कर सकती है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि यह चार्जर, बैटरी प्रौद्योगिकी को नए सिरे से विकसित करके तैयार किया गया है. इस बैटरी में होने वाले रिऐक्शन सामान्य बैटरी में होने वाले रिऐक्शनों से पूरी तरह भिन्न होते हैं और इसमें खासतौर से तैयार किए गए कृत्रिम कार्बनिक एटम शामिल होते हैं. ■

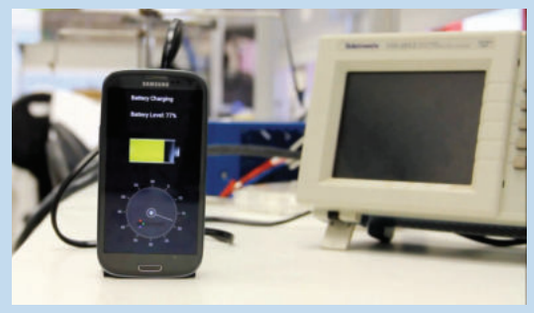

बजाज पल्सर 200एसएस जल्द होगी लॉन्च

बजाज पल्सर 200एसएस कभी-कभी भी लॉन्च हो सकती है. नई बाजाज पल्सर 200एसएस को युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कंपनी इसे फुल फेयरिंग के साथ लेकर आई जिसके चलते यह काफी बोल्ड दिखती है. इसके अलावा इसमें डयूल टोन कलर दिया गया है जो काफी आकर्षक है. पल्सर 200 एनएस के प्लेटफॉर्म पर बनी यह फ्रंट फेयरिंग के साथ-साथ लार्ज ट्रांसपेरेंट विंड शील्ड, ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैंप तथा एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स जैसे फीचर्स से लैस है. इसे स्पोर्टी लुक देने के लिए फ्यूल टैंक कवर, स्पिलिट सीट, स्पोर्टी साइड स्लंग टाइम मफलर तथा यूनिक टेल लैंप से लैस किया गया है. बजाज पल्सर 200एसएस में 199.5 सीसी, सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड, 4वॉल्व, ट्रिपल स्पार्क इंजन लगा है. यह 23.2 बीएचपी का पावर तथा 18.3 एनएम का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करती है. यह पहले आई पल्सर 200 एनएस से ज्यादा माइलेज देने वाली भी है. इसकी कीमत लगभग 1 लाख 25 हजार रुपये होगी ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आईसीसी विश्वकप 2015

किसमें कितना है दम

क्रिकेट के सबसे बड़े खिताब के लिए एक बार फिर जंग वेलेंटाइन्स-डे (14 फरवरी) के दिन शुरू हो रही है. इसमें खेलने वाली सभी 14 टीमों की घोषणा हो चुकी है. सभी टीमों ने विश्वखिताब जीतने के लिए कमर कस ली है. इस बार टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में विश्व चैंपियन का खिताब बचाने उतर रही है. खिताब बचाने की इस जंग में उन्हें सबसे कड़ी टक्कर मेजबान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और पाकिस्तान से मिलने वाली है. वेस्टइंडीज की टीम अपने अंतर्द्वंद में उलझी हुई है. ऐसे में कौन सी टीम विश्व चैंपियन बनेगी यह तो 29 मार्च को फाइनल मैच में साफ हो पाएगा. आईए टीमों की विश्वकप जीतने की संभावनाओं पर नज़र डालते हैं.

नवीन चौहान

साल 2011 में 28 साल बाद विश्व चैंपियन बनने वाली भारतीय टीम इस बार अपने विश्व चैंपियन के खिताब को बचाने के लिए उतर रही है. विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जिन खिलाड़ियों को जगह दी गई है उनमें से कप्तान धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना और आर अश्विन के अलावा अन्य किसी खिलाड़ी को विश्वकप में खेलने का अनुभव नहीं है. अक्षर पटेल और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है. जिनके पास दस से भी कम अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मैच खेलने का अनुभव है.हर बार की तरह इस बार भी बल्लेबाजी भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी है. विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाजों के इर्द-गर्द नज़र आएगी. शिखर धवन और तेज गेंदबाजों का फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय हैं, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही त्रिकोणीय श्रृंखला में सभी खिलाड़ियों के पास अपने फॉर्म को वापस पाने और कमियों को पूरा करने का सुनहरा मौका है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी भी यह कह चुके हैं कि टेस्ट सीरीज के परिणाम के मद्देनज़र भारतीय टीम को बिलकुल भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए. भारतीय टीम के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि विश्वकप से ठीक पहले भारतीय टीम दो महीने से ऑस्ट्रेलियाई माहौल में है. टीम इंडिया यहां की परिस्थितियों के अनुकूल ढ़ल चुकी है. भारतीय टीम लंबे समय से एकदिवसीय फॉर्मेट में टॉप थ्री टीमों में बनी हुई है. गेंदबाज जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे टीम इंडिया के खिताब बचाने की संभावनायें उतनी प्रबल हो जाएंगी.

2011 में टीम इंडिया ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का 12 साल से चल रहा विजय रथ अहमदाबाद में रोका था. चार बार की विश्व चैंपियन और मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार भी विश्वकप जीतने की प्रबल दावेदार है. इसके लिए टीम की कमान माइकल क्लार्क के हाथों में सौंपी गई है. फिलहाल वह चोटिल हैं यदि वह अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाते हैं तो टीम की कमान जॉर्ज बेली के हाथों में आ जाएगी. जो कि धोनी की तरह कैप्टन कूल माने जाते हैं साथ ही वह अपनी बेहतरीन कप्तानी का परिचय दे चुके हैं. घरेलू सरजमीं पर घरेलू दर्शकों के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा पाना दूसरी टीमों के लिए नामुमकिन सा काम है. टी-20 क्रिकेट का असर एकदिवसीय क्रिकेट में आने के बाद बड़े से बड़े स्कोर चेज किए जा रहे हैं. ऐसे में घर में खेलने का सीधा फायदा ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिलेगा. टीम की बल्लेबाजी की कमान डेविड वॉनर, एरोन फिंच, स्टीव स्मिथ, शेन वाटसन और जॉर्ज बेली जैसे बल्लेबाजों के हाथों में है. वहीं गेंदबाजी की कमान मिशेल जॉनसन जैसे अनुभवी गेंदबाज के हाथों में है. ऐसे में ग्लैन मैक्सवेल, जेम्स फॉक्नर और मिशेल मार्श जैसे खिलाड़ियों की टीम में उपस्थिति किसी भी समय मैच का रुख बदलने का माद्दा रखती है. ऐसे में मेजबान ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड पांचवीं बार विश्वखिताब जीतने में सफल हो सकती है.

तीन बार विश्वकप के फाइनल में पहुंचने वाली इंग्लैंड आखिरी बार 1992 में विश्वकप के फाइनल में पहुंचा थी. इस बार इस सपने को पूरा करने के लिए आखिरी समय में कप्तानी टेस्ट कप्तान एलिएस्टर कुक से छीनकर आयरलैंड की ओर से खेल चुके इयान मॉर्गन को सौंप दी गई है. कुक को अंतिम पंद्रह में भी शामिल नहीं किया गया. भारत और श्रीलंका के बेहद खराब दौरे के बाद इंग्लैंड के पास अपने खोये विश्वास को वापस पाने का आखिरी मौका भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही ट्रायंगुल सीरीज है. चयनकर्ताओं ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन पर विश्वास जताया है, साथ ही स्टुअर्ट ब्रॉड को भी टीम में जगह दी गई है. लेकिन केविन पीटरसन और कुक को टीम में शामिल न करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अनुभवी बल्लेबाजों को विश्वकप जैसी प्रमुख प्रतियोगिता में भी तरजीह क्यों नहीं दी गई. जबकि पीटरसन ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रही बिगबैश टी-20 में खेल रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं. चुनी गई टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ियों को तरजीह दी गई है, लेकिन टीम में स्टार और अनुभवी बल्लेबाजों की कमी साफ नज़र आ रही है ऐसे में इंग्लैंड के लिए चैंपियन बनने का सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है.

विश्व की छह बार की सेमी-फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड (1975,1979,1992,1999,2007,2011) इस बार बतौर मेजबान विश्वकप के फाइनल में पहुंचने और विश्वकप जीतने की कोशिश करेगी. पिछले दो सालों में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को हराया है. ब्रैडन मैक्लम की कप्तानी में टीम अनुशासित हो गई है. विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में डेनियल विटोरी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को भी जगह दी गई है यह उनका पांचवां विश्वकप होगा. इसके साथ की केन विलियमसन और कोरी एंडरसन जैसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है. ब्लैक कैप्स हर बार की तरह ब्लैक हॉर्स होंगे. उनकी टीम में बहुत से स्टार खिलाड़ी नहीं हैं बावजूद इसके यह टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है.

विश्वकप के लिए क्वालीफाई करने वाले देश और टीमें

दक्षिण अफ्रीका

एबी डिविलियर्स(कप्तान), हाशिम अमला, काइल एबोट, फरहान बेहरडिअन, क्विंटन डी-कॉक(विकेट कीपर), जे पी डुमिनी, फेप-डू-प्लेसिस, इमरान ताहिर, डेविड मिलर, मोर्नी मोर्केल, वेन पार्नेल, एरोन फेंगिसो, वेरनॉन फिलेंडर. रिली रॉसो, डेल स्टेन.

भारत

महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर-कप्तान), शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रविंद्र जड़ेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, स्टुअर्ट बिन्नी.

न्यूजीलैंड

ब्रैंडन मैक्लम (कप्तान), ट्रेंट बॉउल्ट, ग्रैंच एलिओट, टॉम लैटहेम, मार्टीन गुप्टिल, मिचेल मैक्लैघन, नाथन मैक्लम, काइले मिल्स, एडम मिलने, डेनियल विट्टोरी, केन विलियमसन, कोरी एंडरसन, टिम साउदी, ल्यूक रोंची(विकेटकीपर), रॉस टेलर.

पाकिस्तान

मिसबाह-उल-हक़(कप्तान), अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़. सरफराज़ अहमद,यूनिस खान, हरिस सोहेल, उमर अकमल, सोहेब मक़सूद, शाहिद अफरीदी, यासिर शाह, मोहम्मद इरफान, जुनैद खान, एहसान आदिल, सोहेल खान,वहाब रियाज.

इंग्लैंड

इयान मॉर्गन (कप्तान), मोइन अली, जेम्स एंडरसन, गैरी बैलेंस, इयान बेल, रवि बोपारा, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोस बटलर, स्टीवेन फिन,ऐलेक्स हेल्स, क्रिस जॉर्डन, जॉय रूट, जेम्स टेलर, जेम्स ट्रेडवेल, क्रिस वोक्स.

श्रीलंका

एंजेलो मैथ्यूज (कप्तान), तिलकरत्ने दिलशान, कुमार संगकारा (विकेटकीपर), महेला जयवर्धने, लहीरू थिरीमाने, दिनेश चांदीमल, दिमुथकरुणा रत्ने, जीवन मेंडिस, थिसारा परेरा, सौरंग लकमल, लसिथ मलिंगा (फिटनसे). धम्मिका प्रसाद, नुवान कुलशेखरा, रंगना हीरथ, सचित्र सेनानायके.

वेस्टइंडीज

जेसन होल्डर (कप्तान), मार्लोन सेमुअल्स, सुलेमान बेन, डैरेन ब्रेवो, जॉनेथन कॉर्टर, शेल्डन कॉटरेल, क्रिस गेल, सुनील नारायण, दिनेश रामदीन (विकेट कीपर), केमर रोच, आंद्रे रसल, डैरेन सामी, लिंडल सिमंस, डेवेन स्मिथ, जेरोम टेलर.

बांग्लादेश

तमीम इक़बाल, अनामुल हक़, सौम्य सरकार, मोमिनुल हक़, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, मेहमूद उल्लाह, नासिर हुसैन, शब्बीर रहमान, मुशर्रफ मोर्तजा(कप्तान), ताश्किन अहमद, अल-अमीन हुसैन, रुबेल हुसैन, अराफात सनी, तैजुल इस्लाम.

ऑस्ट्रेलिया

माइकल क्लार्क (कप्तान), जॉर्ज बेली (उप-कप्तान), डेविड वॉनर, एरॉन फिंच, शेन वाटसन, स्टीव स्मिथ, ब्रैड हैडिन (विकेट-कीपर), ग्लैन मैक्सवेल, मिशेल मार्श, जेम्स फॉक्नर, मिशेल जॉनसन, मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, पेट कमिन्स, जेवियर डोहर्टी.

अफ़ग़ानिस्तान

मोहम्मद नबी (कप्तान), नौरोज मंगल, असगर स्तानिकजई, समीउल्लाह शेनवारी, अफसर जज़ाई (विकेट कीपर), नज़ीबुल्लाह ज़ादरान, नासिर जमाल, मीरवाइज़ अशरफ, गुलबदिन नेब, हामिद हसन, शपूर ज़ादरान, दौलत ज़ादरान, आफताब आलम, जावेद अहमदी, उसमान घानी.

जिंबाब्वे

एल्टन चिकमबुरा (कप्तान), सिकंदर रज़ा, रेगिस चकाब्वा, टेंडई चतारा, चामू चिभाभा, क्रेग इरविन, टफाड्जवा कमुनगोज़ी, हैमिलटन मसाक्ज्दज़ा, स्टुअर्ट मैट्सीकेनयेरी, सोलोमेन मायरे, तवांडा मुपारिवा, तिनाशी पानायानगर, ब्रेंडेन टेलर, प्रोस्पेर उत्सेया, सीन विलियम्स.

आयरलैंड

विलियम पोटर्फील्ड (कप्तान), एंड्रयू बालबिर्नी, पीटर चेज, एलेक्स कुसैक, जॉर्ड डॉकवेल, एड जॉयस, एंड्रयू मैकब्रायन, जॉन मूनी, टिम मुरटैग, केविन ओ ब्रायन, नेल ओ ब्रायन (विकेट कीपर), पॉल स्टरलिंग, स्टुअर्ट ऑमसन, गैरी विलसन (विकेट कीपर), क्रैग यंग.

स्कॉटलैंड

प्रीस्टन मोमसेन (कप्तान), कोइट्ज़र, रिची बैरिंगटन, फेडरिक कोलमैन, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), जोशुआ डेवी, एलासडायर इवान्स, हमीश गार्डिनर, माजिद हक़, माइकल लीस्क, मैट मैकहैम, कैलम मैक्लियोड़, सैफियान शरीफ, रॉबर्ट टेलर, लेन वाइर्ला.

यूएई

खुर्रम खान (कप्तान), मोहम्मद तौकीर (उप कप्तान), स्वनिल पाटिल, सक्लैन हैदर , अमजद जावेद, शैमान अनवर., अमजद अली, नासिर अज़ीज, रोहन मुस्तफा, मंजुला गुरुगी, एंद्री बेरेंजर, फहाद अल हाशमी, मुहम्मद नवीद, कामरान शहज़ाद, कृष्णा कराते.

विश्वकप में चोकर्स के रूप में विख्यात दक्षिण अफ्रीकी टीम एक बार फिर मजबूत दावेदारी पेश करती दिखाई देगी. टीम की कमान एबी डिविलियर्स के हाथों में है. उन्हें हाशिम अमला, फेप-डु-प्लेसिस और किलर मिलर कहलाने वाले डेविड मिलर जैसे बेहतरीन बल्लेबाजों का सहयोग मिलता दिख रहा है. तेज गेंदबाजी की कमान डेल स्टेल, मोर्नी मोर्केल, वेरनॉन फिलेंडर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के हाथों में है जबकि स्पिन आक्रमण इमरान ताहिर संभालेंगे. कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीकी टीम एक बार फिर संतुलित दिखाई दे रही है. जहां अनुभवी और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है, लेकिन चुनौती इस बार भी बड़े मैचों के दबाव में नहीं बिखरने से बचने की होगी. अगर दक्षिण अफ्रीकी टीम ऐसा कर पाती है. तो 1992 और 1999 के विश्वकप की तरह कुछ अप्रत्याशित करती दिखाई देगी.

जो टीमें चुनी गईं हैं उनमें श्रीलंका की टीम अनुभव के आधार पर सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है. श्रीलंका की टीम में कुमार संगकारा, महेला जयवर्धने, लसिथ मलिंगा, तिलकरत्ने दिलशान जैसे खिलाड़ी हैं जिनके पास दो लगातार दो विश्वकप फाइनल खेलने का अनुभव है. इन खिलाड़ियों ने भी सचिन तेंदुलकर की तरह अपने क्रिकेट जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं लेकिन विश्वविजेता बनने का उनका ख्वाब अभी भी अधूरा है. पिछला टी-20 विश्वकप भी श्रीलंका ने ही जीता है. उसमें भी इन अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन योगदान रहा. पिछले चार टी-20 विश्वकप में भी श्रीलंका तीन बार 2009, 2012, 2014 में फाइनल में पहुंची लेकिन उसका विश्व विजेता बनने का सपना 2014 में पूरा हो सका.

वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर अंतर कलह से जूझ रही है. ऐसे में दो बार की विश्वचैंपियन टीम का विश्वकप जैसी बड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन मजह संयोग ही हो सकता है. एक नए और गैरअनुभवी 23 वर्षीय गेंदबाज जेसन होल्डर को टीम का कप्तान बनाया जाना हास्यास्पद निर्णय है. डेवेन ब्रेवो और केरन पोलार्ड जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह भी नहीं दी गई है ऐसे में सारा दारोमदार क्रिस गेल के ऊपर आ गया है. सुनील नारायण स्पिन गेंदाबाजी में थोड़ा बहुत कमाल दिखा सकते हैं. इस विश्वकप के बाद भी टीम का सुनहरा इतिहास ही याद किया जाएगा. वेस्टइंडीज की टीम कोई बड़ा उलटफेर नहीं करने जा रही है. गेल का संभवत: यह आखिरी विश्वकप है और वह दक्षिण अफ्रीका में टी-20 मैचों के फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो कुछ उनकी बेहतरीन पारियां विश्वकप में देखने को मिल सकती हैं.

पाकिस्तान की टीम को स्टार गेंदबाज सईद अजमल की कमी खलेगी, लेकिन बावजूद इसके उनकी टीम नॉकआउट दौर में उम्दा गेंदबाजी और सधी हुई बल्लेबाजी की बदौलत पहुंच जाएगी, उनके भी कैंपेन की शुरुआत भारत के साथ 15 फरवरी को है. इस हाइ प्रेशर मैच में जो भी टीम जीत हासिल होगी. विश्वकप में आगे की राह उसके लिए आसान हो जाएगी.

बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बेहद ही खराब दौर से गुजर रही है. पिछले साल जिंबाब्वे को टेस्ट सीरीज में 3-0 और एकदिवसीय मैचों में 5-0 से सूपड़ा साफ कर दिया इसके अलावा पिछले साल उन्होंने प्रशंसकों को खुशी मनाने का और कोई मौका नहीं दिया. बांग्लादेश ने एकदिवसीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराकर और 2007 के विश्वकप में भारत को हराकर विश्वकप से बाहर करने जैसे बड़े कारनामे किए थे. ऐसे में उनके सामने अपने प्रदर्शन के उस स्तर तक पहुंचने की चुनौती होगी. टीम को जीत की राह पर लाने का सारा दारोमदार नए कप्तान मुर्शरफ मोर्तजा, ऑल राउंडर साकिब-अल-हसन और विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम पर होगा.

जिम्बाब्वे एक बार फिर से विश्व क्रिकेट में अपनी जड़ें जमाने के लिए प्रयासरत है. यूएई की टीम ने दूसरी बार विश्वकप के लिए क्वालीफाई किया है, पिछली बार 1996 में यूएई एक भी मैच नहीं जीत सकी थी. इस बार भी कुछ ऐसा भी हो. स्कॉटलैंड की टीम ने तीसरी बार विश्वकप क्वालीफाई किया है. उससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है. अफगानिस्तान को पूल ए में जगह मिली है. जहां उसका मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड जैसी टीमों से होना है. लेकिन पूल में उनके साथ बांग्लादेश और स्कॉटलैंड है. अफगानिस्तान कम से कम इन दोनों टीमों के खिलाफ मैच जीतना चाहेगी. यदि वह ऐसा करने में कामयाब रहती है तो विश्वकप में उनके पदार्पण को बेहद सफल माना जाएगा. हालांकि नवंबर में यूएई के खिलाफ उन्हें 1-3 से हार का सामना करना पड़ा इसके अलावा हाल ही में दुबई में आयरलैंड के खिलाफ मिली हार से टीम का मनोबल कमजोर है. ऐसे में अफगानिस्तान से किसी बड़े उलटफेर की आशा करना बेमानी है. उनकी बल्लेबाजी कमजोर है. लेकिन गेंदबाजी मज़बूत पक्ष है. आयरलैंड की टीम ने पिछले विश्वकप में केविन ओ ब्रायन के एक शतक की बदौलत इंग्लैंड के साथ मैच टाई हुआ था. 2007 में आयरलैंड सुपर एट स्टेज में पहुची थी. उसने पहले राउंड में पाकिस्तान को और बांग्लादेश को हराया और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच टाई रहा था. क्रिकेट अनिश्चत्ताओं का खेल है यदि इस बार भी कुछ ऐसा उलटफेर हो जाए तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए.■

navinonline2003@gmail.com

फिल्मों में विवाद यानी सफलता की गारंटी

एक तरफ आमिर खान की फिल्म पीके को लेकर विवाद हो रहा था दूसरी तरफ यह फिल्म सफलता के झंडे गाड़ती जा रही थी, जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया फिल्म को देखने की ललक लोगों में बढ़ती चली गई. यह फिल्म 400 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई. आमिर खान और राजू हीरानी के निर्देशन में बनी पीके को मुख्य रूप से हिंदू धर्म को केंद्र में रखकर बनाया गया है. कहीं कहीं दूसरे धर्मों पर धीरे से कटाक्ष करते हुए राजू हीरानी निकल गए. हिंदू संगठनों को इस बात पर आपत्ति है कि अगर कुरीतियां ही दिखानी थीं तो सभी धर्मों पर बराबर नज़र रखी जानी चाहिए थी. लेकिन इस मामले में फिल्म बैलेंस नज़र नहीं आई. कई लोगों को यह फिल्म एकतरफा नज़र आई. अब यह एक रवायत बनती जा रही है कि फिल्मों को व्यासायिक सफलता दिलाने के लिए उनमें विवाद का तड़का डाल दिया जाता है. आईए ऐसी ही कुछ विवादित फिल्मों पर नज़र डालते हैं.

राजलक्ष्मी मल्ल feedback@chauthiduniya.com

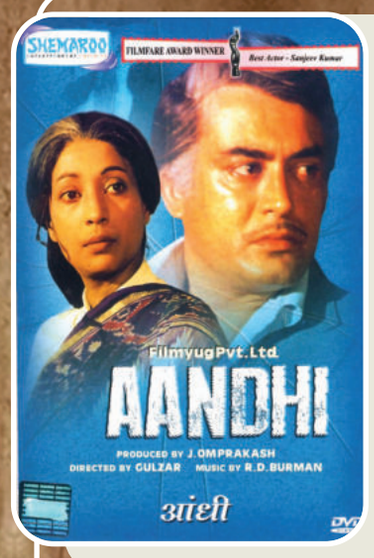

आंधी: साल 1975 में गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म आंधी के जरिए विवादों की ऐसी आंधी उठी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया. कथित रूप से इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म की नायिका सुचित्रा सेन का पूरा गेट-अप उनसे प्रेरित था. बालों के कुछ हिस्सों की सफेदी वाले हेयर स्टायल और एक हाथ से साड़ी का पल्लू संभालने और दूसरे हाथ से लोगों को देखकर हाथ हिलाने की उनकी शैली को सुचित्रा सेन ने रुपहले पर्दे पर कॉपी किया था. प्रतिबंध से नाखुश फिल्म के निर्माता ने बाद में इसमें एक संवाद जोड़ा जिसमें नायिका अपने पिता से कहती है कि इंदिरा गांधी उसकी आदर्श है और वह उनकी तरह देश की सेवा करना चाहती है. 1977 के आम चुनावों के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनने पर आंधी का राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रीमियर हुआ. इस फिल्म ने उस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का ख़िताब जीता.

सत्यम शिवम सुंदरम् - साल 1978 राज कपूर के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म का टाइटल किसी धार्मिक फिल्म जैसा था, लेकिन फिल्म हकीकत में ऐसी नहीं थी. शो-मैन के नाम से प्रसिद्ध राजकपूर ने सत्तर अस्सी के दशक में जीनत अमान और शशि कपूर को लेकर यह फिल्म बनाई थी. फिल्म अपनी कहानी से ज्यादा फिल्म में जीनत अमान के अंग प्रदर्शन की वजह से ज्यादा चर्चा में थी. उस दौर में जीनत अमान पर ऐसे दृश्य फिल्माये गए जैसा उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था. फिल्म में शशि कपूर और जीनत के बीच कई इंटीमेट दृश्य भी फिल्माए गए थे. इस वजह से फिल्म का बहुत विरोध हुआ और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई. विवादों की वजह से यह फिल्म सफलता के शिखर पर पंहुच गई. फिल्म को 26 वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में दो अलग-अलग अवार्ड्स से सम्मानित किया गया.

जोधा अकबर - लगान जैसी फिल्म निर्देशित करने वाले आशुतोष गोवरिकर फ़िल्म जोधा-अकबर लेकर आए. मुग़ल बादशाह अकबर और जयपुर की राजकुमारी जोधा से विवाह और मोहब्बत को पर्दे पर उतारने का प्रयास किया गया. क्षत्रिय और राजपूत संगठनों ने इस फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इस फिल्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सवाल भी खड़े किए. अदालत में भी फिल्म को चुनौती दी गई. फ़िल्म जोधा-अकबर पर राजस्थान के राजपूत संगठनों को सख्त ऐतराज़ है, क्योंकि उनके ख़याल से यह फ़िल्म राजपूत समाज के लिए अपमानजनक है और ऐसी प्रस्तुति इतिहास में वर्णित तथ्यों के ख़िलाफ़ है. राजपूतों की करणी सेना ने फ़िल्म के विरोध में प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर इसे सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे. विरोध करने वालों का कहना था कि जोधा कभी अकबर की पत्नी थी ही नहीं, हालांकि फ़िल्म को व्यावसायिक उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. जयपुर राजपरिवार ने फ़िल्म का समर्थन किया और कहा है कि इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है. हालांकि फ़िल्म के निर्माता आशुतोष गोवरिकर कह चुके थे कि फ़िल्म में काल्पनिकता का पुट है और यह कोई ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं है. हिंदी फिल्मों की जातीय परंपरा में बनी यह आशुतोष गोवरिकर की उल्लेखनीय और दर्शनीय फिल्म है. फिल्म जोधा अकबर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ख़िताब से सम्मानित किया गया.

इंसाफ का तराजू: साल 1980 में बनी यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म लिपिस्टिक पर आधारित थी. फिल्म में बलात्कार का आरोपी कानूनी दांवपेच की वजह से बाइज्जत बरी हो जाता है. इस फिल्म पर काफी विवाद हुआ लेकिन क़ानून की विसंगतियों को लेकर सवाल भी खड़े हुए. इस फिल्म की सफलता को देखते हुए तेलुगू में फिल्म ईडी नयायम ईडी धर्मम (1982) का निर्माण किया गया. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी.

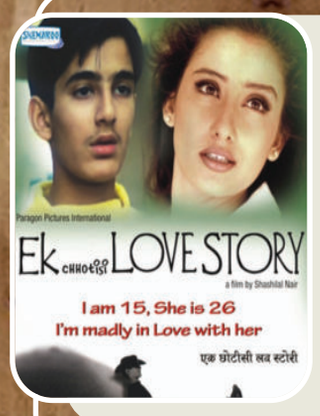

एक छोटी सी लव स्टोरी- वर्ष 2002 में शशिलाल नायर के निर्देशन में बनी फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी में मनीषा कोईराला मुख्य भूमिका में थीं. इस फिल्म में 15 साल के युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती दिखाई गई है. जो अपने सामने वाली सोसायटी के एक फ्लैट से टेलीस्कोप के जरिये एक 26 साल की लड़की को देखता है और उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है. फिल्म की हीरोइन मनीषा कोईराला ने फिल्म के डायरेक्टर पर उनकी डुप्लीकेट का प्रयोग करते हुए बेहद अश्लील दृश्य फिल्म में डालने का आरोप लगाया और इस पर रोक लगाने की मांग की. इस फिल्म के विवाद को बढ़ता देख देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म को देखने के लिए लंबी कतारें लग गईं.

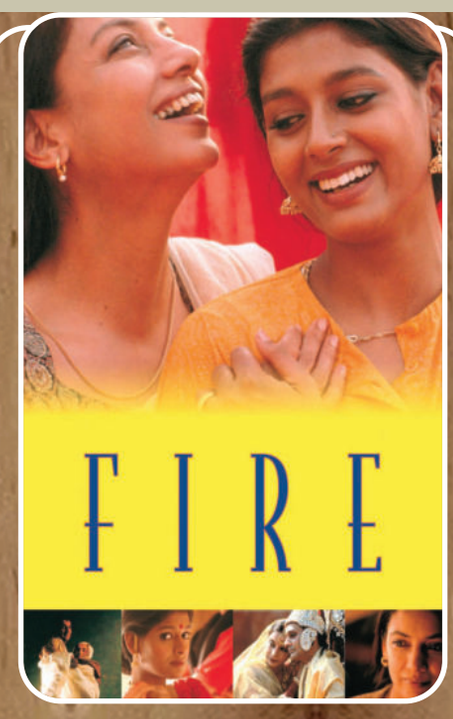

फायर: साल 1996 में दीपा मेहता ने समलैंगिक संबंधों पर आधारित फिल्म फायर बनाई, तो पूरा देश आग-बबूला हो गया, इस फिल्म में शबाना आजमी और नंदिता दास मुख्य भूमिका में थीं. सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस फिल्म का जमकर विरोध किया. देश भर में कई जगह सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की गई.

बैंडिट क्वीन- साल 1994 में शेखर कपूर की महत्वकांक्षी फिल्म का पर्दे पर उतरने से पहले ही विरोध शुरु हो गया था. फिल्म में कई विवादास्पद दृश्य थे तो गालियों और हिंसा की भरमार थी. हालांकि यह फिल्म फूलन देवी के दर्दनाक जीवन का एक सच्चा चित्रण था. इस फिल्म की दुनिया भर में खूब प्रशंसा हुई थी. रेप सीन को लेकर विवाद हुआ था. बैंडिट क्वीन का विरोध फूलन देवी ने खुद किया था और रिलीज रोकने का प्रयास किया था. बैंडिट क्वीन ने 2.53 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार मिले. इस फिल्म की समाज सेविका अरुंधति रॉय ने बहुत आलोचना की थी और फिल्म की समीक्षा करते हुए उसे द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक करार दिया था.

ओह माय गॉड-उमेश शुक्ल की निर्देशन में धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों और आडम्बरों पर यह फिल्म आधारित है. इस फिल्म में भगवन को एक मॉडर्न रूप दिया गया है और भगवान के ऊपर अदालत में मुक़दमा चलता दिखाया गया है. देश के कई हिस्सों में इस फिल्म को लेकर विरोध दर्ज कराया गया और फिल्म पर बैन लगाने की मांग हुई. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए अक्षय कुमार, परेश रावल और फिल्म के निर्माता को एक नोटिस जारी किया. 20 करोड़ की लगत से बनी इस फिल्म ने तकरीबन 80 करोड़ रुपये की कमाई की.

ब्लैक फ्राइडे- वर्ष 1993 में हुए मुंबई धमाकों पर अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे साल 2004 में रिलीज हुई. यह फिल्म उन धमाकों की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी. फिल्म की कहानी बम विस्फोटों के पीछे की साजिश और योजना बनाने पर आधारित है. इस फिल्म को पत्रकार हुसैन जैदी की पुस्तक से लिया गया है, फिल्म की रिलीज होने की पूर्व संध्या पर इस फिल्म को बैन कर दिया गया था. इसके बाद दो साल तक इस फिल्म को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया था.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

26 जनवरी–01 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

दही-चूड़ा में भी नहीं मिली विलय को लय

सरोज सिंह

राजद और जनतादल यूनाइटेड के प्रस्तावित विलय के लिए बहुप्रचारित दही चूड़ा भोज का प्रतिफल बहुत सीना चौड़ा करने वाला नहीं रहा. सभी दलों के नेताओं, राजनीतिक पंडितों के अलावा सूबे की जनता को भी इस भोज के टेबल से विलय के उद्घोष का इंतजार था लेकिन दोपहर होते-होते यह साफ हो गया कि दही और चूड़ा का तो विलय हो गया पर दलों का विलय अभी दूर की कौड़ी है. लालू प्रसाद ने अपने आवास में भोज में इसे साफ भी कर दिया. उन्होंने कहा कि आज केवल दही और चूड़ा का ही विलय होना था और वह हो गया. दोपहर बाद लालू प्रसाद के बयान के बाद विलय की तमाम अटकलों पर विराम लग गया. भाजपा नेताओं ने चुटकी ली, यह विलय न होना था और न कभी होगा. जीतन राम मांझी प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए यह नीतीश कुमार का ड्रामा था जिसका दही चूड़ा के भोज में लालू प्रसाद ने पटाक्षेप कर दिया. दरअसल जीतनराम मांझी के तरह-तरह के बयानों के बीच नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा ने विलय की अटकलों को चरम पर पहुंचा दिया. लालू प्रसाद भी बार-बार कह रहे थे कि विलय में महज अब औपचारिकता बची है. नीतीश कुमार ने अपने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर विलय पर मुहर भी लगवा ली थी. लेकिन ऐन मौके पर हुई कुछ घटनाओं ने विलय की लय को पूरी तरह बिगाड़ दिया.

विलय को पहला झटका बाग़ी विधायकों पर हाईकोर्ट के फैसले से लगा. ज्ञानू सहित चार विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को रद्द करने का फैसला जैसे ही आया वैसे ही हां और न में फंसे बाग़ी विधायक एक बार फिर एकजुट होने लगे. जानकार सूत्र बताते हैं कि यह संख्या 30 के ऊपर चली गई. बागी विधायकों की बढ़ती संख्या ने नीतीश कुमार के रणनीतिकारों की विलय कर नई पार्टी बनाने की योजना पर पानी फेर दिया. इसके अलावा मुलायम सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वह विलय को लेकर बहुत जल्दबाज़ी में नहीं हैं. तीसरी बात जो विलय को फंसा रही है वह है लालू प्रसाद की चुनावी रणनीति. अब एक-एक कर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह पहले दिन से ही इस बात के पक्षधर रहे हैं कि नई पार्टी का चेहरा जैसा भी हो पर चुनाव चिन्ह साइकिल ही होना चाहिए.

केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर पर मकरसक्रांति के मौके पर दही-चूड़ा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिरकत की और साथ में हैं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी.

लालू प्रसाद जदयू और राजद का विलय बिल्कुल अपनी शर्तों पर चाहते हैं. लालू खेमे का साफ कहना है कि जनता में जिसकी जितनी पैठ है और जातीय और सामाजिक गणित का आंकड़ा जो बताता है, उसी आधार पर सीटों की भागीदारी तय होनी चाहिए. केवल वर्तमान सीटों के आधार पर बंटवारा करना लालू खेमे को गंवारा नहीं है. इसमें उन्हें राजद खेमे का भारी नुकसान दिख रहा है. जबकि जदयू के वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी कहते हैं कि भागने वाली फ़ौज कभी जंग नहीं जीतती है. नीतीश पहले भाजपा के पीछे भाग रहे थे अब वह लालू प्रसाद के पीछे भाग रहे हैं. विलय की कोई जरूरत ही नहीं है.

मुलायम किसी भी हाल में साइकिल चुनाव चिन्ह को छोड़ना नहीं चाहते हैं. नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हैं. नीतीश इस पक्ष में हैं कि पार्टी का एक नया नाम हो और नया चुनाव चिन्ह. बात जनता दल और चक्र चुनाव चिन्ह की हुई. कहा गया कि वीपी सिंह ने इसी हथियार से सत्ता परिवर्तन कर दिया था इसलिए चक्र के मार्फत ही नरेंद्र मोदी की सत्ता का ख़ात्मा किया जाए. लेकिन बताया जाता है कि मुलायम इसके लिए तैयार नहीं हैं. यूपी की राजनीति के मद्देनजर मुलायम हर हाल में साइकिल की ही सवारी करना चाहते हैं. सभी दलों में विलय की बात फिलहाल बिगड़ती देख एक बात यह उठी कि चूंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं इसलिए क्यों न पहले राजद और जनता दल यूनाइटेड का ही विलय कर लिया जाए. इस थ्योरी में भी कई अगर-मगर सामने आ गए. सवाल उठा कि आखिर किस पार्टी का किस पार्टी में विलय हो. मतलब कि जदयू का राजद में विलय हो या फिर राजद का जदयू में विलय हो या फिर दोनों का एक दूसरे में विलय कर नई पार्टी ही बना ली जाए. जदयू के राजद में विलय में कई परेशानियां सामने आ जाने का खतरा दिखाई पड़ने लगा.

अगर जदयू के 25 विधायकों ने भी विलय से मना कर जदयू के अलग अस्तित्व पर मुहर लगा दी तो फिर मांझी सरकार पर ही खतरा पैदा हो जाएगा. नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि चुनावी साल में यह संदेश जाए कि पार्टी में विद्रोह है और सरकार कभी भी गिर सकती है. दूसरा विकल्प यह है कि राजद का जदयू में विलय कर दिया जाए और पार्टी की कमान लालू प्रसाद को सौंप दी जाए. इससे जदयू में न तो टूट का ख़तरा पैदा होगा और न ही सरकार गिरने का ख़तरा पैदा होगा. राज्य में एक नई सरकार काम करने लगेगी जिसका नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सहमति से चुना जा सकेगा. बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद ने इस फार्मूले को तवज्जो नहीं दी. जानकार सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद जीतन राम मांझी को हटाने में भागीदार बनकर दलितों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते हैं. सरकार के अब मात्र आठ महीने ही बचे हैं इसलिए इस आखिरी घड़ी में सरकार में शामिल होकर लालू अपयश से भी बचना चाहते हैं. लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू जदयू और राजद का विलय बिल्कुल अपनी शर्तों पर चाहते हैं.

लालू ख़ेमे का साफ कहना है कि जनता में जिसकी जितनी पैठ है और जातीय और सामाजिक गणित का आंकड़ा जो बताता है, उसी आधार पर सीटों की भागीदारी तय होनी चाहिए. केवल वर्तमान सीटों के आधार पर सीटों का बंटवारा करना लालू ख़ेमे को सूट नहीं कर रहा है. इसमें उन्हें राजद ख़ेमे का भारी नुकसान दिख रहा है. इसलिए लालू ख़ेमा यह चाहता है कि विलय तो हो, पर अपनी शर्तों पर. राजद चाहता है कि विलय से पहले सीटों के बारे में खुलकर बात हो जाए ताकि विलय या फिर नई पार्टी की स्थिति में कोई गलतफ़हमी न हो. इसलिए लालू प्रसाद ने यह कहकर मामले को आगे बढ़ा दिया कि दो पार्टियों का नहीं बल्कि विलय होगा तो तमाम जनता दल परिवार का. चूंकि लालू प्रसाद जानते हैं कि इस प्रक्रिया में अभी काफी वक्त लगेगा. मामला तभी निपटेगा जब साइकिल पर सहमति बने और नीतीश और चौटाला परिवार इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं दिखते हैं. इसलिए यह बात अब विलय से जुड़े हर नेता की जुबान पर है कि हमलोगों के दिल मिल गए हैं तो दल भी जल्द ही मिल जाएंगे. लेकिन जदयू के वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी कहते हैं कि भागने वाली फौज कभी जंग नहीं जीतती है. नीतीश पहले भाजपा के पीछे भाग रहे थे अब वह लालू प्रसाद के पीछे भाग रहे हैं. विलय की कोई जरूरत ही नहीं है. बेहतर होता नीतीश अपने बलबूते चुनावी अखाड़े में उतरते.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

घर से होगा ऊर्जा संरक्षण

पूर्वी भारत की सबसे बड़ी भवन निर्माण कंपनी वास्तु विहार अब ऐसे आधुनिक घरों को बनाएगी जो सौर ऊर्जा से संचालित होंगे. ये घर सूरज की रोशनी का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे. घर की आधी से ज्यादा बिजली की ज़रूरत सूरज की रोशनी से ही पूरी हो जाएगी. इससे बिजली की खपत कम होगी और बिजली का बिल लगभग आधा आयेगा और बिजली अन्य ज़रूरतमंद लोगों को मिल सकेगी. दुनिया में बिजली की भारी किल्लत ने वास्तु विहार का ध्यान इस ओर खींचा और कंपनी ने ऊर्जा संरक्षित घर बनाने की सोची. इन घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगी होंगी. ये सोलर प्लेट धूप की ऊर्जा को संरक्षित करेंगी. इसी ऊर्जा से घर के एसी, गीज़र चलेंगे. इससे घर की बिजली का खर्च लगभग आधा हो जाएगा और खाना बनाने में लगने वाले गैस सिलिंडर की खपत भी कम होगी. क्योंकि किचेन में लगे गीज़र के गर्म पानी से खाना आसानी से बन जायेगा. इससे महिलाओं को आराम होगा और उनका बजट भी काबू में रहेगा. वास्तु विहार का ऊर्जा संरक्षित ये घर कई मायनों में क्रांतिकारी होगा. क्योंकि इस नई सोच से जहां बिजली की ख़पत कम होगी, सौर ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल होगा. वहीं पर्यावरण भी प्रदूषणमुक्त रहेगा. *– निक्की सिंह*

पत्रकार को मातृ शोक

चौथी दुनिया के पत्रकार नीरज सिंह की माता इन्दु सिंह की ब्रेन हैमरेज के कारण असमय मृत्यु से पत्रकार नीरज सिंह गहरे सदमे में हैं. उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी के पारामाउंट एवं डॉ. चेंग हॉस्पिटल में लगातार 30 दिनों तक गहन चिकित्सा कक्ष में रहने के उपरांत स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद नर्सिंग होम की लापरवाही से उनकी 62 वर्षीय माता असमय चल बसीं. पत्रकार की माता के असमय निधन से विधान पार्षद सह सचिव एमजीएम मेडिकल कॉलेज दिलीप जायसवाल पूर्णिया के भाजपा नेता विधायक किरण केसरी, प्रफुल्ल रंजन वर्मा, बबलू चौरसिया भाजपा प्रदेश हिंदी प्रकोष्ठ मंच के वरुण सिंह, प्रसिद्ध अंगिका गायक व भाजपा नेता सुनील छैला बिहारी भाजपा आजीवन निधि सहयोग के विजय खेमका, मंटू राय, विजय मांझी, संजय चौधरी, समाजसेवी नीलम जयसवाल, राजेश जयसवाल आदि ने संवेदना व्यक्त करते हुए इस गम के माहौल में शरीक हुए. *– नीरज सिंह*

मांझी महादलितों के सर्वमान्य नेता

बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महादलितों के सर्वमान्य नेता हैं. उनमें सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की भी क्षमता है. यह बात राजद के वरिष्ठ नेता अलाउल अहमद ने कही है. उन्होंने कहा कि बिहार में महादलितों का 16 प्रतिशत वोट है. ऐसे में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का सवाल ही नहीं उठता है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी यह बात कह चुके हैं. अलाउल अहमद ने कहा कि जीतन राम मांझी को हटाने से महागठबंधन को क्षति होगी. मुख्यमंत्री मांझी फिलहाल बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं. महागठबंधन के सभी दलों का सहयोग उन्हें मिल रहा है. *– सुनील सौरभ*

समिति की हुई बैठक

समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन भवन के सभागार में गहमा-गहमी के बीच जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई. बैठक में भ्रष्टाचार का मामला मुख्य रूप से छाया रहा और अनेक सदस्यों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में मची लूट व मनमानी से सदन को अवगत कराया. बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री रमई राम ने की जबकि मौके पर मंत्री अवधेश कुशवाहा, जिलाधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव, पुलिस कप्तान सुनील कुमार, उप विकास आयुक्त अनिल चौधरी, राघवेन्द्र सिंह, विधायक लक्ष्मीनारायण यादव, रामचन्द्र सहनी, सचिन्द्र सिंह, विधान पार्षद सतीश कुमार, सांसद संजय जायसवाल, समिति के सदस्य विनय कुशवाहा, डॉ. तफ़्ज़ुल हुसैन, प्रमोद सिन्हा, सरदार मंजीत सिंह, सिविल सर्जन डॉ. मीरा वर्मा, डीईओ ज्ञानानन्द प्रसाद, आईसीडीएस प्रभारी प्रवीण कुमार, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक विवेक सिंह, अभ अधीक्षक संजीव कुमार समेत सभी विभागों के अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित थे. बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आईसीडीएस, समेत कई विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और असंतोषजनक प्रतिवेदन पर कई अधिकारियों को फ़जीहत झेलनी पड़ी.

भाजपा का सदस्यता अभियान

पूर्वी चंपारण जिले के ढाका उच्च विद्यालय खेल-कूद मैदान के बाहर भारतीय जनता पार्टी ढाका ईकाई के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया. उक्त अभियान का नेतृत्व पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी एवं भाजपा ढाका विधान सभा के संभावित प्रत्याशी प्रभुनारायण ने किया. प्रभु नारायण ने बताया कि मोबाइल के द्वारा 250 लोगों ने भाजपा की सदस्यता प्राप्त की. मौके पर उपस्थित ढाका नगर इकाई के संगठन महामंत्री बब्लू चौधरी ने बताया कि सदस्यता अभियान मार्च तक चलाया जाएगा. चौधरी ने बताया आम लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़ने के लिए पार्टी के द्वारा टोल फ्री नंबर 1800 266 2020 जारी किया गया है. चौधरी ने बताया कि युवा वर्ग सदस्यता अभियान को ले काफी उत्साहित हैं. मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश आर्य, चन्देश्वर ठाकुर, राजेश गुप्ता, नूर मोहम्मद, राज कुमार पटेल, पप्पू चौधरी सहित दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे.■

– इंतेज़ारुल हक़

चंपारण

पूर्वी चंपारण में छह वर्षों में हुई हैं लगभग 46 हजार आपराधिक घटनाएं

सरकार का अपराध नियंत्रण का दावा खोखला

इंतेज़ारुल हक़

पुलिस कप्तान सुनील कुमार

बिहार की जदयू सरकार भले ही समाज में अमन-चैन कायम करने व शांति-व्यवस्था बहाल रखने के लिए अनेक एहतेयाती कदम उठाती है किन्तु महात्मागांधी की कर्म भूमि चंपारण में सरकार के सभी दावे की पोल खुलती नज़र आ रही है. ऐसा लगता है जैसे यहां क़ानून का राज खत्म हो गया है. पूर्वी चंपारण जिले में हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण, लूट जैसी घटनाएं अब आम हो गयी हैं और अपराधी अपनी मंशा में कैसे लगातार कामयाब हो रहे हैं, पिछले छह वर्षों में हुई आपराधिक घ्टनाओं व प्राप्त आंकड़ों से सहज अनुमान लगाया जा सकता है. पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक 46 हजार 34 आपराधिक घटनाएं हुई हैं. इनमें 845 मासूमों की हत्या, 168 महिलाओं के साथ बलात्कार व 845 लोगों का अपहरण हुआ है. इसके अलावा तीन हजार मामले चोरी के दर्ज हैं. सब से चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि प्रत्येक वर्ष इन घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और पुलिस की सभी कार्रवाई बौनी दिख रही हैं. चौथी दुनिया को जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके मुताबिक वर्ष 2009 में पांच हजार पांच सौ पचीस अपराधिक घटनायें घटी हैं जिसमें एक सौ एकतीस हत्या, तीस डकैती, चार लूट, पैंसठ ठगी, पांच सौ पचास चोरी, चार सौ तीरपन दंगा, एक सौ इक्कीस अपहरण, चार फिरौती के लिए अपहरण, 26 बलात्कार, बारह सड़क डकैती व सड़क लूट के पचास मामले शामिल हैं. यह आंकड़ा वर्ष 2010 में और बढ़ गया है. वर्ष 2010 में पांच हजार आठ सौ 81 घटनाएं घटीं, जिसमें हत्या के 154, डकैती के आठ, लूट के चार, ठगी के 75, चोरी के पांच सौ चौबीस, दंगा के चार सौ छियालीस, अपहरण के एक सौ अठारह, फिरौती हेतु अपहरण के चार, बलात्कार के चौबीस, सड़क डकैती चौदह व सड़क लूट के तीरपन मामले में शामिल हैं. इसी तरह वर्ष 2011 की आपराधिक घटनाओं पर गौर करें तो पता चलता है कि यहां भी पुलिस का दावा खोखला है और घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है. वर्ष 2011 में सात हजार आठ सौ छतीस घटनाएं हुई हैं. इनमें हत्या के एक सौ बतीस, डकैती के सात, लूट के पांच, ठगी के 98, चोरी के 526, दंगा के 628, अपहरण के 119, फिरौती हेतु अपहरण के दो, बलात्कार के सैंतीस, सड़क डकैती के नौ व सड़क लूट की 57 घटनायें हुई हैं. यही स्थिति 2014 की भी रही है और लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है. दर्ज आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में नौ हजार दो सौ तीस आपराधिक घटनायें घटी है, जिनमें हत्या के एक सौ बयालीस, डकैती के आठ, लूट के छह, ठगी के अंठानवे, चोरी के छह सौ छह, दंगा आठ सौ एकसठ, अपहरण के दो सौ पैतीस, बलात्कार के तीस, सड़क डकैती नौ व सड़क लूट के अठारह तथा दहेज के लिए इनहतर की हत्याये हुई है. हालांकि बिहार की सरकार विधि-व्यवस्था मजबूत बनाये रखने के लिए पिछले छह वर्षो में करीब आधा दर्जन पुलिस कप्तानों की पदस्थापना व तबादला कर चुकी है किन्तु इसका असर यहां नहीं दिखा और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला गया.यहां एक बात और स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भूमि-विवाद का मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है और इस कारण भी हिंसक घटनाएं होती रहती है.यही स्थिति अगर कायम रही तो भविष्य में पूर्वी चंपारण की स्थिति क्या रहेगी सहज अनुमान लगाया जा सकता है. हालांकि पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान सुनील कुमार इन दिनों अपराध पर शिकंजा कसने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में कई दुर्दान्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता भी मिली है. दूसरी तरफ यही स्थिति पश्चिम चम्पारण की है.यह जिला अपराधियों के लिए चारागाह बनता दिख रहा है और पुलिस की कार्रवाई अपराधियों के सामने बौनी दिख रही है. कब कहां किसकी हत्या हो जायेगी और अपराधी अपराध की घटना को अंजाम दे देगे,यह कहना काफी मुश्किल है.■

feedback@chauthiduniya.com

दही-चूड़ा में भी नहीं मिली विलय को लय

– पृष्ठ 17 का शेष

शकुनी चौधरी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला भागने वाली फौज कैसे कर सकती है. अभी समय युद्ध की तैयारी का है तो हमलोग विलय के पचड़े में फंसे हुए हैं. इधर जदयू में ही जीतन राम मांझी समर्थक मंत्रियों और नेताओं की तादाद रोज बढ़ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने भी मांझी को अगले सीएम का सबसे प्रबल दावेदार बता दिया. दही चूड़ा के भोज में मांझी पहले लालू के निवास पर गए और फिर बाद में अपने प्रदेश अध्यक्ष के भोज में. जदयू विधायकों और मंत्रियों की एक बड़ी फौज लालू प्रसाद के निवास पर अपना चेहरा दिखाने के लिए उमड़ पड़ी. मतलब लालू प्रसाद ने अपने आप को आगे की चुनावी राजनीति के लिए बड़ा खिलाड़ी कम से कम इस दही चूड़ा के भोज में तो साबित कर ही दिया. नीतीश के बीमार हो जाने की कमी जदयू को बुरी तरह खली और इसका पूरा फायदा लालू प्रसाद को मिला और वह ही सभी के आकर्षण के केंद्र बने रहे.

भोज के बाद यह साफ हो गया कि विलय की गाड़ी को लय पकड़ने में अभी वक्त लगेगा. फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अगली चाल क्या चलते हैं और लालू प्रसाद इसका कैसा जबाव देते हैं. एनडीए खेमें में भी दही चूड़ा भोज की धूम रही. सुशील मोदी और उपेंद्र कुशवाहा ने जहां पटना में ही भोज दिया वहीं रामविलास पासवान ने दिल्ली में भोज दिया. इस भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की. लेकिन चर्चा तो लालू प्रसाद की भोज की ही रही जिसने बिहार की राजनीति के कई पेंचों को और भी उलझा दिया.■

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी

कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा चुनावी टास्क

इंतेज़ारुल हक़

लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की बैठक

चंपारण का राजनीतिक तापमान आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर एक बार फिर इन दिनों बढ़ गया है और अपनी जमीन तैयार करने में राजनीतिक दलों के नेता अलग-अलग मुद्दों को लेकर जुट गये हैं.आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण माहौल में पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाकर चुनावी टास्क दिया जाने लगा है. कहीं यात्रा तो कहीं किसी की जंयती के बहाने पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को मजबूती से अपने पक्ष में जोड़े रखने का प्रयास किया जा रहा है और इसी बहाने चुनावी गणित भी तैयार की जाने लगी है.लोक सभा चुनाव के दौरान नमो की सुनामी के शिकार राजनीतिक दलों के नेताओं को तो सर्दी के इस मौसम में भी पसीना बहाने की नौबत आ रही है. हालांकि मंचों पर वे गर्मजोशी के साथ गरज रहे हैं और ज़मीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं किन्तु कोई ख़ास सफलता उनके हाथ आते नहीं दिख रही है.पिछले दो बार के बिहार विधान सभा चुनावों में एनडीए चंपारण में अपनी मजबूत पकड़ की बदौलत सीटों पर कब्ज़ा जमाने में कामयाब रही थी. वर्ष 2005 के चुनाव में राजद के लालू विरोधी मतों के एक होने से जहां नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था, वहीं भाजपा से अलग होने का ख़ामियाज़ा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भुगतना पड़ा है. लेकिन अपने पुराने राजनीतिक शत्रु से गठबंधन करने पर मजबूर हुए नीतीश ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए युवाओं को अपनी ओर जोड़ने के लिए यूथ कमेटी का नया रूप दिया है.

कई महीनों से भंग युवा जदयू को धारदार बनाने व अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विपिन पटेल को जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई है. विपिन युवाओं को पार्टी से जोड़ने में किस हद तक क़ामयाब होते हैं यह तो समय निर्धारित करेगा किंतु राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जदयू की युवा शक्ति काफ़ी बिख़र गयी है और उन्हें फिर से लाना असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है. विपिन ने पूछे जाने पर बताया कि पार्टी में अधिक युवाओं को जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, दी जायेगी. दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सत्ता में सहयोगी रही भाजपा ने यहां पूरी तरह से अपना कमर कस ली है और सदस्यता अभियान व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जदयू को औक़ात बताने के लिए भरपूर तैयारी कर रही है. वैसे पूर्वी चंपारण जिले में सभी दलों के संभावित प्रत्याशियों की बोलती बंद है.बिहार में बन रही गठबंधन की राजनीति ने उनकी मंशा को अधर में लटका दिया है.

गठबंधन के तहत कौन सीट किस दल को मिलेगी और कौन कहां से प्रत्याशी बनेगा ,फिलहाल कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है. ऐसी स्थिति में किसी भी दल का कोई भी नेता मुखर होकर बोलने को तैयार नहीं है. पिछले दिनों गोविंदगंज के ममरखा-मलाही में लोजपा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें लोजपा संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष अनील चौधरी,राष्ट्रीय सचिव परवेज़ अहमद ख़ां, राजू तिवारी, जिलाध्यक्ष धरनीधर मिश्रा व जिला प्रभारी केशव सिंह आदि की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को अनेक दिशा-निर्देश दिये गये और आगामी विधान सभा चुनाव में काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया. पूर्वी चंपारण जिले के 12 विधान सभा क्षेत्रों में कम से कम तीन सीटों पर लोजपा का प्रत्याशी उतारने का संकेत भी सामने आया. वैसे पार्टी सूत्रों पर भरोसा करें तो लोजपा चार सीटों पर अपना कब्ज़ा जमाने को आतुर है, किंतु गठबंधन के कारण मजबूत दावेदारी पर फिलहाल ग्रहण लगता नज़र आ रहा है. राजनीतिक गलियारों से जो ख़बर छन कर आ रही है, उसके मुताबिक, जिले की तीन सीट,गोविंद गंज-नरकटिया व पिपरा विधान सभा क्षेत्र, लोजपा को मिलने की संभावना है,जब कि चौथी सीट ढाका पर भी लोजपा नेताओं की नज़र टिकी हुई है. यहां बतातें चलें कि गोविंद गंज की जदयू विधायक मिना द्विवेदी, नरकटिया के जदयू विधायक श्याम बिहारी व पिपरा विधान सभा के विधायक मंत्री अवधेश कुशवाहा हैं जबकि ढाका विधान सभा से निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल हैं.

पार्टी के जानकार बताते हैं कि गोविंद गंज से पूर्व विधायक राजन तिवारी के अनुज राजू तिवारी, नरकटिया से परवेज अहमद ख़ां व पिपरा से सलाउद्दीन ख़ां के मैदान में उतारे जाने की संभावना है. चर्चा यह भी है कि पूर्व विधायक राजन तिवारी इस बार बगहां में अपनी किस्मत अजमाएंगे. वैसे अभी चुनाव में समय है और जिले से लेकर प्रदेश तक की राजनीति में उतार-चढ़ाव की संभावना है. इस प्रकार संभावित प्रत्याशियों की पलटन चाहे जितना भी ख्याली पुलाव पका ले लेकिन अंतिम फैसला समय आने पर ही होगा.आम मतदाताओं में भी चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं और नेताओं के इरादे भांपे जाने लगे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

धर्मांतरण के दो मामले को लेकर गया गर्म

सुनील सौरभ

बीते वर्ष के अंतिम महीने में देश में धर्मातरण को लेकर राजनीति गर्म रही. बिहार में हाल के वर्षों में धर्मातरण के मामले बहुत कम देखे-सुने गये. लेकिन जब धर्मांतरण को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विवाद, चर्चा और वास्तत में धर्मातंरण की बातें सामने आने लगीं तो इसमें बिहार भी शामिल हो गया. वह भी जब दुनिया को शांति, अहिंसा और विश्ववंधुत्व का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की ज्ञानभूमि में धर्मांतरण की बातें सामने आयीं तो लोग चौंक गये. ऐसे बोधगया में किसी के भी 'चीवर धारण' कर घूमने पर लोगों को आश्चर्य नहीं होता. क्योंकि बोधगया के लोग सीजन में चीवर धारण करने वालों का अर्थ जानते हैं. लेकिन जब बुद्ध भूमि में प्रभु ईशु की शरण में सामुहिक रूप से सैकड़ों लोग चले जायें तो लोगों का चौंकना स्वाभाविक था. बोधगया के अतिया गांव के महादलित टोले मे 45 घरों के 203 परिवारों द्वारा ईसाई धर्म को अंगीकार करने के मामले गर्म थे ही कि दूसरी ओर गया शहर के दूसरे छोर मानपुर के खजाहांपुर मे सौ से अधिक लोगों द्वारा धर्मातरण कर बौद्ध धर्म स्वीकार किये जाने की बातों ने जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों को परेशान कर दिया तो धर्म के कथित ठेकेदारों तथा राजनीतिज्ञों को बेचैन कर दिया. दोनों मामले की तहकीकात में एक तरफ आर्थिक मजबूरी तो दूसरी तरफ शांति की चाहत में धर्मांतरण का कारण सामने आया. विदा होते साल और नव वर्ष के आगमन पर धर्मांरण को लेकर गया जिले में खूब बवाल हुआ. लेकिन धर्मातंरण की समस्या की लाचारी की बातों को किसी संगठन, प्रशासन ने समझने की कोशिश नहीं की. बोधगया से करीब आठ किलोमीटर दूर अतिया गांव के महादलित टोले में प्रभु ईशु के जन्मदिन क्रिसमस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें ईसाई धर्म के गुरु ने लोगों को शांति का पाठ पढाया. इस कार्यक्रम में शामिल गांव के महादलित टोले के लोगों ने भाग लिया और प्रभु ईशु के जयकारे लगाये. बस इसी के बाद से धर्मांतरण की बातें शुरू हो गयीं. इस दिन गया पहुंचे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लोगों ने इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने जांच का आदेश दे दिया. 26 दिसंबर 2014 को गया जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों का दल जांच करने पहुंचा. जांच टीम में शामिल बोधगया के बीडीओ अजय कुमार ने बताया कि जांच में धर्मांतरण का मामला सामने नहीं आया है. गांव के सामुदायिक भवन में ईसाई धर्मगुरु के रहने की बात सामने आयी है. गांव में प्रोमिश नामक मिशन संस्था के नाम से स्कूल होने की बात सामने आयी है. इस संस्था के निबंधन आदि की जांच की जा रही है. वहीं दूसरी ओर इसी दिन गांव पहुंचे गया के सांसद हरि मांझी ने कहा कि महादलितों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है. वे सामुदायिक भवन में चौपाल लगाकर धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों से मिले. सांसद ने बताया कि ईसाई बने सभी परिवार घर वापसी को तैयार हैं. शीघ्र ही इनकी घर वापसी होगी. विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल के लोगो ने भर धर्मांतरण करने वालों से मिले. बाद मे इन सभी की घर वापसी करायी गयी. लेकिन धर्मांतरण के छिपे कारणों को कोई भी संगठन समझने-जानने का प्रयास नहीं किया. अतिया गांव में धर्मांतरण का विवाद पूरी तरह कम भी नहीं हो पाया था कि गया शहर के मानपुर के खजाहांपुर में सैकड़ों लोगों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की बात ने लोगों को चौंकाया. खजाहांपुर में नव निर्मित बुद्ध मंदिर के पास पांच जनवरी 2015 कों सैकड़ों लोगों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना पर गया सदर एसडीओ तथा मानपुर बीडीओ ने पहुंच कर मामले को समझा. नवनिर्मित बुद्ध मंदिर के पास दोनों पक्ष के लोग अपने-अपने तर्क प्रशासनिक पदाधिकारियों को देते रहे. लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी धर्मांतरण की बातों को छोड़कर विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर ही ज्यादा चिंतित दिखे. बौद्ध धर्म अपनाने वाली अनेक महिला-पुरुषों ने अपने धर्मांतरण के कारण भी बताये. खजाहांपुर की दयमंती देवी ने बताया कि हमलोग परेशान थे. घर में अशांति थी. बौद्ध धर्म अपनाने से शांति है, घर के सभी लोग मिलजुल का रह रहे हैं. इसी प्रकार कंचन देवी, गायत्री देवी, उर्मिला देवी, नीलम वर्मा आदि ने कहा कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से घर में शांति हुई है. फिलहाल किसी तरह इन दोनों जगह धर्मांतरण के मामले को शांत कर दिया गया है.लेकिन सच्चाई है कि धर्मातरण करने वाले लोग पूरी तरह अपने मकसद में सफल होने का प्रयास भविष्य में करने को लेकर चिंतित है. अतिया के महादालित 'आर्थिक' स्थिति मजबूत करने तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के प्रलोभन मे हैं तो खजाहांपुर के लोग बुद्ध मंदिर निर्माण कर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर अर्थिक समृद्धि तथा विदेशी राशि प्राप्त कर अर्थिक उन्नति को लेकर आशांवित है.

अब तो आने वाला समय ही बतायेगा कि धर्मांतरण का लाभ किसको कितना मिला या घर वापसी कर लोग कितने फायदे या शांति पा सकें. बहरहाल धर्मांतरण के इन मुद्दों को लेकर पूरे गया जिले में चर्चा का बाजार गर्म है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

भाकपा का हुआ अधिवेशन

केन्द्र की भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है. केन्द्र सरकार लोकतांत्रिक भारत को एक बार फिर गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है. उक्त बातें भाकपा के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक कामरेड राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा में आयोजित तीन दिवसीय अधिवेशन में कहीं. उन्होंने केन्द्र सरकार व वर्तमान राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर कटाक्ष किया और कहा कि केन्द्र व राज्य की दोनो सरकारें आम गरीबों को लूटने का काम कर रही है. सभा को पूर्व विधायक त्रिवेणी तिवारी, भाकपा नेत्री शालिनी मिश्रा, अशोक यादव, मनोज सिंह, विजय शंकर सिंह, शम्भूनाथ सिंह समेत राजेश शुक्ल आदि थे. समारोह की अध्यक्षता कामरेड राधामोहन सिंह ने की जबकि संचालन कृष्ण सिंह ने किया. *– इंतेज़ारुल हक़*

भाईचारे की मिसाल

कमांडेंट के रूप में एसएसबी बथनाहा में पदस्थापित एकेसी सिंह ने अपने कार्यकाल में जिस रूप में भाईचारे की मिसाल पेश कर लोगों का दिल जीत लिया था, उससे ज्यादा उन्होंने एक बार फिर अपने तबादले के उपरांत अररिया आगमन पर लोगों का दिल अपने उत्कृष्ठ व्यवहार से जीत लिया. सिंह जब अररिया पहुंचे तो उनके निकट सहयोगी आनंद कुमार के जरिये लोगों को जब उनके आगमन की ख़बर प्राप्त हुई तो लोगों ने उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया. अपने अल्प प्रवास के दौरान ही उन्होंने न सिर्फ अपने स्वागतकर्ताओं से उनका कुशल क्षेम जाना वरन पूरे इलाके के लोगों के बारे में जानकारियां लीं.

पोशाक राशि वितरित

फॉरबिसगंज प्रखंड के रामलाल उच्च विद्यालय हरिपुर डाक में मुख्यमंत्री साइकिल एवं पोशाक योजना की राशि वर्ग नवम एवं दषम के 300 छात्र-छात्राओं के बीच वितरित की गयी. साइकिल क्रय हेतु 2500 एवं पोशाक हेतु 1000 की राशि मुखिया प्रवीण कुमार, सरपंच महेन्द्र प्रसाद भगत, पूर्व मुखिया डॉ. नूर मोहम्मद आज़ाद, विन्देश्वरी मेहता, प्रधानाध्यापक, तेज बहादुर सिंह के द्वारा प्रदान की गयी. इस अवसर पर विद्यालय परिवार के शिक्षक जगदीश प्रसाद गुप्ता, तेजनारायण मंडल, धीरनारायण मंडल, गिरिजानंद झा, नागेन्द्रनाथ झा, मो. एकरामुद्दीन, विनोद कुमार तिवारी, अजय आनंद आदि इपस्थित थे. *–अजातशत्रु अग्रवाल*

जयंती मनी

इन्द्रधनुष साहित्य परिषद् के तत्वावधान में शायर मिर्ज़ा ग़ालिब की जयंती समारोहपूर्वक मनायी गयी. इसकी अध्यक्षता मांगन मिश्र 'मार्तण्ड' ने की जबकि संचालन विनोद कुमार तिवारी ने किया. वक्ताओं में हेमंत यादव, हर्ष नारायण दास, दिलीप समदर्शी, सुनील दास, कृत्यानंद राय, कृष्ण सिंह, शिवनारायण चौधरी, राजनारायण प्रसाद आदि ने अपने-अपने विचार रखते हुए गालिब के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये. वक्ताओं ने कहा कि ग़ालिब की शायरी में तड़प और चाहत के साथ-साथ आशिकाना अंदाज पाया जाता है. दिल्ली में उनके नाम पर मिर्जागालिब अकादमी स्थापित होने की जानकारी श्री तिवारी ने दी. *– कुमार विशाल*

रैली निकाली

गंगा बचाओ जनजागरण अभियान के तहत बाल मंच फॉरबिसगंज के द्वारा शहर एवं गांव के टोलों में रैली निकाली गयी. इस रैली में रामलाल उच्च विद्यालय हरिपुर के बच्चों के अलावा विभिन्न स्कूलों के बच्चे शामिल थे. रैली का नेतृत्व हेमंत यादव, हर्ष नारायण दास, राजनारायण प्रसाद एवं विनोद कुमार तिवारी ने किया. रैली के जरिये बच्चों ने गंगा मईया पर आधारित गीतों की प्रस्तुति के जरिये लोगों से गंगा मईया के संरक्षण की अपील की. *– अजातशत्रु अग्रवाल*

निकाला कैंडिल मार्च

सीतामढ़ी जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में दवा व्यवसायियों द्वारा नगर में कैंडिल मार्च निकाला गया. जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में निकाली गयी मार्च में दवा प्रतिनिधियों, चिकित्सकों समेत अन्य संगठनों ने भी भाग लिया. मौके पर विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, सचिव राज कुमार, घनश्याम व्यास, अशोक प्रियदर्शी, मनोज मित्तल, कैलाश हिसारिया, डॉ. राजेश कुमार सिंह, डॉ. एम ठाकुर, विभा ठाकुर, डॉ. राजेश कुमार सुमन, डॉ. आलोक, प्रो. राजकुमार गुप्ता, डॉ. विजय सर्राफ, नागरिक मंच के संयोजक डॉ. ब्रजेश शर्मा, प्रो. जितेंद्र कुमार वर्मा, नागेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ. रमा शंकर प्रसाद, अरुण गोप, आफताब अंजुम बिहारी, विनय कुमार मिश्रा, नरोत्तम व्यास, डॉ. शशि रंजन व डॉ. राम सागर ठाकुर समेत अन्य थे. *– ब्रिजेश*

शोकसभा का आयोजन

सीतामढ़ी शहर के कोट बाजार महारानी स्थान सरस्वती शिशु मंदिर में एक शोकसभा का आयोजन किया गया. जिसमें विद्यालय के सचिव सह प्रमुख दवा व्यवसायी यतींद्र खेतान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गयी. राम इकबाल प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. वसंत कुमार मिश्र, आरएसएस के प्रांत कार्यवाह अभय कुमार गर्ग, गोपीकांत ठाकुर, सुरेश जालान, मुन्ना जी, दिनेश जी, सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य शंभू शरण तिवारी, मदन प्रसाद, चंदेश्वर सिंह, नागेंद्र तिवारी, मिथिलेश कुमार सिंह, अनिता झा, किरण प्रसाद, सूरज प्रसाद, विनय कुमार मिश्र, अवधेश प्रसाद, मनोज कुमार सिंह, सर्वजीत, विनय स्वर्णकार समेत अन्य थे.

विधायक ने किया राशि वितरण

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के महंत विजयानंद गिरी उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिक चौक में एक समारोह का आयोजन किया गया. पवन कुमार झा की अध्यक्षता व पूर्व प्रधान शिक्षक जगन्नाथ झा के संचालन में आयोजित समारोह में स्थानीय विधायक गुड्डी देवी ने साइकिल योजना के तहत राशि का वितरण किया. मौके पर विधायक ने मानिक चौक की धरती को ऐतिहासिक बताते हुए बच्चों से सफलता के लिए प्रयासरत रहने की अपील की. जदयू नेता राजेश चौधरी ने बच्चों से अनुशासन को जीवन का अहम हिस्सा बनाने की अपील की. मौके पर जिला पार्षद संजीत कुमार छोटू, महादेव दास, रामचंद्र राय, डॉ. परमानंद गिरी, सीताराम साह, वंशीधर झा, राम स्वार्थ साह, राधाकांत झा, कमल साह, शैलेंद्र झा व कर्मवीर पासवान समेत अन्य थे.■

– विभा

संक्षिप्त ख़बरें

आप का प्रतिरोध मार्च

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला. कार्यक्रम में संयोजक ओम प्रकाश, सचिव दिलीप कुमार सिंह, डॉ. आनंद किशोर, मंसूर अहमद खान, जितेंद्र कुमार, इरशाद अहमद, भवेश सर्राफ, भिखारी शर्मा, चितरंजन कुमार, उमा शंकर सिह, डॉ. सुरेश प्रसाद यादव, पूर्णेदू झा, रकीन सिद्दकी, हारुन रसीद, मुस्तकीम सिद्दकी समेत अन्य थे. *– विभा*

सुशासन को चाहिए नीतीश

ऑल पूर्वांचल संघ के संस्थापक सह जदयू नेता रामेश्वर कुमार महतो ने कहा कि सूबे बिहार में सुशासन के लिए शासन का कमान पूर्व सीएम नीतीश कुमार में हाथ में होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि गठबंधन टूटने के बाद भाजपा कमजोर पड़ती गयी. इसका एहसास होते ही विरोधियों द्वारा साजिश का सहारा लेकर नीतीश कुमार व जदयू को बदनाम करने का प्रयास किया जाने लगा है. उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश के हाथ में शासन की कमान रही है, तब तक कोई अपराधी ने घर से निकलने का साहस नहीं किया. परंतु अब राजनीतिक साजिश का नतीजा है कि हत्या व अपहरण आम बात होती जा रही है. उन्होंने सीतामढ़ी के चर्चित दवा व्यवसायी यतींद्र खेतान एवं पवन सिंह कुशवाहा, मुनिंद्र पाठक समेत अन्य की निर्मम हत्या पर दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि घटना निंदनीय है. *– वाल्मीकि*

युवा शक्ति ने दिया धरना

सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित अंबेडकर स्थल पर युवा शक्ति के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना दिया गया. जिलाध्यक्ष संतोष कुमार उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिले में बढ़ते अपराध की निंदा की गयी. संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जिले में राजनैतिक हस्तक्षेप व लेन-देन के आधार पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती है. जिसका खामियाजा जिले की जनता को भुगतना पड़ता है. कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव अवध किशोर यादव, जिला पार्षद सरिता देवी, मीना देवी, पूर्व जिला पार्षद मो. अली, कौशल किशोर यादव, अजय कुमार गुप्ता, दिलीप खिरहर, संजीव कुमार, दिनेश प्रसाद यादव, राम ईश्वर यादव, अरूण कुमार, दिलीप राय, मदन कुमार, रजनीश कुमार व संजय राय समेत अन्य थे.

अस्पताल में दिया 110 कंबल

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम सुमिरन सिंह ने समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के सेवार्थ सीएस डॉ. गिरिन्द्र शेखर सिंह को 110 कंबल दिया. कहा कि शीतलहर के दौरान अस्पताल में इलाज को आने वाले गरीब मरीजों को इससे राहत मिलेगी. मौके पर उपाधीक्षक डॉ श्याम मोहन दास, डीपीसी आदित्यनाथ झा, शशि भूषण, अस्पताल प्रबंधक विश्वजीत रामानंद, सुनील कुमार, अभय कुमार, राकेश कुमार राज, शैलेंद्र सिंह, राकेश रंजन पिंटू, मुकेश कुमार सिंह, प्रभात कुमार, राकेश कुमार ठाकुर, राजेश कुमार, रंजीत कुमार, इंद्रजीत राय, मनोज कुमार राय, रौशन कुमार, नवल किशोर शर्मा, आलोक गुप्ता व वसीम अख्तर समेत अन्य थे. *– अमृता*

पोशाक राशि वितरित

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के उच्च विद्यालय के प्रांगण मे मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अन्तर्गत पोशाक की राशि बांटी गई. इस मौके पर साईकल वितरण समारोह को संबोधित करते हुए जदयू प्रखंड अध्यक्ष युवा नेता नंदलाल मंडल ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा जगत में ऊंची छलांग लगा रही हैं. मौके पर स्थानीय ग्रामीण छठ्ठू मंडल, मदन मोहन प्रसाद, मनोज मालाकार ,मिथलेश कमार सिंह आदि ने स्कूल की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया इधर शारीरिक शिक्षक सोनू कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में खेल की महत्ता पर प्रकाश डाली. वहीं स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मधुकांत झा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि साइकिल व पोशाक योजना के लाभार्थी इस राशि का इस्तेमाल साइकिल व पोशाक खरीदने में ही करें. उन्होंने कहा कि वर्ग 9 के 491 छात्र व छात्राओं के बीच साइकिल क्रय के लिए प्रति छात्र 2500 रुपये नगद तथा वर्ग 9 के 234 व वर्ग 10 के 212 छात्राओं को पोशाक क्रय के लिए प्रति छात्र 1000 रुपये दिये जा रहे हैं. मौके पर जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता जयजय राम चौधरी ,धुमार शर्मा, जर्नादन कुमार आदि ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बालक व बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए साइकिल, पोशाक एवं प्रथम श्रेणी से इर्त्तीण छात्रों के बीच 10-10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि देकर एक इतिहास कायम किया है. इस मौके पर बीस सूत्री सदस्य सह प्रखंड जदयू अध्यक्ष नंदलाल मंडल सहित सैकड़ों छात्र-छात्रा एवं ग्रामीण उपस्थित थे. *– गीता कुमार*

सीतामढ़ी

किसानों का मानना है कि सरकारी सहयोग से मिल प्रबंधन किसानों के साथ अन्याय कर रही है. जिला प्रशासन व गन्ना विभाग सुगरकेन एक्ट लागू कराने में उदासीन बना है. नतीजा है कि सूबे में दूसरी जगहों पर चीनी मिलों ने जहां किसानों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, वहीं रीगा चीनी मिल प्रबंधन के ज़िम्मे किसानों के क़रीब 40 करोड़ रुपये अब भी बक़ाया हैं. किसानों ने साफ़ लहज़े में कहा कि राज्य के गन्ना सचिव के आदेश की अवहेलना मिल प्रबंधन कर रही है. मिल प्रबंधन घोषित मूल्य का पूर्ण भुगतान करने की बजाय आंशिक भुगतान कर रही है.

स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन पर उपजा जंगल

वाल्मीकि कुमार

नेता चुनाव जीतने के लिए बड़े–बड़े वायदे तो कर देते हैं लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद वे अपने क्षेत्र का विकास तो दूर उसके बारे में सोचना तक मुनासिब नहीं समझते. राज्य में विधानसभा के चुनाव को लेकर जैसे ही माहौल गर्म हुआ है, आम जनता को नेताओं द्वारा पिछली दफ़ा किए गए वायदे याद आने लगे हैं. लोग इसका हिसाब लगाने लगे हैं कि पिछली बार जीतने वाले विधायक ने अपने वायदों को किस हद तक निभाया है.

सीतामढ़ी–पुपरी पथ में आवापुर चौक से उत्तर जाने वाली सड़क में पचड़ा नामक एक गांव है. बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इस गांव में तकरीबन पांच दशक पहले आम जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को लेकर एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गयी थी. गांव के अंतिम छोर पर मौजूद मंदिर के समीप करीब 20 कट्ठा सरकारी जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था. स्थापना के बाद विभागीय स्तर पर भवन निर्माण की कवायद भी की गयी. ग्रामीणों की मानें तो उस समय करीब 15 कमरों की नींव डाली गई थी. परंतु तीन–चार कमरों का ही निर्माण कराया गया. तब उक्त स्वास्थ्य केंद्र में दो–दो चिकित्सक नियमित सेवा देते थे. अस्पताल में पशु चिकित्सक भी मौजूद रहते थे. स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था ऐसी थी कि मामूली शल्य चिकित्सा तक स्वास्थ्य केंद्र में ही चिकित्सकों द्वारा सुगमता पूर्वक कर दी जाती थी. परंतु समय गुजरने के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र अतीत की कहानी बन कर रह गया. स्वास्थ्य केंद्र के भवन की जर्जरता के साथ ही जब विभागीय उपेक्षा सामने आने लगी तब कुछ लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र की वस्तुओं को अपने घरों में ले जाकर रख लिया. वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर न भवन है और न ही कोई संसाधन. अब उक्त स्थान पर विशाल पीपल के पेड़ के अलावा काफी खर पतवार निकल आई है. यहां कई सांप स्थाई रूप से डेरा जमाए हुए हैं. जमींदोज हो चुके स्वास्थ्य केंद्र की नींव ही अब उक्त जमीन के सरकारी होने का एकमात्र गवाह प्रतीत होती है. ग्रामीण लक्ष्मेश्वर मंडल, पंचू मुखिया, राम प्रवेश भंडारी, बुधन मुखिया, त्रिभुवन कुमार, दिनेश कुमार कुंवर, रामश्रेष्ठ दास, उपेंद्र मंडल व दिलीप सिंह समेत अन्य की मानें तो स्वास्थ्य केंद्र की वर्तमान स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया. परंतु कोई इस दिशा में गंभीर नहीं है. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू प्रत्याशी रही डॉ. रंजू गीता ने भी समस्या का निदान कराने का भरोसा दिया था. वर्तमान में वे जदयू की विधायक हैं. लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सका है. तकरीबन 3 हजार की आबादी वाले इस गांव में करीब 7 सौ मतदाता है. जिन्हे मामूली स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी प्रखंड मुख्यालय आने की विवशता है. ग्रामीणों की मानें तो वर्तमान में अब कोई चिकित्सक गांव में नहीं आता, लेकिन एक एएनएम कभी–कभार लोगों के बीच उपलब्ध संसाधन के बल पर स्वास्थ्य लाभ दिलाने आती जरूर है. इसके अलावा आशा कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की सेवा में अक्सर तत्पर रहा करती है.

स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. केके झा की मानें तो प्रखंड में कुल 14 स्वास्थ्य केंद्र है. जिनमें बलहा, पिपराही, पथराही, बाजितपुर, पचड़ा, मधुरापुर, मधुबन गोट, बसहा, धनकौल, बडहरबा, मुरौल, हुमायुपुर, मिर्जापुर व माधोपुर चतुरी शामिल है. पचड़ा स्वास्थ्य केंद्र भवनहीन है. प्रखंड में मात्र तीन चिकित्सक ही पदस्थापित है. ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित सेवा संभव नहीं है. गन्ना उद्योग मंत्री बिहार सरकार सह स्थानीय जदयू विधायक डॉ. रंजू गीता ने इस मसले पर राजनीतिक नजरिये से कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है. अपने स्तर से मामला को कई बार विधानसभा में उठाये जाने का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार समस्या निदान को लेकर गंभीर है. परंतु केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण जन समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है.

ऐसा नही है कि यह स्थिति एकमात्र पचड़ा स्वास्थ्य केंद्र की है. इसके अलावा जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिनकी हालत खराब है. लेकिन लोगों का कहना है कि जब सरकार के मंत्री अपने क्षेत्र की समस्या का निदान कराने में विफल रही है तो सूबे बिहार में विकास का आलम क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. गुमनामी की शर्त पर कुछ लोगों का कहना है कि अबकी बार किसी के भी झांसे में मतदाता नही पड़ने वाले हैं. चुनावी वायदों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है. चुनाव बाद कोई जनता की पीड़ा समझने को तैयार नहीं होता है. अबकी बार मतदान का बहिष्कार तक करने के निर्णय से सरकार व प्रशासन को अवगत कराने की रणनीति बनायी जाने लगी है. अब देखना है कि लोग अपनी रणनीति पर काबिज रहते है या फिर चुनावी लॉलीपॉप पर भरोसा करते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में सुशासन व विकास का दावा करने वाली सरकार अब भी कई मायनों में पिछड़ी है. स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब राज्य सरकार में मंत्री के रूप में शामिल विधायक का अपना ही क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो. सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के पचड़ा गांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र की दशा सरकारी व विभागीय उदासीनता का जीवंत उदाहरण बन गई है. यह अस्पताल कभी लोगों के लिए बेहतर इलाज का मुख्य केंद्र हुआ करता था लेकिन अब पिछले तकरीबन डेढ़ दशक से इसकी हालत बदतर हो चुकी है. हालात यह है कि अब लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है...

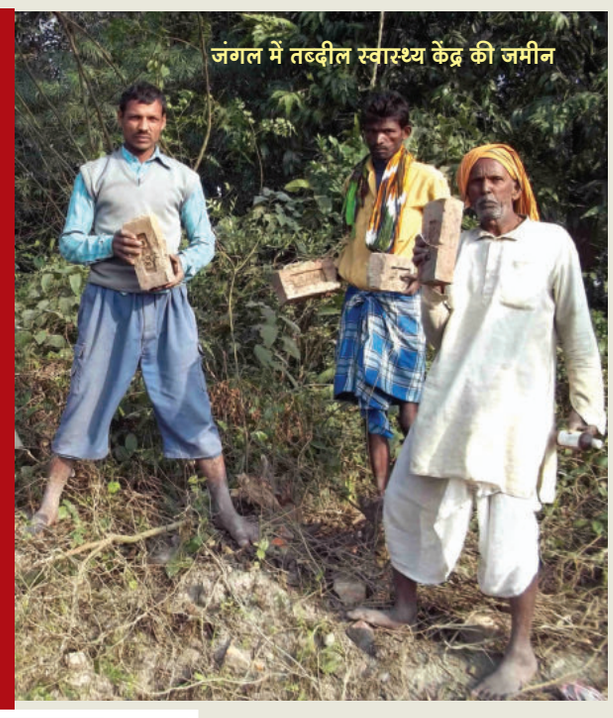

जंगल में तब्दील स्वास्थ्य केंद्र की जमीन

डॉ. रंजू गीता

ग्रामीणों की मानें तो वर्तमान में अब कोई चिकित्सक गांव में नहीं आता, लेकिन एक एएनएम कभी–कभार लोगों के बीच उपलब्ध संसाधन के बल पर स्वास्थ्य लाभ दिलाने आती जरूर है. इसके अलावा आशा कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की सेवा में अक्सर तत्पर रहा करती है.

गन्ना किसानों के आंदोलन ने पकड़ा ज़ोर

भारत–नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी जिले की एकमात्र औद्योगिक इकाई रीगा चीनी मिल एक ओर जहां सैकड़ों परिवार के जीवन यापन का जुगाड़ कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिले के लाखों किसानों को बकाया राशि के भुगतान को लेकर आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है. सीतामढ़ी के किसानों का ऐसा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना इस वजह से भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रदेश की गन्ना उद्योग विकास मंत्री डॉ. रंजू गीता इसी जिले से विधायक हैं. बकाया भुगतान को लेकर जिले के गन्ना किसान अब आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं. किसानों की मांग पर सरकार और मिल प्रबंधन कितना गंभीर होते हैं, इसका सभी को इंतजार है...

वाल्मीकि कुमार

गन्ने की पेराई का समय शुरू होने के साथ ही गन्ना किसानों का धरना–प्रदर्शन, सड़क जाम व गन्ना जलाने जैसी घटनाएं प्रत्येक साल शुरू हो जाती हैं. यह कोई नई बात नहीं है. परंतु गन्ना किसानों की समस्या के स्थाई निदान की दिशा में सरकार, प्रशासन अथवा जनप्रतिनिधि खास दिलचस्पी नहीं लेते हैं, यह सोचने की बात जरूर है. इस साल भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया है. गन्ना किसानों ने राज्य सरकार व मिल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर आंदोलन की श्रृंखला चलाना शुरू कर दिया है. पिछले दिनों संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा की रीगा इकाई के तत्वावधान में 'गन्ना खेती बंद आंदोलन' का श्रीगणेश कर दिया गया है. साथ ही गन्ना जलाने व सड़क जाम कर रोष व्यक्त करने जैसा कार्य भी शुरू कर दिया है. पिछले 4 दिसंबर को रीगा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों ने रामपुर बराही घाट पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया. जिसमें सड़क से लेकर खेत तक संघर्ष का निर्णय लिया गया. कार्यक्रम के दौरान पूसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेटर डॉ. भूपेंद्र नारायण सिंह की अध्यक्षता में गन्ने के विकल्प में खेती के तरीके पर विचार के लिए एक कमेटी भी बनाई गई.

इधर मिल क्षेत्र के किसानों का मानना है कि सरकारी सहयोग से मिल प्रबंधन किसानों के साथ अन्याय कर रही है. जिला प्रशासन व गन्ना विभाग सुगरकेन एक्ट लागू कराने में उदासीन बना है. नतीजा है कि सूबे में दूसरी जगहों पर चीनी मिलों ने जहां किसानों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, वहीं रीगा चीनी मिल प्रबंधन के ज़िम्मे किसानों के क़रीब 40 करोड़ रुपये अब भी बक़ाया हैं. किसानों ने साफ़ लहज़े में कहा कि राज्य के गन्ना सचिव के आदेश की अवहेलना मिल प्रबंधन कर रही है. मिल प्रबंधन घोषित मूल्य का पूर्ण भुगतान करने की बजाय आंशिक भुगतान कर रही है. सूबे की गन्ना विकास मंत्री सह बाजपट्टी की विधायक डॉ. रंजू गीता ने भी जुलाई के अंत तक किसानों की बकाया राशि का भुगतान कराने का भरोसा दिलाया था. परंतु अब तक इस दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाया गया है. किसान आंदोलन की अगुआई कर रहे मोर्चे के संस्थापक डॉ. आनंद किशोर ने राज्य सरकार के समक्ष कई मांगें रखी हैं. जिनमें गन्ना मूल्य की बकाया राशि का भुगतान, नये सत्र में गन्ना मूल्य नहीं दिला सकने की स्थिति में धान की भांति 3 सौ रुपये राज्यानुदान, नये सत्र के गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान शुरू कराने, बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज दिलाने, सुगरकेन एक्ट का अनुपालन कराने, रीगा डिस्टलरी से व्याप्त जल प्रदूषण पर रोक लगाने व तौल केंद्रों पर धर्मकांटा लगाने समेत अन्य मांगें शामिल हैं.

आंदोलन के क्रम में पिछले 20 दिसंबर को सैकड़ों किसानों ने रीगा मिल चौक़ को जाम कर प्रदर्शन किया था. किसान मोर्चा के रीगा इकाई के अध्यक्ष राम कैलाश सिंह की अध्यक्षता में गन्ना किसानों ने घंटो सड़क जाम कर नारेबाज़ी की. कार्यक्रम के दौरान किसान यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वरचंद्र त्रिपाठी ने गन्ना दहन कर किसानों के साथ रोष व्यक्त किया. साथ ही कहा कि देश में किसानों पर अन्याय बढ़ रहा है. किसानों के आंदोलन को तेज़ करने की नियत से अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत देश के किसानों को गोलबंद करने की मुहिम को लेकर देश भ्रमण कर रहे हैं. मोर्चे के जिलाध्यक्ष राम तपन सिंह, महासचिव अभय कुमार सिंह, उप प्रमुख शिवेंद्र सिंह, पूर्व उप प्रमुख रणधीर सिंह, पारसनाथ सिंह, रमेश प्रसाद सिंह, नवीन कुमार सिंह, राम शोभित सिंह, मंसूर अहमद ख़ान, विनय कुमार सिंह, सर्वजीत यादव, कुलदीप यादव, ब्रज मोहन कुमार, मनोज कुमार, चंदेश्वर पूर्वे, शंकर मंडल, ओम प्रकाश कुशवाहा, राकेश कुमार, चंदेश्वर चौधरी व वीरेंद्र यादव समेत अन्य ने किसान आंदोलन को तेज़ करने का संकल्प लिया.

अब सवाल यह उठता है कि किसानों के इस आंदोलन का नतीजा क्या निकल सकता है? सरकार, प्रशासन अथवा जनप्रतिनिधियों के अलावा मिल प्रबंधन कोई सार्थक हल निकालेगी अथवा पुन: किसानों को अगले आंदोलन के लिए बाध्य करेगी. एक ओर मिल प्रबंधन लगातार घाटा का रोना रोती है तो दूसरी ओर गन्ना किसान लागत के हिसाब से मूल्य नहीं मिलने का राग अलापते हैं. इन दोनों के बीच किसान नेता आंदोलनों की श्रृंखला चलाकर गन्ना किसानों की गोलबंदी करने में लगे हैं. समय रहते अगर सरकार, प्रशासन और मिल प्रबंधन ने कोई सार्थक हल निकाला तो संभव है कि आने वाले दिनों में किसानों का आंदोलन सरकार व मिल प्रबंधन के साथ ही किसानों के लिए भी घातक साबित होगा. कारण कि जिले में एक मात्र औद्योगिक इकाई है, जहां से लाखों किसानों की उम्मीदे जुड़ी हैं. अगर इस मिल में किसी कारण से ताला लटका अथवा कोई अन्य परेशानी उत्पन्न हुई तो इसके लिए सभी समान रूप से ज़िम्मेदार हो सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

26 जनवरी–01 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

सीएम बोले किसान समाजवादी होंगे तभी खुशहाल होंगे

बेचारे किसानों का बेचारा अनशन

प्रभात रंजन दीन

गन्ना किसानों को बर्बाद करने के बाद अब धान पैदा करने वाले किसान उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर हैं. उत्तर प्रदेश में इस समय किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है. सरकार ने 1360 रुपये प्रति क्विंटल बी ग्रेड और 1400 रुपये प्रति क्विंटल ए ग्रेड निर्धारित कर रखा है, लेकिन किसानों को अपनी फसलों की यह कीमत कहीं नहीं मिल रही है. प्रदेश के ज्यादातर क्रय केंद्र बंद पड़े हैं. कहीं-कहीं किसानों का तीखा विरोध हुआ तो शासन ने कुछ क्रय केंद्र खोले, लेकिन उन क्रय केंद्रों पर भी धान की खरीद नहीं हुई. ऐसा ही वाकया लखनऊ से सटे जिले उन्नाव में हुआ, जहां सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय घेरा, तब जाकर 10 क्रय केंद्र खोले गए. लेकिन किसानों के साथ दुष्टता पर उतारू प्रशासन ने वहां भी धान की खरीद नहीं शुरू कराई. आखिरकार सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के उन्नाव जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा को किसानों के साथ राजधानी लखनऊ में हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को विवश होना पड़ा.

यह घोर शर्म की बात है कि जिस देश में पिछले 20 वर्षों में ढ़ाई लाख से अधिक किसानों की आत्महत्या हो चुकी हो और किसान बदहाली की स्थिति में हो, वहां उसे अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है. यह प्रदेश के किसानों को और कर्ज व गरीबी की तरफ धकेलने की साजिश है. दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी खत्म करने की साजिश है. यदि सरकार किसानों से अनाज नहीं खरीदेगी तो लोगों को राशन व्यवस्था में अन्न कैसे देगी? अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार की मिली-जुली साजिश पर कड़ा विरोध जताया है. किसानों ने नौकरशाहों से पूछा है कि यदि उन्हें निर्धारित वेतन से कम वेतन दिया जाए तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा और क्या वे उसे स्वीकार करेंगे?

कुछ स्थानों पर किसानों को झांसा देने के लिए काफी घटी हुई कीमत पर धान खरीदे जा रहे हैं और किसानों से यह कहा जा रहा है कि उनकी फसलों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण अनाज की मात्रा कम कर भुगतान में कटौती की जा रही है. यह छिटपुट खरीद भी सरकारी केन्द्रों पर करने के बजाय निजी मिलों पर की जा रही है. सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के प्रदेश संरक्षक गिरीश कुमार पांडेय ने किसानों के प्रति बरते जा रहे ऐसे रवैये पर प्रदेश सरकार की कड़ी भर्त्सना की है. दूसरी तरफ मगसेसे पुरस्कार से सम्मानित सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संदीप पांडेय ने कहा कि किसानों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं. एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसलों की लागत का मूल्य भी नहीं दे रही है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून पर एक नया अध्यादेश जारी कर उसे कमजोर कर दिया है. अब किसानों की जमीन अधिगृहीत करने से पहले भू-स्वामियों की सहमति जरूरी नहीं है और न जन-सुनवाई की आवश्यकता ही रह गई है. इस तरह भूमि-अधिग्रहण की वजह से उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभाव का अध्ययन जरूरी नहीं रह गया है. डॉ. पांडेय ने कहा कि यह सारे किसान-विरोधी कदम हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से बदहाल किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. पांडेय कहते हैं, हम दोनों सरकारों की नीतियों का विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि वह किसान-विरोधी रवैया छोड़ें जो किसान सबको खिला कर जिंदा रखता है यदि उसी की स्थिति बदहाल रहेगी तो समाज कैसे खुशहाल रहेगा?

उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति भयावह होती जा रही है. किसानों की सबसे ज्यादा हितैषी होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किसान दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर हुए हैं. गन्ना किसान बकाये के भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे हैं और धान क्रय केंद्र बिचौलियों के हवाले होने के चलते किसान लूट का शिकार हो रहे हैं. कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र मदान का कहना है कि किसानों से झूठे वायदे करके सत्ता हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी का अंतर अब उजागर हो गया है. उन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य तो तय है, लेकिन धान क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद ही नहीं हो रही है. धान मिलों या किसी अन्यत्र स्थान पर खरीद हो भी रही है तो किसानों को अपनी उपज औने-पौने दाम में बेचनी पड़ रही है. सरकार की शह पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और दलालों द्वारा खुलेआम लूट की जा रही है. गन्ने के बाद अब प्रदेश का किसान धान का उचित मूल्य पाने के लिए मारा-मारा फिर रहा है. कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों तक सैफई महोत्सव में ही व्यस्त रहे. मनोरंजन के नाम पर करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा हो गया. किन्तु उन्हें किसानों की सुध नहीं आई. धान खरीद के नाम पर अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र छठे हिस्से की ही खरीद हो पाई है. सच्चाई यही है कि सरकारी धान क्रय केंद्र सिर्फ कागजों पर संचालित हैं, जमीनी वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है. यहां-वहां एकाध केंद्र यदि खुले भी हैं तो धान में कमी बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है. क्रय केंद्र समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लूट का अड्डा बने हुए हैं और किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के बदहाल किसानों को प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी होने की सीख दे रहे हैं. मुख्यमंत्री कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा अपनाकर ही प्रदेश के किसान खुशहाल हो सकते हैं. मुख्यमंत्री रटे-रटाए अंदाज में सभा-समारोहों में दोहराते-तिहराते रहते हैं कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं. वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा भूमि बन्धक रखकर 50 हजार रुपये का कर्ज लेने वाले किसानों के ऋण माफ किए गए हैं. मुख्यमंत्री किसानों के बच्चों को लैपटॉप बांट रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य मिल जाए, इसकी कोई पहल नहीं कर रहे. पूर्वांचल के जुझारू किसान नेता शिवाजी राय कहते हैं कि प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देकर सत्ता पर बिठाया. सपा को वोट देने वालों में क्या किसान नहीं थे? फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसे समाजवादी होने की सीख दे रहे हैं? किसानों को खुशहाल बनाने के लिए समाजवादी विचारधारा अपनाने की बात सीख है या धमकी? किसानों ने समाजवादी पार्टी को अपनी बदहाली के लिए वोट दिया था या अपनी खुशहाली के लिए? यह क्या मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है? शिवाजी राय कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को

(शेष पृष्ठ 18 पर)

किसान-हितैषी सरकारों ने ही बंद कराईं चीनी मिलें

सरकारें किसानों का हित सोचतीं तो उत्तर प्रदेश की सरकारी चीनी मिलें बंद नहीं हुई होतीं. सरकारी चीनी मिलों का बंद होते जाना सरकार की साजिश का परिणाम है. उत्तर प्रदेश की कुल 122 चीनी मिलों में से एक भी सरकारी चीनी मिल नहीं है. सहकारी क्षेत्र की मात्र 23 चीनी मिलें हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है. ये चीनी मिलें खस्ता हाल हैं. प्रदेश में 99 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं और इनमें से अधिकतर औद्योगिक घरानों की हैं. पहले उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी गन्ना विकास निगम की 33 चीनी मिलें थीं. केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत भी चार चीनी मिलें थीं. उस समय निजी चीनी मिल मालिकों की निरंकुशता नहीं चल पाती थी. सरकार पूंजी घरानों के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी. लिहाजा, पहले केंद्र सरकार के दो उपक्रमों, एनटीसी और कानपुर शुगर वर्क्स की तीन चीनी मिलों को बंद किया गया. दिलचस्प यह है कि निगम की चीनी मिलें बंद हो रही थीं और उसी दौर में निजी चीनी मिलें धड़ाधड़ स्थापित हो रही थीं. बड़े पूंजी घराने की इन चीनी मिलों को कर आदि में भारी रियायत दी गई. निगम की जो चीनी मिलें फायदे में थीं उसके क्षेत्र का गन्ना भी निजी चीनी मिलों को दे दिया गया. यूपी में मायावती सरकार ने निगम की 21 चीनी मिलें बेच डालीं. ■

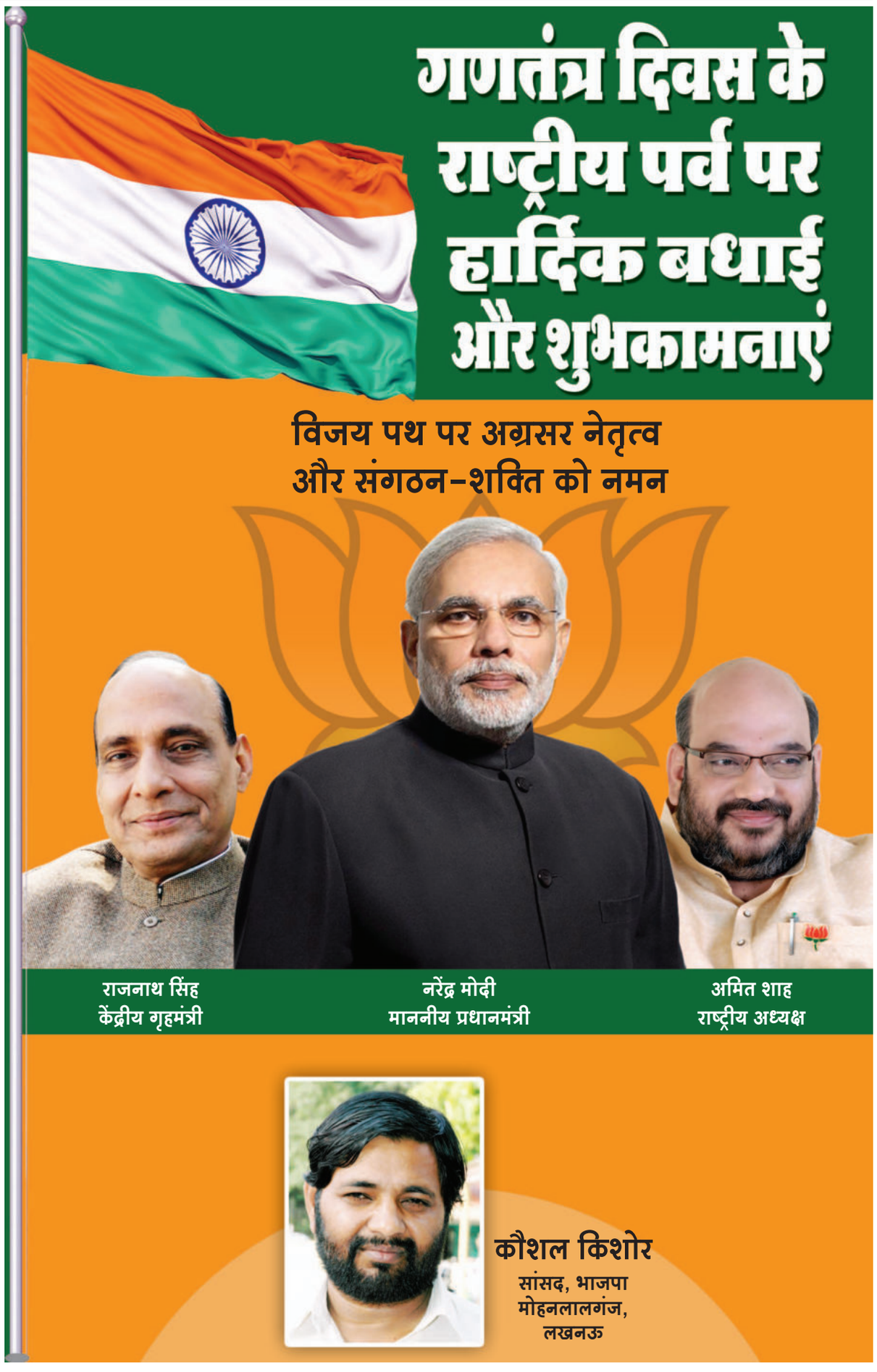

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

सीएम बोले किसान समाजवादी होंगे तभी खुशहाल होंगे

बेचारे किसानों का बेचारा अनशन

पृष्ठ 17 का शेष

मार डाला. गन्ना किसान अब गन्ने की खेती करने से भाग रहा है. गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के सरकारी आंकड़े सरासर धोखा हैं. प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का नहीं बल्कि चीनी मिल मालिकों का भला किया है. इसका पूरा तथ्य केवल उनके पास ही नहीं, प्रदेशभर के किसानों के पास है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस अपराधिक रवैये के कारण कई चीनी मिलें बंद हो रही हैं. प्रदेश में 11 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में गन्ना बोआई के क्षेत्रफल में तेजी से गिरावट आई है. विभागीय सर्वे में भी स्पष्ट हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गन्ना क्षेत्रफल 1,50,378 हेक्टेयर कम है. गन्ने की खेती के केंद्र माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल में कमी छह प्रतिशत से ज्यादा है. सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ व बरेली में किसान अब गन्ना बोने से परहेज कर रहे हैं. पश्चिम में शामली, संभल, मथुरा व मुजफ्फरनगर के अलावा सभी जिलों में गन्ना क्षेत्र घट गया है. फैजाबाद में भी एक साल में गन्ना क्षेत्रफल 40 फीसद कम हो गया. बाराबंकी, पीलीभीत, हरदोई और सीतापुर के किसान भी गन्ने की खेती से बचने लगे हैं. मध्य क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल 7.6 फीसद कम हुआ है. पूर्वांचल में भी ऐसे ही हालात हैं.

इसके बाद अब धान पैदा करने वाले किसानों को मारे जाने की साजिश की जा रही है. किसान नेता ने कहा कि पूंजीवादी घरानों की साजिश के तहत सरकारें किसानों के खिलाफ काम कर रही हैं. उनकी फसलों का लागत-मूल्य भी वसूल नहीं होने पाए, इसकी साजिश है. माल किसी और का, दाम किसी और का' के हथियार से किसानों को मारा जा रहा है. फसलें तैयार करने में लागत चाहे जो आए, उसकी कीमत सरकार तय करेगी पर उसकी डोर पूंजी घरानों के हाथ से संचालित होगी. गेहूं, धान और गन्ना ही नहीं सब्जियों तक के दाम में किसानों की मौत सुनिश्चित की जा रही है. यह इसलिए हो रहा है कि किसान अपनी जमीन छोड़ कर शहरों की तरफ आजीविका के लिए भाग जाएं, उनके खेत औने-पौने दामों पर बिक जाएं और उन्हें बड़े-बड़े पूंजी घरानों को सौंप दिया जाए, ताकि कॉरपोरेट फार्मिंग की उनकी योजना कारगर हो सके. इन्हीं सोची-समझी साजिशों के तहत किसानों को तबाह किया जा रहा है. खेतों को कॉरपोरेट फार्मिंग में बदलने की साजिश के तहत ही प्रदेश की सरकार न्यूनतम मूल्य नहीं देती और केंद्र की सरकार भूमि अधिग्रहण कानून पर मनमाना अध्यादेश ले आती है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड), स्पेशल डेवलपमेंट जोन (एसडीजेड) और कॉरपोरेट फार्मिंग वगैरह पूंजी घरानों का हित साधने के लिए ही हैं. भारत का किसान शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करके पेट पालेगा और पूंजी-पशु उन्हीं किसानों के खेत पर फसलें उगाएगा, पूंजी बढ़ाएगा और नेताओं को भी उच्छिष्ट खिलाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

ताजमहल की खूबसूरती फीकी पड़ रही है

वैष्णवी वंदना

विश्व प्रसिद्ध ताज महल एक बार फिर से चर्चा में है. इस बार कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मसला इसकी फीकी पड़ती खूबसूरती को लेकर चिंता का है. अभी हाल ही में संसद में इस मामले पर चिंता जताई गई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग व उत्तर प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर वास्तविक स्थिति की जानकारी देने को कहा गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञों का दल नियुक्त कर इसकी जांच करने की भी जरूरत महसूस की गई. ताजमहल के संरक्षण से जुड़े केंद्रीय पर्यावरण सचिव के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भी पर्यावरण संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सामने स्वीकार किया कि ताज पर प्रदूषण का असर काफी दिख रहा है. ताज महल की फीकी पड़ती चमक और संरक्षण को लेकर वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं और इस धरोहर की चमक कम करने वाले खतरों से सरकार को अगाह भी किया जाता रहा है, बावजूद इसके इस वैश्विक धरोहर की रक्षा के लिए कोई ठोस और स्थाई कदम अभी तक नहीं उठाया जा सका है.

शिल्प कला का बेजोड़ नमूना ताज धीरे-धीरे अपनी खूबसूरती और चमक खोता जा रहा है. लगभग चार दशक पहले ही 1970 की शुरुआत में पर्यावरणविदों को ताजमहल की चमक कम होने का आभास हो गया था. इसकी चमक खोने का कारण जानने में लगे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने ताजमहल की फीकी पड़ रही दूधिया चमक की वजह कार्बन और धूलकण बताया. अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रदूषण की वजह से संगमरमर से बने ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है. जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर माइकल बर्गिन और उनकी टीम यह पता लगाने में सफल रही कि ताजमहल की चमक को फीका करने वाले प्रदूषित तत्व जैव ईंधन, अपशिष्ट, जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाले कार्बन कण और धूल कण हैं. इस अध्ययन में आईआईटी कानपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता भी शामिल थे. शोधकर्ताओं ने ताजमहल की चमक के फीका पड़ने की वजह जानने के लिए हवा के नमूनों की जांच करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया. इन उपकरणों को ताजमहल के कई स्थानों पर रखा गया और संगमरमर के नमूने लिए गए. उन्हें उपकरण के फिल्टर में और संगमरमर नमूनों पर भूरे ऑर्गेनिक कार्बन और काले कार्बन के कण मिले. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ताजमहल के हल्के पीलेपन की वजह लाखों की संख्या में आने वाले दर्शकों की सांस से निकलने वाली कार्बन डाईऑक्साइड गैस भी हो सकती है. वैसे इस मामले में जांच नेशनल इनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) द्वारा कराई जा रही है. इसके अलावा यमुना का सूखना भी मुख्य कारण माना जा रहा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में रेत के कण सामान्य से बहुत ज्यादा हैं लेकिन यदि यमुना में पर्याप्त पानी हो तो वायु में इनकी मात्रा कम हो सकती है. ताजमहल को सूखी और प्रदूषित यमुना से खतरे का अंदेशा पहले भी जताया जाता रहा है. इतिहासकार इरफान हबीब का मानना है कि ताजमहल के पीछे से बहने वाली यमुना ही ताजमहल की सुरक्षा की गारंटी है. उसमें जल स्तर हर हाल में बरकरार रहना चाहिए. वरदराजन समिति ने कहा था कि ताजमहल के आसपास की परिस्थितियों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. छुट्टी और सप्ताहांतों में होने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ भी ताज को क्षति पहुंचा रही है. विशेषज्ञों की मानें तो इस तरह की अनियंत्रित और गैर अनुशासित भीड़ जो यहां के नियमों का पालन नहीं करते हुए अपनी मनमानी करती है, उससे भी ताज को भारी नुकसान पहुंच रहा है. रोजाना हजारों की संख्या में आने वाले सैलानी अपने हाथों से ताज की दीवारों को रगड़ते और खुरचते हैं, जिससे ताज की चमक फीकी पड़ रही है. संगमरमर पर उभरे बदरंग धब्बों को देखकर ऐसा लगता है कि ताजमहल की खूबसूरती खत्म होने की शुरुआत हो गई है. यदि यह सिलसिला जारी रहा तो ताज की चमक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी.

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग भी समय-समय पर ताजमहल में होने वाली टूट-फूट की मरम्मत करा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन दूषित पर्यावरण से होने वाली हानि को दूर करने का उपाय तलाशने में वे कतई सचेष्ट नहीं होते. कुछ अर्सा पहले पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने प्रतिदिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण ध्वंसे जा रहे स्मारक और ताज की घिसती सीढ़ियों को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने स्मारक की सैर करने वाले सैलानियों की ताज में ठहरने की अवधि कम करने का प्रस्ताव दिल्ली मुख्यालय को भेजा था लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरह

का निर्णय नहीं लिया गया. ताज में उर्स के दौरान उमड़ने वाली सर्वाधिक भीड़ और गर्मियों में घटती पर्यटकों की संख्या के समय वातावरण में मौजूद गैसों के सैंपल लिए गए हैं. ताज के गुंबद पर लोगों की तादाद और उससे ताजमहल पर पड़ने वाले असर का ब्यौरा भी जमा किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या निर्धारित की जाएगी. लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी चाल से चल रही है. पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने ताज में बढ़ते सैलानियों की संख्या देखते हुए दबाव कम करने का मन बनाया है. इस बारे में मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें सलाह दी गई है कि मुख्य गुंबद पर एक समय में सैलानियों की संख्या निर्धारित कर दी जाए. बीते साल 80 लाख से अधिक देसी सैलानी ताजमहल देखने आए. इससे पहले के वर्षों में यह संख्या 30 से 35 लाख तक हुआ करती थी.

ताज के मुख्य गुंबद के भार उठाने की क्षमता का भी आकलन किया जा रहा है. एएसआई के एक अधिकारी ने ताज की नींव कमजोर होने को लेकर उठ रहे सवालों के बारे में कहा कि कुछ वर्षों पहले ही नींव में दरार पड़ने की घटना सामने आई थी लेकिन उसकी मरम्मत कर ली गई थी. ताज महल की देखरेख की जिम्मेदारी संभालने वाले पुरातत्व विभाग की लापरवाही और उत्तर प्रदेश प्रशासन की कुव्यवस्था भी ताज को बहुत नुकसान पहुंचा रही है. पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच खींचतान और बेवजह की सियासत भी ताज के लिए हानिकारक है. ताजमहल में मक़बरे के ऊपर बनी एक मीनार के तीन इंच झुकने की बात कही गई थी, लेकिन पुरातत्व विभाग इन ख़बरों को गलत बताता है. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बना कर इसे राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की थी. पुरातत्व विभाग का कहना है कि ताज की देखरेख उसके जिम्मे है तब उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच के लिए समिति कैसे बना सकती है.

विदेशियों को कम, घरेलू पर्यटकों को ज्यादा लुभा रहा है ताज

दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल की खूबसूरती शायद विदेशियों को रिझाने में नाकाम रही तभी तो इसके दीदार के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले तीन साल से लगातार कम हो रही है. वैसे तो भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है लेकिन इनमें से करीब ढाई फीसदी लोग ही ताजमहल को देखने पहुंचते हैं. दूसरी ओर, ताजमहल देखने वाले घरेलू पर्यटकों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि नायाब ताज देखने के लिए वर्ष 2012 में सात लाख 90 हजार विदेशी सैलानी आगरा आए. वर्ष 2013 में आगरा आने वाले विदेशी मेहमानों की संख्या सात लाख 40 हजार रह गई. वर्ष 2014 में ताजमहल देखने आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई. गत वर्ष छह लाख 94 हजार विदेशियों ने ही ताजमहल को देखने के लिए टिकट खरीदा. ताजमहल देखने आने वाले विदेशी मेहमानों की संख्या लगातार कम होने के बीच दिलचस्प तथ्य यह है कि देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में इस दौरान बढ़ी है. इन तथ्यों के मद्देनजर यह सवाल उठता है कि जब विदेशी पर्यटकों का भारत आना बढ़ रहा है तो ताजमहल देखने आने वाले इन मेहमानों की संख्या में कमी क्यों आ रही है. पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कुछ जानकार ताजमहल देखने आने वाले विदेशी मेहमानों की संख्या में कमी होने को टिकटों की बिक्री की हेराफेरी की आशंका जता रहे हैं. ताजमहल देखने के लिए टिकटों की बिक्री से ही यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या की गणना होती है. विदेशी पर्यटकों के लिए ताजमहल देखने के वास्ते एक टिकट की कीमत 750 रुपये हैं. एक ही टिकट पर कई बार विदेशी पर्यटकों के ताजमहल परिसर में जाने की जानकारी मिलती रहती है. ऐसे में विदेशी पर्यटकों की सही संख्या का आकलन नहीं हो पाता.

ओबामा के दर्शनार्थ खोली जाएंगी कब्रें

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां और साम्राज्ञी मुमताज महल की मुख्य कब्रें खोली जाएंगी. व्यवस्थाओं का जायजा लेने आगरा आई अमेरिकी टीम ने ताज के बंद हिस्सों में भी दिलचस्पी दिखाई. टीम ने एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक निरीक्षण कर सुरक्षा की जानकारी जुटाई. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि हैं. वह आगरा भी आ सकते हैं. उनके संभावित कार्यक्रम के चलते निरीक्षण और व्यवस्थाओं का जायजा लेने 40 सदस्यीय अमेरिकी टीम मारजा वेरलूप के नेतृत्व में आगरा पहुंची थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूरा की फरारी पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी

तीन पखवारे के बाद भी भूरा की फरारी उत्तराखंड पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है. दस लाख का इनामी भूरा ने अपने साथ चलने वाले उत्तराखंड पुलिस को जिस तरह उन्हें मद मस्त करके चकमा देकर सरकारी अत्याधुनिक हथियारों को अपनी मित्र पुलिस से लूट कर चम्पत हो गया. देहरादून के सहसपुर के धर्मावाला पुलिस चौकी के पास बीते दिनों एक संदिग्ध कार मिली थी. उसके बाद पुलिस महकमे में इस बात को लेकर भी हड़कंप मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी राहुल खट्टा और उसके साथी उत्तराखंड में छिपे हो सकते हैं. सुनील राठी और अमित उर्फ भूरा को सूचनाएं भेजने में शामिल रहे राहुल खट्टा की संलिप्तता भूरा की फरारी से भी जोड़ी जा रही है. उसके लिए राज्य के डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. कुख्यात बदमाश सुनील राठी और भूरा के बीच लम्बे समय तक राहुल खट्टा ने सूचनाओं का आदान-प्रदान किया था. बीते दिनों लूट में इस्तेमाल की गई कार सहसपुर के धर्मावाला चौकी के पास मिली. कार के पीछे की सीट पर खून के धब्बे होने से मेरठ लूट की बात की पुष्टि हुई है. ऐसे में राहुल खट्टा और उसके साथियों के राज्य में छिपे होने की प्रबल आशंका जताई जा रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि भूरा की फरारी में राहुल खट्टा का भी हाथ हो सकता है. पुलिस ने इस दिशा में भी जांच शुरू कर दी है. राज्य पुलिस के मुखिया बीएस सिद्धू ने कहा कि राहुल खट्टा बैंक, एटीएम और कैश वैन को निशाना बना सकता है. ऐसे में सभी जिलों की पुलिस और बैंकर्स सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें. कहा कि दून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और पहाड़ी जिलों में निगरानी बढ़ाई जाए. इधर, भूरा मामले में खट्टा की संलिप्तता पर पुलिस पड़ताल में जुट गई है. इसके लिए ऑपरेशन में जुटी टीमों के अलावा खुफिया तंत्र जांच में लगे हुए हैं. इन लूटों में शामिल रहा राहुल खट्टा एक लाख रुपये का ईनामी बदमाश है. 2010 में तिहाड़ जेल से फरारी के दौरान जब भूरा ने दिल्ली में कैश वैन से तीन करोड़ लूटे थे, इस समय राहुल खट्टा, भूरा के साथ शामिल बताया गया. 2014 में उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर में एटीएम लूटने की घटना में भी राहुल खट्टा का नाम सामने आया था. जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में कैश वैन, एटीएम और बैंक लूट की घटनाओं में सबसे अधिक खट्टा का नाम ही सामने आया था. जिसके बाद खट्टा को ईनामी घोषित कर दिया था. डीआईजी को दिए निर्देश धर्मावाला में लग्जरी कार में खट्टा की मौजूदगी के बाद डीजीपी ने गढ़वाल और कुमाऊं के डीआईजी के साथ बैठक कर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. खासकर राज्य के सभी बैंक, एटीएम और कैश वैनों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है. डीजीपी ने दोनों मंडलों के डीआईजी को संबंधित जिलों की पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सभी बैंकर्स को भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं. सहसपुर में कार लावारिस छोड़ने के बाद राहुल खट्टा और उसके साथी हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, विकासनगर, ऋषिकेश जैसे आबादी वाले क्षेत्रों में कहीं भी छिपे हो सकते हैं. खासकर लग्जरी होटलों में ठहरने की कोशिशें भी खट्टा कर सकता है. राज्य में पर्यटक बनकर और कारोबारी के रूप में भी बदमाश पहचान और नाम छिपाकर रह सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, दून के एकांत क्षेत्रों में बने होटल बदमाशों के लिए सुरक्षित ठिकाना बताया जा रहा है. उत्तराखंड पुलिस में दागी पुलिस अफसर के हाथ विभाग की कमान देना सरकार के लिए मुसीबत बन गई है. ■

-राजकुमार शर्मा

सेना केदारनाथ धाम को आबाद करेगी

आपदा में पूरी तरह तबाह हो चुके केदारधाम को सेना के प्रयास से आबाद किया जा रहा है, सूबे की सरकार की मदद में लगी सेना ने केदारधाम के दिन बहुरने के संकेत दिए है. केदारनाथ के पुनर्निर्माण में जुटी सेना की टीम ने भरोसा दिलाया है कि अप्रैल-मई में जब पुनः चारधाम यात्रा शुरू होगी तब तक केदारनाथ में पांच हजार लोगों के रुकने के लिए पक्के भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा. केदारनाथ में मंदाकिनी की तरफ एंटी लैंडिंग वाल बनाई जा रही है जो पांच मीटर तक ऊंची होगी. इससे फायदा यह होगा कि बाढ़ आने की स्थिति में केदारनाथ की तरफ पानी नहीं घुसेगा. ऐसी ही दीवार हाल में निर्मित हैलपीपैड पर भी बनाई गई हैं जहां अभी एमआई-26 उतरा है. अभी हाल में एमआई-26 हेलीकॉप्टर के केदारनाथ में उतरने के बाद सेना ने निर्माण कार्य में तेजी लानी शुरू कर दी है. हेलीकॉप्टर के जरिए वहां भारी मशीनें पहुंचनी शुरू हो गई हैं. टीम का नेतृत्व कर रहे और एनआईएम के हेड कर्नल अजय कोटियाल ने चौथी दुनिया ब्यूरो को बताया कि केदारनाथ में डेढ़ फुट बर्फ में हमारी टीम दिन रात जुटकर कार्य कर रही है. एमआई-26 के उतरने के बाद हमारे पास जेसीबी, क्रेन आदि मशीनें पहुंचने लगी हैं. इन मशीनों की मदद से पुराने ढांचे को गिराकर नए बनाने का कार्य शुरू किया है. पहले ही 25 डिजास्टर प्रूफ कॉटेज वहां पहले ही बनाए जा चुके थे. सबसे पहले लगभग चार दर्जन मकानों, सरकारी भवनों को तोड़कर उन्हें नया बनाया जाएगा इसमें सरकारी कार्यालय, होटल, गेस्ट हाइस आदि शामिल हैं. रामबाड़ा से एक नया रास्ता जो मंदाकिनी को पार कर इसके दाहिनी तरफ से केदारनाथ तक के लिए बनाया गया है, वह गर्मियों में खोल दिया जाएगा. सेना की कोशिश है कि अप्रैल के अंत तक न सिर्फ इस रास्ते से आवाजाही शुरू हो बल्कि पांच हजार लोगों के केदारनाथ में स्थाई भवनों में रहने का इंतजाम हो जाए. केदारनाथ में मंदाकिनी की तरफ एंटी लैंडिंग वाल बनाई जा रही है जो पांच मीटर तक ऊंची होगी. इससे फायदा यह होगा कि बाढ़ आने की स्थिति में केदारनाथ की तरफ पानी नहीं घुसेगा. इस कार्य में कोटियाल के नेतृत्व में सेना के जवानों के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंटेनियरिंग के वालंटियर भी लगे हुए हैं. साथ ही कोटियाल ने उत्तराखंड के सेवानिवृत्त सैन्यकार्मिकों को भी इस कार्य में लगाया है. ■

-चौथी दुनिया ब्यूरो

अंतर्कलह की वजह से छावनी परिषद चुनाव में भाजपा हारी

देश की सांस्कृतिक राजधानी और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के छावनी परिषद चुनाव में भाजपा की करारी हुई, जिसने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के माथे पर सर्द मौसम में भी पसीना ला दिया है. छावनी परिषद के चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों की पराजय ने एक बार फिर भाजपा के रणनीतिकारों की कलई खोलने के साथ ही उन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया है. भाजपा की पराजय का यह सिलसिला बीते निकाय चुनाव से ही शुरू है. विधानसभा उपचुनावों और पंचायत चुनावों में भाजपा की करारी हार हो चुकी है. उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेताओं ने हार के कारणों को तलाशने की कोशिश नहीं की. छावनी परिषद जैसे चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की हार ने यह साबित कर दिया कि यदि भाजपा हाईकमान जल्द टीम तीरथ के भविष्य पर निर्णय नहीं लेगा तो मिशन-2017 में भाजपा को कामयाबी मिलने में संदेह है. राज्य में लगातार कांग्रेस को मिल रही सफलता से प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत की छवि चमकती जा रही है. इस संदर्भ में जनता में लगातार सकारात्मक संदेश जा रहा है. छावनी परिषद के चुनावों में भी भाजपा की हार की मूल वजह जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना ही है.

केवल गणेश परिक्रमा करने वाले जनाधार हीन लोगों को इस बार भी टिकट दिया गया जिसके कारण भाजपा हार का मुंह देखना पड़ा. जिन जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए था, उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया. कई निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को मिली शानदार जीत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पार्टी कि दुर्दशा के लिए दिग्गजों की दो-गली नीति ही जिम्मेदार है. टीम तीरथ को लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद से ही लगने लगा था कि मोदी लहर प्रदेश में लंबे समय तक चलेगी. प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता जनता की समस्याओं से दूर हटते गए. भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग भाजपा नेताओं के पास नहीं है. यदि टीम तीरथ वाकई गंभीर होती तो निकाय चुनाव में हुई हार के बाद आत्मचिंतन करती, लेकिन भाजपा के नेता केवल कागजी बयानबजी में उलझे रहे. जिसका परिणाम छावनी परिषद के चुनाव में भी देखने को मिला. ऐसे में टीम तीरथ से मिशन-2017 की सफलता की उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती. भाजपा की लगातार हार से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी अब ठंडा पड़ने लगा है. अब सबकी नजरें हाईकमान की ओर टिकी हैं कि कब भाजपा हाईकमान टीम तीरथ के भविष्य का फैसला करेगा और हार की वजह जानने की कोशिश करेगा. पांच के पाच सांसद देने वाले हिमालयी राज्य में मोदी लहर की निकलती हवा अमित शाह तक को बेचैन कर दिया है. हाईकमान की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश भाजपा में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. गुटबाजी का ताजा उदाहरण बीते दिनों प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित सचिवालय कूच के दौरान देखने को मिला. सचिवालय कूच में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जरूर उमड़ी, मगर बड़े नेता धरना-प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए. जिससे एक बार जनता में फिर नकारात्मक संदेश गया कि भाजपा के दिग्गजों के पांव जमीन पर अब भी नही है. बीते दिनों भाजपा का सचिवालय कूच प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुआई में आयोजित किया गया. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेताओं को इस कूच में आमंत्रित किया गया. बावजूद भाजपा के पांच सांसद सहित पूर्व सांसद सतपाल महराज सहित दिग्गज देहरादून में मौजूद रहते हुए भी पार्टी द्वारा आयोजित धरना स्थल पर नहीं पहुंचे. चौंकाने वाली बात यह है कि धरना स्थल पर नहीं पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता फोन द्वारा कार्यकर्ताओं से दिन भर इस बात की जानकारी संग्रह करने में जुटे रहे कि सचिवालय कूच के दौरान पार्टी के किस गुट के नेता शामिल हुए. जब पार्टी सरकार के खिलाफ ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन कर रही है तो ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल न होना इस बात को दर्शाता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता केवल निजी स्वार्थों की ही राजनीति प्रदेश में कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले नेता सरकार के खिलाफ कागजों में ही बयानबाजी करने में माहिर माने जाते हैं. ऐसे में संगठन किस तरह से सशक्त होगा. यह बात भाजपा हाईकमान को गंभीरता से समझना पड़ेगा. जनहित से जुड़े मुद्दों को भविष्य में पार्टी जोरशोर से उठाएगी. अब समय आ गया है कि भाजपाई सड़क से लेकर सदन तक सरकार की कलई खोलें. अगर ऐसे ही भाजपा के दिग्गजों में गुटबाजी फैली रही है तो भाजपा का सपना मिशन-2017 अधूरा रह सकता है. ■

-रेनू शर्मा

मोक्षदायनी गंगा लाशों को कब तक ढोएगी

वैष्णवी वंदना

मीडिया में खबरें नहीं आती की उन्नाव में गंगा नदीं में सैकड़ों लाशें पड़ी हैं, तो यह बात सार्वजनिक तौर सबके सामने नहीं आ पतीी. गंगा को गंदा करने वाले वही रूढ़िग्रस्त लोग हैं, जो लाशों को जलाते नहीं, बल्कि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं. धर्म के नाम पर हो रहा यह वीभत्स कर्म नदियों को तीव्र गति से प्रदूषित कर रहा है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव जिले में परिहार घाट के पास नाले जैसी हो चुकी गंगा में फंसी लाशों को देख कर मीडिया ने सनसनी फैला दी. टीवी चैनेलों पर लाशें दिखाई जाने लगीं और सनसनीखेज संदेह के सवाल उछाले जाने लगे. इस पर इलाके के पढ़े लिखे लोगों का कहना था कि जब लाशें गंगा में यूं ही प्रवाहित की जाती हैं तब टीवी चैनल वाले उनसे पूछते नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो. कर्मकांड के नाम पर यह धतकरम बड़े पैमाने पर हो रहा है. इसे धार्मिक कृत्य समझ कर पुलिस-प्रशासन चुप्पी साधे रहता है. नेता को इसमें वोट नहीं दिखता. एनजीओ को इसमें पैसा नहीं दिखता. पत्रकार लाशें इकट्ठी होने का इंतजार करते हैं. इलाके के लोग गंगा में धार आने का इंतजार करते हुए सड़ांध भोगते रहते हैं.

उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र में परियारघाट के निकट गंगा नदी में सौ सवा सौ लाशें पाए जाने की खबरों से अचानक हड़कंप जैसा मच गया. पुलिस प्रशासन के अलावा अखबारों के दफ्तरों में फोन घनघनाने लगे. अखबार वालों ने फौरन राज्य के पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) ए. सतीश गणेश का फोन खड़काया. आईजी ने बताया कि परिहारघाट के पास पानी कम होने के कारण उसमें फंसे शव मिले हैं. शव काफी पुराने हैं. कई शवों पर तो कफन भी बंधा हुआ पाया गया है. आईजी ने भी कहा कि इस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों की मृत्यु के बाद उनकी लाशों को प्रवाहित करने की परम्परा है. कुंवारों और बच्चों के शव को भी गंगा में प्रवाहित करने की परम्परा है. यह काम रोजाना होता है और बृहत्तर इलाके में होता है. इसके अलावा जहां शव बरामद हुए हैं वहां गंगा का एक किनारा कानपुर के बिठूर का भी लगता है. उसके निकट ही शमसान घाट भी है. बिठूर घाट पर कन्नौज, बिल्हौर आदि जगहों से शव बहते हुए आ जाते हैं. यही शव परियार गांव की

ओर किनारे लग जाते हैं और इन शवों को खाने के लिए चील, कौओं के साथ ही कुत्ते और सियार टूट पड़ते हैं. गांव के लोग इस त्रासद अनुभव से गुजरते हुए इसके आदी हो चुके हैं. यह वीभत्स दृशय मीडिया को कभी नहीं दिखता. धार्मिक आस्था और मान्यता के कारण प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस भी लोगों को शव प्रवाहित करने से नहीं रोकती. घटनास्थल के समीप रहने वाले परिहार गांव के लोगों का कहना है कि शवों का इस तरीके से दिखना तो आम बात है. यहां साल में एक बार यह नजारा देखने को जरूर मिलता है. परियार गांव से करीब एक किलोमीटर पर ही शमशान घाट बना हुआ है. गांव के लोगों ने कहा कि हर साल जाड़े के महीनों में काफी शव इसी तरह ऊपर आ जाते हैं, लेकिन कभी कोई मीडिया वाला या प्रशासन का अधिकारी नहीं झांकता. लोगों ने कहा कि कई लोग शवों को पूरा नहीं जलाते और कई गरीबी के चलते लाशों को सीधे गंगा में प्रवाहित कर देते हैं. दाह संस्कार कराने वाले कर्मकांडी पंडे भी चंद रुपये के लिए शवों को जलाने के बजाय गंगा नदी में प्रवाहित करा देते हैं. कर्मकांड कराने वाले पंडे एक लाश के कम से कम 500 रुपये वसूलते हैं और फिर उसे ऐसे ही गंगा में बहवा देते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी यहां फटकते नहीं और इसीलिए कर्मकांड कराने वाले पंडे अराजक होकर गंगा से और पर्यावरण से खुलेआम खिलवाड़ करते जा रहे हैं. इस पर कोई रोकटोक नहीं है.

बहरहाल, गंगा में सौ से अधिक शव मिलने की हड़कंप मचाती खबर पाकर जोनल आईजी आशुतोष पांडेय के अलावा कानपुर नगर व उन्नाव के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर भागे. जब वहां पहुंचे तब माजरा समझा. जेसीबी मंगवाकर गड्ढे कराए गए और शवों को दफनाया गया. मौके पर सियासत सेंकने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी के साथ ही उन्नाव सदर के विधायक भी पहुंच गए. यही नेता आम लोगों की रूढ़िवादी विचारों को खत्म करने और लोगों में समझ पैदा करने का कोई प्रयास नहीं करते, बल्कि उसे और बढ़ाते हैं. मां गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान समिति के संयोजक रामजी त्रिपाठी तो ब्रह्मावृत घाट पर धरना देकर बैठ गए. इलाके के लोगों ने कहा कि धर्म के नाम पर होने वाले गंदे कर्मकांडों के खिलाफ ये लोग कभी धरना आदि पर नहीं बैठते और न कभी कोई जागरूकता का कार्यक्रम ही आयोजित करते हैं. इस मामले में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि यूपी सरकार को पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए. मौके पर मौजूद आईजी आशुतोष पांडेय ने कहा शमशान घाटों पर भी लोग शवों को पूरा जलाते नहीं हैं और उसे नदी में फेंककर चले जाते हैं. यह प्रकरण कोई जांच का विषय का नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पानी की कमी को देखते हुए शमशान घाट को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है. इस सिलसिले में उन्होंने डीएम से भी बातचीत करने का आश्वासन दिया. श्री पांडेय ने कहा कि गंगा की स्ट्रीम रोकने की वजह से भी पानी काफी कम हो गया है. इसके चलते इसमें प्रवाहित शव नदी में उतराने लगे हैं. इसमें प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है. इतनी तादाद में शवों के आने की बड़ी वजह यह भी है कि गरीब लोग पैसे के अभाव में शवों का दाह संस्कार करने के बजाय उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं. अब जिला प्रशासन को यह देखना होगा कि कोई यहां दाह संस्कार नहीं कर पाए, क्योंकि यहां चेक डैम और गंगा की स्ट्रीम भी नहीं है. लाशें देखने की तो परिहार गांव के लोगों को आदत पड़ गई है. लेकिन इस खबर के अन्यत्र फैलने से बाहर-बाहर से लोग वहां जुटने लगे और भीड़ इकट्ठा होने लगी. राजधानी लखनऊ भी अधिक दूर नहीं है, तो लखनऊ से भी पत्रकार घटनास्थल की तरफ दौड़े. उन्नाव की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने भी पत्रकारों को शव बरामद किए जाने की खबर ब्रीफ की. इलाके में यह भी चर्च फैली कि बीते दिन जहरीली शराब के कारण मरने वाले लोगों की लाशें तो नहीं गंगा में फेंक दी गईं. लेकिन यह महज अफवाह ही साबित हुई. बरामद हुई लाशें काफी पुरानी थीं.

मौके पर गंगा की जो तस्वीरें खींची गईं, वे खुद ब खुद गंगा की दुर्दशा दिखाती हैं और गंगा सफाई के नाम पर हो रही सियासत की असलियत का प्रदर्शन करती हैं. गंगा की दुर्दशा दिखाती ये तस्वीरें प्रदेश और केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों की संवेदनशीलता को नहीं छूतीं. नेता मुंह बिचकाते हैं और नदियों की स्वच्छता पर राजनीति करते हैं. गंगा का पानी खून और मांस के लोथड़ों से पटा रहता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखीमपुर खीरी

26वां सड़क सुरक्षा सप्ताह
(दिनांक 11 जनवरी 2015 से 17 जनवरी 2015 तक)
Safety is not just a slogan; it is a way of life.

सड़क पर सुरक्षित यात्रा हेतु निम्न बातों का ध्यान दें:-
1. नशे की हालत में वाहन न चलायें.
2. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें.
3. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें.
4. विद्यालय/स्कूल के निकट वाहन धीमी गति से चलायें.
5. चकाचौंध करने वाली (डिजिटल तथा अनाधिकृत अतिरिक्त) लाइटों का प्रयोग वर्जित है.
6. वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें.
7. समस्त व्यावसायिक वाहनों में नियमानुसार रिफ्लेक्टिव टेप लगवायें.

संजीव कुमार गुप्ता-ए.आर.टी.ओ. (प्रवर्तन) लखीमपुर-खीरी
श्वेता वर्मा-ए.आर.टी.ओ. (प्रशासन) लखीमपुर-खीरी
अरविन्द सेन-पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर-खीरी
गौरव दयाल-जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी

> मलिहाबादी आम के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में जहरीली शराब का धंधा घरेलू उद्योग की तरह फैला हुआ है. आबकारी महकमे और पुलिस के संरक्षण में एक दर्जन से अधिक गांवों में करीब तीन दर्जन भट्टियों में जहरीली शराब बनाई जाती है. मलिहाबाद के दतली गांव में बनने वाली कच्ची शराब आस-पास के गांवों में भी सप्लाई होती है. आस-पास के गांवों के लोग शराब पीने दतली गांव आते-जाते हैं. अवैध शराब का धंधा पुलिस की शह और संरक्षण में चलता है. यही वजह है कि दतली के लगभग हर घर में कच्ची शराब बनती है. जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद दतली, पहाड़पुर, खड़ता, रामपुर, गोडवा, बरौजा और भोगला जैसे गांवों में कोहराम मचा हुआ है.

जहरीली शराब मौत का कारोबार बनी

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के लोग जहरीली शराब पी रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जहरीली शराब यहां के लोगों को पी रही है. सरकार ने लोगों के लिए जितने ही वैध दारूखाने खोल रखे हैं उतने ही अवैध. जी हां, अवैध दारूखाने और अवैध शराब के धंधे भी सरकार की जानकारी में ही चलते हैं और फलते-फूलते हैं. इसी अवैध शराब ने हाल ही में लखनऊ और उन्नाव के करीब 39 लोगों की मौत हो चुकी है और यह संख्या और अधिक हो सकती है. तकरीबन दो सौ लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इन बीमार लोगों में से भी कई लोग मरेंगे. जहरीली शराब के कारण लोगों के मरने की खबरें रुटीन तरीके से आती रहती हैं और इसे बनाने का धंधा रुटीन तरीके से चलता रहता है. अभी जहरीली शराब पीने से मरने वालों में लखनऊ के मलिहाबाद, सरोजनीनगर और उन्नाव के लोग शामिल हैं. कुछ ही दिन पहले आजमगढ़ और वाराणसी के लोग मरे थे. इस तरह की मौतों का सिलसिला जारी है.

पिछले दिनों लखनऊ के पास मलिहाबाद के गांवों में एक के बाद एक लोगों के दम तोड़ने की खबरें पहुंचने लगीं. पुलिस और प्रशासन तो जानता ही है कि अवैध शराब किन-किन ठिकानों पर बनती है. बस, उन जगहों पर तलाशी और छापामारी की नौटंकी शुरू हो गई. लेकिन इसके पहले ही नाराज ग्रामीणों ने अवैध शराब बनाने वालों के घर जलाने शुरू कर दिए. पुलिस ने बचाव में उतर उनकी भट्ठियां, भारी मात्रा में महुआ, शराब बनाने के काम आने वाले केमिकल और तैयार शराब नष्ट होने से बचा ली. दतली गांव में भुइयां देवी मंदिर के मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट देखने आसपास के गांव से लोग आए थे. सैफई का मजा वे दतली में क्रिकेट मैच देख कर और घटरू की शराब पीकर लेना चाहते थे. मैच देखने के बाद लोगों ने जुगनू और घटरू की बनाई हुई देसी शराब उड़ाई. ग्रामीणों का कहना है कि शराब पीने वालों को उल्टियां होने लगीं और दिखाई देना बंद होने लगा. पुलिस को सूचना दी गई लेकिन तब कोई पुलिस वाला नहीं आया. इसके बाद ग्रामीण खुद ही बीमार लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भागे. लेकिन लोगों के मरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह खत्म ही नहीं हुआ. देखते-देखते मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहरीली शराब के शिकार लोगों की भीड़ बढ़ने लगी. हालात बेकाबू होते देख मरीजों को लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर भेजा जाने लगा. तब तक मलिहाबाद के दर्जन भर लोग

दम तोड़ चुके थे. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. राजेश श्रीवास्तव खुद कहते हैं कि जहरीली शराब पीने से गंभीर हालत में कुल 88 मरीज पहुंचे थे, जिसमें कई महिलाएं भी थीं. क्रिकेट मैच देखने के लिए दूर-दूर के गांवों से लोग आए थे. इनमें पड़ोस के उन्नाव जिले से भी कई लोग पहुंचे थे. सरोजनी नगर से भी लोग आए थे. देखते-देखते उन्नाव के छह लोगों ने और सरोजनी नगर के चार लोगों ने दम तोड़ दिया.

खास बात यह है कि आबकारी का महकमा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ही तहत रख रखा है. अवैध शराब का गोरखधंधा तो वे रोक नहीं पाते, लेकिन अवैध शराब पीने से लोगों के मरने के बाद कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने की रस्म जरूर पूरी करने लगते हैं. इस घटना के बाद भी मुख्यमंत्री ने जिला आबकारी अधिकारी समेत एसडीएम और सीओ को निलंबित कर दिया. निलंबित लोगों में जिला आबकारी अधिकारी लाल बहादुर यादव, एसडीएम, सीओ मलिहाबाद श्यामाकांत त्रिपाठी, इंस्पेक्टर मलिहाबाद अमर सिंह रघुवंशी, आबकारी इंस्पेक्टर वीवी मिश्रा सहित आबकारी के छह व मलिहाबाद थाना के आठ सिपाही शामिल हैं. सूबे के आबकारी आयुक्त अनिल गर्ग और लखनऊ के संयुक्त आयुक्त से भी मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण मांगा है. सरकार ने जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवार को दो-दो लाख रुपये देने और बीमारों के मुफ्त इलाज की भी घोषणा की है.

जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद पुलिस ने सक्रियता का प्रहसन खेलते हुए उस जुगनू को गिरफ्तार किया जो जहरीली शराब बनाने का धंधा करता है. मलिहाबाद के खड़ता गांव के प्रधान राममूर्ति ने दतली गांव के जुगनू, पुष्पा, जगदीश उर्फ गटरू, फूलचंद व भूपेन्द्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. हादसे के पहले ग्राम प्रधान को अवैध शराब के धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं था. जबकि स्थानीय लोग खुलेआम कहते हैं कि स्थानीय विधायक से लेकर तमाम ग्राम प्रधानों और छुटभैया नेताओं से लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों तक को अवैध शराब के इस धंधे का फायदा पहुंचता है. इसी वजह से इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती.

मलिहाबादी आम के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में जहरीली शराब का धंधा घरेलू उद्योग की तरह फैला हुआ है. आबकारी महकमे और पुलिस के संरक्षण में एक दर्जन से अधिक गांवों में करीब तीन दर्जन भट्टियों में जहरीली शराब बनाई जाती है. मलिहाबाद के दतली गांव में बनने वाली कच्ची शराब आस-पास के गांवों में भी सप्लाई होती है. आस-पास के गांवों के लोग शराब पीने दतली गांव आते-जाते हैं. अवैध शराब का धंधा पुलिस की शह और संरक्षण में चलता है. यही वजह है कि दतली के लगभग हर घर में कच्ची शराब बनती है. जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद दतली, पहाड़पुर, खड़ता, रामपुर, गोडवा, बरौजा और भोगला जैसे गांवों में कोहराम मचा हुआ है. पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे मजदूरी करते हैं, जबकि कुछ लोग छोटा व्यवसाय करते हैं. ऐसे ही एक पीड़ित परिवार के सदस्य राजेश सिंह ने ट्रॉमा सेंटर पर कहा कि दतली गांव में शराब बनती है और यह सब पुलिस की शह पर होता है. शाम होते ही वहां आस-पास के गांव वालों का जमावाड़ा लग जाता है. लोग कभी-कभी वहां से पीकर आते हैं तो कभी-कभी घर पर ले जाते हैं. इस तरह कई लोगों ने बताया कि मलिहाबाद में 10 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन तीन दर्जन गांवों में अवैध शराब की भट्ठियां धधक रही हैं. शराब के अवैध कारोबारियों से हर महीने लाखों की वसूली होती है.

खास बात यह है कि आबकारी का महकमा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ही तहत रख रखा है. अवैध शराब का गोरखधंधा तो वे रोक नहीं पाते, लेकिन अवैध शराब पीने से लोगों के मरने के बाद कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने की रस्म जरूर पूरी करने लगते हैं. इस घटना के बाद भी मुख्यमंत्री ने जिला आबकारी अधिकारी समेत एसडीएम और सीओ को निलंबित कर दिया. निलंबित लोगों में जिला आबकारी अधिकारी लाल बहादुर यादव, एसडीएम, सीओ मलिहाबाद श्यामाकांत त्रिपाठी, इंस्पेक्टर मलिहाबाद अमर सिंह रघुवंशी, आबकारी इंस्पेक्टर वीवी मिश्रा सहित आबकारी के छह व मलिहाबाद थाना के आठ सिपाही शामिल हैं.

पुलिस और आबकारी विभाग के अफसर मलिहाबाद में आम के बागों में जहरीली शराब की खेती करवा रहे हैं. गांवों में अवैध शराब की भट्ठियां खुलेआम चल रही हैं. आम के बागों में पेड़ों के नीचे जगह-जगह प्लास्टिक के गैलन में जहरीली शराब बनाई जा रही है. पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी सब जानते हैं, लेकिन हर महीने करीब लाखों रुपये की वसूली के चलते कभी कार्रवाई नहीं करते. उल्टा, अवैध शराब बनने की सूचना देने पर कार्रवाई की जगह धमकियां मिलती हैं. मलिहाबाद इलाके में पहुंचते ही आप किसी से पूछें तो कहेगा मटरिया की बरफी और दतली की शराब पूरे इलाके में मशहूर है. स्पष्ट है कि दतली गांव में शराब का अवैध कारोबार न तो आबकारी विभाग से छिपा था और न ही पुलिसकर्मियों से. आम की फसल देने वाले बाग जहरीली शराब बनाने का अड्डा बन चुके हैं. हादसे के बाद भी पाया गया कि पेड़ों के नीचे मिट्टी में दबे मटके और प्लास्टिक के पीपों में जहरीली शराब बनाई जा रही थी. यहां तक कि अवैध शराब बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल पुलिस की जीप से आती थी. ग्रामीणों ने बताया कि दतली गांव में जगनू की शराब सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी. वह शराब में कोई खास केमिकल डालता था. ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुलिस की जीप में हर सप्ताह उसके लिए एक गैलन केमिकल आता था. माना जा रहा है कि यह मिथाइल अल्कोहल था. दरअसल मिथाइल अल्कोहल बाजार में बगैर लाइसेंस के नहीं मिलता. इसकी सप्लाई बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में कंटेनर के जरिए की जाती है. पुलिस ही जगनू को मिथाइल अल्कोहल उपलब्ध कराती थी और उससे मोटी रकम वसूलती थी. दतली गांव के अलावा शेरनगर, गदियाखेड़ा, लालताखेड़ा, तिलकखेड़ा, सेंरैयां, फत्तेपुर, कैथुलिया, रुसैना, शाहीखेड़ा, माधवपुर, मधवापुर, कलुआखेड़ा, जगदीशपुर, हासिमपुर, हरिहरपुर, मोहज्जीपुर, गोपालपुर, चांदपुर, खड़ौहां, गौंदा, चिहुंटा, मानखेड़ा, घोला, दुलारमऊ, भुलसी, दौलतपुर, अमानीगंज, सिरगामऊ समेत कई अन्य गांवों में भी अवैध शराब धड़ल्ले से बिकती है.

दतली गांव से शराब की सप्लाई उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी के अलावा दूसरे कई जिलों में होती है. पुलिस के हत्थे चढ़े जगनू के एजेंट वंशीलाल पासी ने बताया कि दतली गांव से शराब का अवैध कारोबार करने वाले उसे दूसरे जिलों में भेजते थे. जगनू की शराब वैन से पहुंचाई जाती थी. जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद एक्साइज इंटलीजेंस ब्यूरो (ईआईबी) को मामले की जांच के लिए लगाया जा रहा है. जहरीली शराब मामले के मुख्य आरोपी जगनू के कब्जे से 50 लीटर शराब और वैन बरामद हुई है. शराब परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजी जाएगी. ■

यूपी में कच्ची दारू का जाल बिछा है

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अवैध शराब का धंधा पसर रहा है. अवैध हथियारों का गढ़ माना जाने वाला आजमगढ़ आज अवैध शराब के धंधे के कारण मशहूर हो रहा है. राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद और गोसाईंगंज क्षेत्र में तो पुलिस के संरक्षण में ही अवैध शराब का धंधा फलफूल रहा है. मलिहाबाद के गांवों का हाल तो आपने देख लिया. अब देखिए गोसाईंगंज का दृश्य. गोसाईंगंज के मुल्ला खेड़ा, बजुआपुर, दुलारामऊ, खुजौली, परेहटा, सिकन्दरपुर, हसनपुर खेवली, जौखंडी जैसे दर्जनों गांवों में कच्ची शराब बनाने की भट्ठियां दिन रात धधक रही हैं. हसनपुर खेवली गांव में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का अवैध कारोबार फलफूल रहा है. इसकी लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस के पास है. लेकिन पुलिस को लोगों के मरने का इंतजार है. इंद्रा डैम (ड्रीम वैली) के पास घने जंगल में चलने वाला शराब का अड्डा भी चर्चा में है. इस अड्डे पर स्थानीय लोगों के अलावा अन्य जगहों के लोग भी मौज करने आते है. स्थानीय पुलिस वाले उन्हें सुविधाएं देते हैं. लखनऊ के नजदीकी जिले बाराबंकी में राम सनेही घाट कोतवाली कच्ची शराब के धंधे में अन्य किसी भी इलाके को पीछे छोड़ रहा है. कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने का धंधा धीरे-धीरे कुटीर उद्योग बनता जा रहा है. यहां महराजगंज, घुरघुटवा, इब्राहिमाबाद, जेठवनी, मठ, गाजीपुर, अल्पीपुरवा, बडेलानरायनपुर, टेमा, सुखीपुर, धुनौली, आदि गांवों में आबकारी विभाग व पुलिस की मिलीभगत से कच्ची शराब का धंधा जोर-शोर से चल रहा है. गांव-गांव में शराब की भट्ठियां धधक रही हैं. यही अवैध शराब लोगों की मौत का कारण भी बनती है. उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के मुख्यालय इलाहाबाद में ही अवैध शराब गांव-गांव में बन रही है. यहां के सोरांव नवाबगंज, नैनी, बारा, लालापुर व कौंधियारा में शराब का कारोबार कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है. कौशाम्बी के पूरामुफ्ती, चरवा, मंझनपुर, सैनी, करारी व सरायअकिल में भी यह धंधा फल-फूल रहा है. वाराणसी के आसपास देसी दारू बनाने का धंधा लम्बे समय से चल रहा है. मुश्किल से ऐसा कोई जिला होगा जहां जहरीली शराब से मौतें न हुई हों.

लखनऊ के सरोजनीनगर, तालकटोरा, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, काकोरी व बंथरा सहित अन्य क्षेत्रों में तस्कर भारी मात्र में महुआ व गुड़ का सीरा मिलाकर शराब बनाते हैं. इसमें नशा पैदा करने के लिए यूरिया खाद व ऑक्सीटोसीन दवा का इस्तेमाल किया जाता है. लखनऊ में ही देसी शराब के करीब चार सौ ठेके हैं. तकरीबन ढ़ाई सौ ठेके लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. लेकिन अवैध ठेकों का तो जाल बिछा हुआ है. कानपुर, उन्नाव और आसपास के क्षेत्रों में भी अवैध शराब का धंधा चरम पर है. रायबरेली में 125 गांवों में इस धंधे को रोकने का प्रयास केवल कागजों तक सीमित है. हरदोई में शायद ही कोई गांव हो जहां कच्ची शराब बनाने का धंधा न फल-फूल रहा हो. कन्नौज के कई क्षेत्र में जाति विशेष की बस्ती में अवैध शराब का कारोबार होता है. फतेहपुर में अवैध शराब की पचासों भट्ठियां धधक रही हैं. इटावा व बांदा के अधिकांश क्षेत्रों में अवैध शराब बन रही है. महोबा और हमीरपुर में अवैध शराब का धंधा उद्योगधंधा बन चुका है. यहां धंधे में महिलाएं ज्यादा सक्रिय हैं. जालौन में बेहद अवैज्ञानिक ढ़ग से तैयार होने वाली दारू कभी भी जहरीली शराब कांड का कारण बन सकती है. पूर्वांचल के अधिकांश जनपदों आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र आदि जनपदों में भारी मात्रा में अवैध शराब का उत्पादन किया जाता है. इससे स्थानीय प्रशासन भलीभांति वाकिफ है फिर भी अवैध रूप से चलाए जा रहे इस धंधे में रसूखदार लोग भी हिस्सेदार हैं. यही वजह है कि इस गोरखधंधे पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता. पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूर-दूर के गांवों में भी शराब से जुड़ी समस्याएं किस कदर बढ़ गई हैं, उसका अहसास यहां के कई जिलों के गांवों का हाल देख कर पता चलता है. कहीं लोग जहरीली शराब से होने वाली मौतों की शिकायत करते हैं तो कहीं शराब-माफिया व पुलिस की मिलीभगत की और कहीं शराब फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण की. कुशीनगर जिले के कसया ब्लॉक में स्थित चकदैया गांव व पास के इलाके में जहरीली शराब पीने से कई मौतें हो चुकी हैं, कई परिवार उजड़ रहे हैं. लेकिन धंधा बदस्तूर जारी है. स्थानीय लोग कभी-कभार शराब की बिक्री का विरोध करने का साहस भी करते हैं लेकिन पुलिस व शराब माफिया की मिलीभगत के कारण बिक्री जारी रहती है. गोरखपुर जिले के खोराबार ब्लॉक के लक्ष्मपुर, झंगहा आदि गांवों में भी यही हाल है. लघु सीमांत कृषक मोर्चे से जुड़ी महिलाओं ने अवैध शराब का विरोध भी किया. कुछ समय के लिए शराब में कमी भी आई, लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस की मिलीभगत से फिर पहले जैसे ही हालात हो गए. गाजीपुर जिले के करंडा ब्लॉक में भी ग्रामीण महिलाओं की पहल पर शराब-विरोधी आंदोलन काफी चर्चा में रहा, लेकिन फिर बात वहीं की वहीं आ गई.

सबसे सनसनीखेज तथ्य तो यह है कि बिहार के सरहदी इलाकों से ऐसा रसायन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में आ रहा है जिसका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में धड़ल्ले से किया जा रहा है. कच्ची की मंडियों में खपाई जाने वाली यह शराब काफी कम दाम पर बेची जा रही है. जानकारों का कहना है कि एक लीटर रसायन में सौ लीटर शराब तैयार की जा सकती है. अब तक तो जनपद में ईंट-भट्ठों से लगायत क्षेत्रों में कच्ची शराब बनाई और बेची जाती रही है. लेकिन अब शराब कारोबारियों ने नायाब तरीका तलाश लिया है. बिहार से पगडंडियों के रास्ते ऐसा रसायन मंगाया जा रहा है जिसकी एक लीटर की मात्रा में पानी मिलाकर सौ लीटर शराब बनाई जा सकती है. इस शराब में पूंजी भी कम लग रही है. शराब बनाने में अगर पानी थोड़ा भी कम हो जाए तो पीने वालों की मौत हो सकती है. पुलिस को पैसा पहुंच जाता है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती. पूर्वांचल के बिहार सीमा से लगे बलिया, देवरिया, गाजीपुर जैसे जिलों में इस शराब का धंधा काफी तेजी फल-फूल रहा है. लोग बताते हैं कि शराब के कारोबारी बिहार से गैलन, टीन के जरिए दूध बेचने के बहाने रसायन लेकर इन जनपदों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं. देवरिया में इस समय बघौचघाट थाना क्षेत्र के बघौचघाट से बनकटा बाजार, पकहा, विशुनपुरा बाजार, धुसवां, करौंदी बैकुंठपुर, भटनी थाना के खोरीबारी से विजईपुर, बलुआ अफगान, भाटपाररानी थाना क्षेत्र के ग्राम घांटी भेंगारी होते हुए भोरे प्रतापुर, रामपुर बुजुर्ग, सलेमपुर के मझौलीराज, हथुआ मार्ग, मेहरौनाघाट का बार्डर शराब कारोबारियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है. रसायन वाली शराब बघौचघाट थाना क्षेत्र के मलवाबर मुसहर बस्ती, सुन्दरपुर, विशुनपुरा, मछैला ईंट-भट्ठों के बगल के घरों में तथा पथरदेवा के लमुआ स्थित शिव मंदिर के निकट धड़ल्ले से बिक रही है. इसी तरह तरलकुवा थाना क्षेत्र के सिधावें, हनुमानगंज, कंचनपुर गांव के मोड़, छोटी गंडक नदी के किनारे, कोन्हवलिया बाबू, भरत राय, विसवा, रामपुर के नौतन हथिया गढ़, हेत्तीमपुर, रामपुर के जंगल बेलवां, मझरटियां, बाजार, शामी पटटी सहित दर्जनों स्थानों पर रसायनिक शराब की बिक्री जोरों पर है. इसके अलावा सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कुर्नानाला स्थित दर्जनों गांव में शराब बेची जा रही है. यही हाल गौरीबाजार थाना क्षेत्र का भी है. सदर कोतवाली क्षेत्र के रामगुलाम टोला, डीएम आवास के पीछे, देवरिया खास, पुरवा चौराहा स्थित दो दर्जन से ऊपर स्थानों पर यह धंधा फल-फूल रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com